

वैचारिकी VAICHARIKI

खण्ड: 2 अंक: 1

जनवरी-जून 2023



Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration,
Nainital

वैचारिकी

VAICHARIKI

खण्ड : 2 अंक : 1

जनवरी-जून 2023

विशेषांक : सुशासन एवं नवाचार
आपदा प्रबन्धन



**Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration,
Nainital**

डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल

कापीराईट : डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल. 2023

खण्ड	:	2
अंक	:	1 जनवरी—जून 2023
संरक्षक	:	श्री बी० पी० पाण्डेय, आई.ए.एस. महानिदेशक,
संयोजक	:	श्री प्रकाश चन्द्र, पी०सी०एस० संयुक्त निदेशक (प्र०),
सम्पादक	:	डा० महेश कुमार, पी०डी०एस० संयुक्त निदेशक (व्य.वि.),
सह-सम्पादक	:	डा० दीपा मेहरा रावत सहायक निदेशक (व्य.वि.),
सहयोग	:	श्री वी.के.सिंह उप निदेशक (कम्प्यूटर) एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण एवं समन्वय प्रकोष्ठ, श्री मनोज पाण्डे, प्रभारी, शहरी विकास प्रकोष्ठ, सी०जी०जी०, श्री आनन्द कुमार, सह समन्वयक, प्रशिक्षण एवं समन्वय प्रकोष्ठ, सुश्री रागिनी तिवारी, कन्सलटेन्ट, की रिसोर्स सेन्टर, सी०जी०जी०, सुश्री प्रियंका त्यागी, शोध अधिकारी, आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ

वैचारिकी डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है।

वैचारिकी में लेख तथा समीक्षाओं आदि के विषय में पत्र व्यवहार सम्पादक, वैचारिकी, डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल-263001 से करें।

वार्षिक चन्दा रु० 1000.00 (संस्थाओं के लिए)

रु० 500.00 (व्यक्तिगत)

Disclaimer

अस्वीकरण

वैचारिकी में प्रकाशित लेख तथा उसमें प्रस्तुत विचार लेखक के निजी विचार हैं।
इससे डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल का कोई संबंध
नहीं है।

सम्पादक

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड शासन द्वारा 'डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल' को राज्य के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल एवं गुणवत्ता विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि, उत्तराखण्ड शासन की प्राथमिकताओं एवं जनसामान्य की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को कार्यक्षेत्र में दक्ष बनाने के उद्देश्य के साथ अकादमी में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों को तदनुसार निरन्तर बेहतर किए जाने के प्रयास अकादमी स्तर पर किये जा रहे हैं।

'वैचारिकी' पत्रिका डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल की मुख्य त्रैमासिक पत्रिका है। 'वैचारिकी' पत्रिका का खण्ड 2 अंक 1 जनवरी-जून 2023 आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह अंक 'सुशासन, नवाचार तथा आपदा प्रबंध' पर केन्द्रित विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक में सुशासन एवं नवाचार तथा आपदा प्रबंध पर कुछ महत्वपूर्ण लेखों का संकलन किया गया है। भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों तथा अकादमी द्वारा 'सुशासन एवं नवाचार' के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को भी लेखों में संकलित किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अंक सुधी पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस अंक के बारे में अपने सुझावों से अवश्य अवगत करायें। आपके सुझावों का स्वागत है।

बी. पी. पाण्डेय,

महानिदेशक

डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

विषय सूची

1. Effective redressal of public grievances 1-26
V. Srinivas, IAS, Secretary, Government of India, Department of Administrative Reforms & Public Grievance, New Delhi
2. Revitalizing Urban Development Cell: The transformative journey of revitalizing the cell's activities, establishing partnerships, and conducting capacity-building initiatives. 27-34
Manoj Pande, Consultant, Urban Development Cell, Centre for Good Governance, Nainital
3. Digital library-the new repository of knowledge 35-42
Anand Kumar, Librarian (Rtd.), Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital
4. Good Governance and Innovation: The Indian Perspective 43-57
Dr. Deepa Mehra Rawat, Assistant Director (B.S.) Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital and Aman Bora, Research Scholar, SSJ Campus, Kumaon University, Nainital
5. History and Landslides in Nainital during 19th Century 58-63
Dr. Ajay Singh Rawat, Retd. Professor, Department of History, Kumaon University, Nainital
6. Application of Geographic Information Science in Governance: With Special Reference to Disaster Management 64-84
J. S. Rawat, Former National Geospatial Chair Professor (under Geospatial Programme, DST Government of India) & Former Professor and Head, Department of Geography, Kumaon University, Nainital
7. Joshimath–Judicial Responses to the Eye Opener for Himalayan Development Model 85-89
Dr. Priya, A. Sondhi and Anoop Kumar
8. Child Centric Disaster Risk Reduction 90-94
Dr. Manju Pandey, Assistant Professor, Disaster Management Cell, Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital

9. Disasters as Dusk or Dawn for the Fairer Sex 95-99
Dr. Priyanka Tyagi, Research Officer, Disaster Management Cell, Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital
10. वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में अकादमी के प्रति योगदान व भविष्य की कार्य-योजना 100-118
प्रकाश चन्द्र, पी.सी.एस., संयुक्त निदेशक (प्रशासन) डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
11. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के फिट रहने से सुशासन को मिलेंगे नये आयाम 119-122
हेम चन्द्र, सहायक निदेशक (रेशम), उत्तराखण्ड सरकार।
12. प्रशासनिक गुरुकुल में तीन दशकीय सफरनामा 123-137
विवेक कुमार सिंह, उप निदेशक, डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
13. उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में एक दशक 138-141
दिनेश कुमार राणा, उप निदेशक (वित्त) डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
14. अभिनव व्यावसायिक यात्रा-डा0 आर0 एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, मई 2019 से फरवरी 2023 142-154
पूनम पाठक तत्कालीन उप निदेशक, डा0 आर0 एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, सम्प्रति- जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्यालय, निदेशालय, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
15. हिमालयी राज्यों में जेण्डर आधारित मुद्दे एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन 155-160
मीता उपाध्याय, कन्सलटेन्ट, सुधा संस्था, अल्मोड़ा।

EFFECTIVE REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES

V. Srinivas, IAS,
Secretary, Government of India,
Department of Administrative Reforms & Public Grievances, New Delhi

“Today, I would like to make a request to the bureaucracy of India, to every government employee, be it in the State government or the Central government. The country has put a lot of trust in you. Work while maintaining that trust. In your service, the basis of your decisions should be only the interest of the country”

-Prime Minister Modi.

Introduction

Prime Minister Modi has said “*Effective Redressal of Public Grievances*” is one of the most important aspects of Indian democracy, accorded highest priority to the subject with focus on citizen engagement. He has focused on improved categorization of grievances – grievances arising out of abuse of office and corruption, grievances arising from systemic deficiencies and grievances arising from poor service delivery, technology adoption in grievance redressal, monitoring and reviews and increased citizen engagement. The Prime Minister’s commitment to an effective grievance redressal mechanism emanated from his early years in Government as Chief Minister Gujarat when he launched the SWAGAT portal in 2003. The SWAGAT portal of Gujarat celebrated its 20th anniversary in 2023, was a pioneer in introducing citizen interaction, categorization of grievances and effective redressal of public grievances.

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances is the nodal agency in respect of policy initiatives on public grievance redressal mechanisms and citizen-centric initiatives. The role of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances is primarily to undertake citizen-centric initiatives in the fields of administrative reforms and public grievances to enable the Government machinery to deliver quality public service to citizens in a hassle-free manner and eliminate the cause of grievance. The grievances received by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances were forwarded to the concerned Ministries / Departments / State Governments / UTs who deal with the substantive functions linked with the grievance for redress under intimation to the complainant. Under CPGRAMS 7.0 grievances land directly at the last mile grievance officer level. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances has issued guidelines to all Ministries / Departments to set up effective grievance redressal systems for effective redressal of public grievances. There exist several digital portals in Government of India for effective redressal of public grievances – CPGRAMS, Rail Madad and e-Nivaran. All Ministries / Departments have designated nodal Grievance Redressal Officers for effective redressal of grievances.

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances has implemented 36 recommendations of the Parliamentary Standing Committee in the years 2021- 2023 for Effective Redressal of Public Grievances. Periodic reviews by the Hon'ble Prime Minister and Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions along with 9 meetings convened by the Parliamentary Standing Committee enabled ushering-in of transformational reforms in CPGRAMS as represented by the 10 Step reform program of CPGRAMS launched in 2022.

The implementation of CPGRAMS 10-Step reforms has resulted in a linear increase in the number of public grievances being redressed every month to over 1 lac

cases and reduction in timelines for disposal to 16 days in central ministries/ departments. Today the CPGRAMS portal has mapped 0.80 lac Grievance Redressal Officers, and 16 lac citizens have registered themselves to file nearly 20 lac grievances/ year. Considerable success was achieved in effective redressal of public grievances during the COVID-19 pandemic with launch of the COVID-19 Grievance Redressal Dashboard and portal on the CPGRAMS portal. This was a period in which 1.25 lac COVID-19 public grievances were redressed with an average disposal period of 1.45 days.

Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System (CPGRAMS)

Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) is an online platform available to the citizens 24x7 to lodge their grievances to the public authorities on any subject related to service delivery. It is a single portal connected to all the Ministries/Departments of Government of India and States. Every Ministry and States have role-based access to this system. CPGRAMS is also accessible to the citizens through stand-alone mobile application downloadable through Google Play store and mobile application integrated with

Guidelines Issued by DARPG

- i. Designate Grievance Redressal Officers up to last mile level wise.
- ii. Designate Grievance Appellate Officers one rank above Grievance Redressal Officers.
- iii. Grievance Redressal time limit of 30 days for both appeals and grievances
- iv. Monitoring of Grievances in Ministries/ Departments on a Monthly basis
- v. Effective Public Grievance Redressal part of Good Governance Week 2021 and 2022

UMANG. The citizen can access the system online through the portal www.pgportal.nic.in. The efficacy of the CPGRAMS portal has been an important thrust area of the Nation's Grievance Redressal Systems.

The status of the grievance filed in CPGRAMS can be tracked with the unique registration ID provided at the time of registration of the complainant. CPGRAMS also provides appeal facility to the citizens if they are not satisfied with the resolution by the Grievance Officer. After closure of grievance if the complainant is not satisfied with the resolution, he/she can provide feedback. If the rating is 'Poor' the option to file an appeal is enabled. The status of the Appeal can also be tracked by the petitioner with the grievance registration number. Since July 2022, DARPG has also reached out to the citizen filing a grievance through CPGRAMS by contacting him through an outbound call centre and soliciting his feedback on his closed grievance.

Grievance Redressal Machinery in the States

The State Governments have evolved advanced mechanisms for redressal of public grievances.

Digital platforms for effective grievance redressal in States

1. Gujrat - SWAGAT
2. Jammu & Kashmir – JKIGEAMS
3. Andhra Pradesh - SPANDANA
4. Telangana – PRAJAVAANI
5. Uttarakhand – CM Helpline
6. Uttar Pradesh – JANSUNWAI Portal
7. Kerala – CM's PG Redressal Cell
8. Rajasthan – Rajasthan Sampark
9. Maharashtra - Aaple Sarkar
10. Madhya Pradesh – CM Helpline
11. Odisha – e-Abhijoga
12. Bihar – Bihar Jan Shikayat Nivaran Pranali

Chief Ministers' designated officers have operationalized public grievances cells which receive complaints from citizens and forward those to the concerned departments and follows them up. Several Chief Ministers hold regular citizen interactions through physical meetings/ virtual meetings for hearing and redressal of public grievances. In several States, Senior Officers visited districts and villages as part of Good Governance Week celebrations in 2021 and 2022 when Nation-wide campaigns for Effective Redressal of Public Grievances were conducted. The impact of multiple grievance redressal platforms functioning in unison in the Good Governance Week from December 19-25, 2022 was quite significant – 315 lac service delivery applications being disposed and 6 lac Public Grievances being redressed. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances has collaborated closely with States in several initiatives for effective redressal of public grievances.

The areas of collaboration included:

- i. Institution of an award category for Improving Service Delivery and Redressal of Public Grievances under the Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020
- ii. National Workshop on Technology Platforms in Public Grievance Redressal on 18 February 2021 and the National Workshop on Sevottam in November 2022 and May 2023
- iii. One Nation – One Portal initiative by integration of CPGRAMS with State Grievance Portals and reverse integration.
- iv. Sevottam Capacity Building Programs for Grievance Redressal Officers.
- v. Publication of Monthly Reports from 2022
- vi. Collaboration with Government of Jammu & Kashmir for revamping the Awaaze-Awam portal and relaunch as JKIGRAMS.

Recommendations of the Parliamentary Standing Committee – 127th Report

The Parliamentary Standing Committee examined the subject of Effective Redressal of Public Grievances 9 times in the years 2021-2023. The 127th Report of the Parliamentary Standing Committee tabled in the House on 15 March 2023 contained the following key observations:

- i. The Committee appreciates the 10-step CPGRAMS reform process that was adopted by DARPG for improving quality of disposal and reducing the timeline. The Committee also commends the Department for faster disposal of grievances by the Department which is over one lakh per month. But the Committee is of the view that ‘quality of grievance redressal’ is more important rather than ‘quantity of grievance disposal’ and therefore recommends the Department to focus more on ‘redressal’ of grievances as compared to ‘disposal of grievances.’ (para 3.5)

127TH REPORT OF PSC

The Committee is pleased to note that the Department has implemented most of its recommendations

The Committee appreciates and commends the efforts of the Department for continuously improving and bringing about thoughtful changes in the grievance redressal system. (para 3.6)

- ii. The Committee is pleased to note that the Department has implemented most of its recommendations like ‘One Nation – One Portal’, CPGRAMS portal in all regional languages, to develop the Grievance Redressal Index, reduction in redressal period from 60 to 45 days and 45 to 30 days, introduction of appellate mechanism, revamping of Sevottam scheme, operationalizing of feedback mechanism and CPGRAMS dashboard. The Committee therefore appreciates and commends the efforts of the Department for

continuously improving and bringing about thoughtful changes in the grievances redressal system. (para 3.6)

- iii. The Committee observes that whereas the number of disposal of grievance redressal is quite high but the feedback taken for the redressal of grievances is not at par with the pace of grievance redressal. The Committee, therefore, recommends the Department to increase the number of seats in the Feedback call centre developed by the Department so that the number of feedbacks can be enhanced. The Committee also recommends the Department to develop a mechanism in which as soon as the Grievance is disposed a SMS message stating the details of disposals is received on the mobile of the complainant and where he/she can submit the feedback of the grievance redressal along with the option to appeal if he/she is not satisfied with the redressal of grievance. (para 3.8)
- iv. The Committee recommends identifying the ‘Scheme wise complaints’ by using the Data Strategy Unit which is functioning under the Department. (para 3.9)
- v. The Committee also recommends the Department to use Artificial Intelligence to develop a mechanism in which grievance can be lodged through voice recording which will help the people who are unable to file grievances using CPGRAMS portal. (para 3.10)

CPGRAMS – 10 STEP REFORMS

CPGRAMS Reforms –10 Step Reform

1. Universalization of CPGRAMS 7.0
2. Use of AI in CPGRAMS
3. CPGRAMS in all Regional Languages
4. Grievance Redressal Index
5. Feedback Call Centre
6. One Nation – One Portal
7. CPGRAMS in CSCs
8. Sevottam Capacity Building Programs
9. Monthly Progress Reports
10. Data Strategy Unit

- vi. The Committee has observed that the percentage of grievances redressed over the past 5 years for States is less compared to the percentage of grievances redressed over the past 5 years of Central Government. The Committee, therefore, urges the Department to take it up with the State Governments to enhance their grievance disposal rate so that Public Grievances are addressed effectively. (para 3.11)
- vii. The Committee appreciates the efforts of the Department in preparing the Grievance Redressal Index (GRI). The Committee urges the Department to continuously monitor and hold meetings with the Departments who are not performing well continuously and guide these Departments so that they can improve their rankings. (para 3.22).

CPGRAMS Reforms:

In pursuance of the decisions taken by the Prime Minister in the review meeting on 16 April 2022, CPGRAMS reforms were implemented by DARPG for improving quality of grievance disposal and reducing the disposal time. A comprehensive 10-Step CPGRAMS Reform program was adopted after several rounds of consultations with key stakeholders. DARPG established collaborations with Common Service Centre (CSCs), Indian Institute of Technology

Kanpur (IIT-K), National Institute of Smart Governance (NISG), National Institute of Design, Ahmedabad (NID), Quality Council of India, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Centre for Good Governance Hyderabad and Haryana Institute of Public Administration (HIPA) Gurgaon through MOUs and work orders.

The technology improvements in CPGRAMS are outlined as follows:

1. Universalization of CPGRAMS 7.0 - Auto-routing of grievances to the last mile

2. Technological Enhancements - Automatic flagging of urgent grievances leveraging AI/ML
3. Language Translation – CPGRAMS Portal in 22 scheduled languages along with English
4. Grievance Redressal Index - Ranking of Ministries / Departments on their Performance
5. Feedback Call Centre - 50-seater call centre to collect feedback directly from every citizen whose grievance is redressed.
6. One Nation One Portal - Integration of State Portal and other GoI portals with CPGRAMS
7. Inclusivity and Outreach - Empowering the remotest citizen to file grievance through CSC's
8. Training and Capacity Building - Conducted by ISTM and State ATIs under SEVOTTAM scheme for enabling effective grievance resolution.
9. Monitoring Progress - Monthly reports for both the Central Ministries/Departments and States/UTs
10. Data Strategy Unit - Established at DARPG for insightful data analytics

Two PMUs were established at DARPG – (a) PMU with QCI team for preparation of the CPGRAMS Monthly Reports for Central Ministries and States and (b) PMU with CGG Hyderabad team for preparation of Grievance Redressal Index in addition to the Data Strategy Unit with Data Analytics specialists in collaboration with National Institute of Smart Governance.

The Public Grievances Division of DARPG was strengthened with comprehensive redeployment and all vacant posts being filled up. DARPG

collaborated with 22 State Administrative Training Institutes for implementation of the Sevottam Program following extensive discussions with HIPA Gurgaon. After the Chintan Shivir of DARPG held on February 18th-19th, 2023 which was presided by the Hon'ble Prime Minister, DARPG has included 4 more steps in its reform agenda for CPGRAMS.

11. Citizen Connect
12. Strengthening existing citizen Grievance Redressal System
13. Improving the Quality of Disposal
14. Re-imagining Service Delivery

The processes for establishing greater citizen connect envisaged are improvements in call centre engagement with citizens, speech records being examined in senior level meetings, training programs for operators, sharing speech records of appeals filed through call centre with appellate officers, introduction of chat bot, introduction of outgoing call centre and addition of new call centre operators.

IMPACT OF THESE REFORMS:

This 10-Step CPGRAMS reforms process adoption has resulted in a remarkable decrease in the average time of disposals of Public Grievances. In 2023, 1.25 lac PG cases in January, 1.22 lac PG cases in February and 1.19 lakh PG cases in March, till 25th March 2023, were disposed by Ministries/Departments. March 2023 was the 8th time in a row since inception of CPGRAMS that PG case redressal has crossed 1 lac cases/ month. The disposal in State PG cases on CPGRAMS portal has crossed 50,000 cases/ month since September 2022.

Average disposal time of Central Ministries/Departments has improved from 32 days in 2021 to 27 days in 2022 to 16 days in 2023, till March, because of

these reforms. The progress for March, 2023 indicates 1,19,706 Grievances Redressed by Central Ministries/ Departments in March 2023, Average Disposal Time of 16 days/ grievance, Pendency level of 71743 cases in the Central Secretariat of Government of India.

The data relating to number of grievances redressed over the past five years is given as under

Total grievances redressed over the past five years:

Year	Number of grievances received during the year (N)	Total number of grievances redressed during the year		Percentage of grievances received and disposed during the year $G \times 100N$
		Grievances received and redressed during the year (G)	Grievances carried forward from previous years and redressed during the year	
2022	1918238	1642846	500622	85.64%
2021	2000590	1665050	470873	83.23%
2020	2271270	1889769	429800	83.20%
2019	1867758	1447377	192475	77.49%
2018	1586415	1248767	257638	78.72%

Grievances redressed over the past five years for Central Ministries / Departments

Year	Total Received in Year	Brought Forward	Disposed (Total during Year)	Disposal (From brought forward)	Percentage of grievances received and disposed during the year
2022	1254099	84097	1244648	66869	93.91%
2021	1362310	137745	1415958	119869	95.14%
2020	1606572	110468	1579295	80623	93.28%
2019	1253626	94303	1237461	69323	93.18%
2018	1118447	101834	1125978	82883	93.26%

Grievances redressed over the past five years for States

Year	Total Received in Year	Brought Forward	Disposed (Total during Year)	Disposal (From brought forward)	Percentage of grievances received and disposed during the year
2022	664139	803874	898820	433753	70.03%
2021	638280	885559	719965	351004	57.81%
2020	664698	961135	740274	349177	58.84%
2019	614132	749394	402391	123152	45.47%
2018	467968	661853	380427	174755	43.95%

One Nation – One Portal:

DARPG had undertaken One Nation - One Portal Digital platform across Government of India and State Governments for seamless digital processing of Grievances adopting a whole of Government approach. The integration/ reverse integration of State portals enables seamless transfer of public grievances from

CPGRAMS to State portals and from State portals to CPGRAMS. To expedite the integration process, monthly Meetings with all Nodal Officers were convened by DARPG with all States/UTs and all Central Ministries. These meetings helped expedite the process of integration of grievance portals of States with CPGRAMS portal. As of date, only 2 State portals remain to be integrated with CPGRAMS. The DARPG has once again reached out to States and Union Territories not linked with CPGRAMS to request them to link them at the earliest.

Central Ministries operationalizing large Grievance Portals – Rail Madad, Champions of MSME, Meri Sadak of MORTH, SCORES of SEBI have been integrated in the CPGRAMS.

CPGRAMS in Regional Languages:

Operationalization of CPGRAMS in all scheduled languages has been completed. CPGRAMS is available in English, Assamese, Bengal, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodo, Santhali, Maithili and Dogri.

Access to CPGRAMS at CSCs:

Citizens can file grievances on CPGRAMS at all Common Services Centers from July 2022 onwards. The initiative of Public Grievances being filed from Common Service Centres has been widely used by Citizens. 44.5 percent of grievances received by Department of Agriculture and Farmers Welfare are being filed through CSCs. The category ‘PM KISAN related issues’ has received the maximum number of grievances followed by ‘PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA related grievances’.

A comprehensive communication and outreach plan to further deepen the outreach has been prepared envisaging communication using community radio system, e- Vigyan, posters with QR code and other digital platforms.

Dedicated Feedback Call Centre of BSNL:

DARPG has operationalized the Feedback call centre through BSNL from 1 July 2022. Feedback for quality of disposal and citizen satisfaction is taken on every Grievance that is redressed on CPGRAMS. The Feedback Call Centre covers all Grievances received by Ministries/Departments and the States/UTs. Citizens who are not satisfied with the quality of grievance redressal have an option to file an appeal with the Nodal Appellate Authority through the call centre. 50 Language based seats are available in the call centre to get feedback in regional languages also as per convenience of citizens. DARPG has advised Nodal Grievance Officers of top grievance receiving ministries/ departments to visit the Feed Back Call Centre to oversee operations. Senior Officials of DARPG visit the Feedback Call Center on a monthly basis to oversee operations. The feedback call centre has successfully connected about 3,68,425 citizens by the end of March, 2023. More than 1,10,000 citizens have expressed satisfaction with the grievance resolution and have given a rating of Excellent/Very Good/Good. Apart from the same, 92 percent of citizens have rated the grievance filing process as very good or excellent. Increasing trends in call surveys are being observed with an increasing number of citizens participating in providing responses.

Universalization of CPGRAMS 7.0:

CPGRAMS 7.0 is a significant systemic upgradation with mapping last mile grievance officers and increase in the number of grievance categories. The objective was to reduce timelines of disposal, ensure enhanced monitoring of last mile officers, bring greater transparency into the CPGRAMS portal thereby improving quality of disposal. *The universal adoption of CPGRAMS 7.0 in all Ministries/ Departments has been completed over a 2-year period and represents a significant milestone.* Prior to CPGRAMS 7.0, public grievances moved from nodal officer of the Ministry to the

last mile grievance officer in a step-by-step manner taking considerable amount of time.

The upgradation of CPGRAMS 7.0 was taken up with significant revision in the number of grievance categories. The grievance categories were delineated by individual Departments/ Ministries and enlarged from the broad set of 20 categories to 1239 major categories and 18762 sub-categories.

The massive exercise of onboarding of all Ministries/Departments on CPGRAMS 7.0 was started with Department of Posts on 25.9.2019 and ended with Ministry of Shipping on 6.10.2022. 4 Ministries were onboarded in 2019, 5 Ministries were onboarded in 2020, 4 Ministries were onboarded in 2021, 77 Ministries were onboarded in 2022.

The PMOPG portal has been migrated to CPGRAMS from 18.2.2023 and the DPG Portal of the Cabinet Secretariat is in the advanced stage of being migrated to CPGRAMS 7.0.

The total number of GRO's in Centre + States has reached 0.80 lac. 0.46 lac grievance officers of central ministries/ departments have been mapped on the system along with 0.34 lac grievance officers from States/ UTs. The focus of the Sevottam Program is to ensure that each and every GRO is imparted capacity building programs for effective redressal of public grievances.

Communication Strategy for CPGRAMS

As part of the Government's 10-point CPGRAMS reforms in 2022, 19.18 lac grievances were received on CPGRAMS of which 85.64% have been disposed of. Average disposal time of Central Ministries/Departments was 27 days in 2022. All the 90 Central Ministries/Departments have been on-boarded on CPGRAMS 7.0 enabling auto-forwarding, faster transition and efficient redressal of grievance. Feedback Call Center on CPGRAMS has been established to collect feedback directly from the

citizens. Intelligent Grievance Management Dashboard leveraging AI/ML technology has been developed and a Data Strategy Unit was set up to create an analytical insight enabling strategic decision-making and policy reforms.

Communication strategy of CPGRAMS envisages publication of CPGRAMS monthly reports which are placed on the DARPG website (www.darpg.gov.in) and circulated to all Central Ministries/ Departments; States/ UT's. PIB Statements and Tweets, Infographics are issued to enhance citizen outreach. DARPG had organized Facebooklive interactions, and direct citizen interactions at Ministerial level to ensure citizen awareness.

CPGRAMS Monthly Reports have assisted Central Ministries/Departments and States/UTs in monitoring the individual progress. Further the reports have been useful in bringing about course corrections to improve quality of grievance redressal, reduce pendency and monitor officers with poor disposal rates. Hitherto, 12 Monthly Reports for the Central Ministries/Departments and 9 Monthly Reports for the States/UTs have been published.

Grievance Redressal Index (GRI) has been introduced and presented in Monthly Reports, instilling a competitive spirit amongst Ministries/Departments. CPGRAMS Flyers have been launched highlighting the scope and features of CPGRAMS 7.0.

The Data Strategy Unit has developed a tree dashboard which is used to monitor grievance officer wise pendency in Central Ministries/ Departments and in States/ UT's. Officers with high pendency have been presented in the reports so that they can reduce pendency levels.

Scheme wise monitoring of CPGRAMS public grievances has been a recent addition. Thus far public grievances received in 4 priority sector schemes, Pradhan Mantri Awas Yojana, Samagra Shiksha, Health & Wellness Centres, Har Ghar Jal

have been examined by the DSU in monthly reports. The scheme wise analysis of Swasthya Bharat indicates that half of the grievances are pertaining to Banking and Insurance related issues and remaining mostly pertained to States/ UTs.

The AI enabled grievance monitoring dashboards have been developed by IIT Kanpur which are used to identify spam, word search, repetitive grievances filed by habitual complainants.

The Monthly Progress Reports of CPGRAMS for Central Ministries/ Departments are circulated with DO letters from Secretary DARPG to all Secretaries of Government of India. The Monthly Progress Reports of CPGRAMS for States are circulated by DO letters from Secretary DARPG to Chief Secretaries of States/ UTs.

Progress review meetings by DARPG every month envisage 5 meetings (i) Monthly review meeting with Grievance Officers (ii) Monthly Review meeting with Appellate Officers (iii) Monthly Review meeting with Knowledge Partners (iv) Monthly review meeting with State Nodal Officers (v) Monthly review meeting with State ATIs. Further a monthly visit to the Feedback Call Centre by Nodal Officers of Ministries/ Departments is made to ensure systems operate at high efficiency levels.

Further Grievance Redressal and Improving Service Delivery have been part of the major campaigns conducted by DARPG in 2022. These are as follows:

1. Good Governance Week - 2022

A week-long Nation-wide campaign on “Prashashan Gaon ki Ore” aimed at redressal of public grievances and deliver services to the people at their door was organized during the Good Governance Week from 19-25 December 2022. About 54 lac public grievances and 315 lac applications for service delivery were disposed and 982 innovations in governance were documented during this one-week Campaign.

2. Special Campaign on Disposal of Pending Matters (SCDPM)

The Special Campaign 2.0 on Swachata and reducing pendency in Government offices was conducted successfully from 2nd - 31st October, 2022 in over 1 lakh offices under the Central Government across the remotest parts of the country and Indian Missions and Posts abroad. About 4.39 lakh public grievances were disposed during this campaign. CPGRAMS was integrated with Common Service Centres (CSC) from 7th June, 2022 to leverage its strength to take the facility of CPGRAMS to rural population. It is now available at more than 5 lakhs CSCs.

For designing of new Logo and name for CPGRAMS, DARPG engaged the National Institute of Design (NID) and MyGov. The names as suggested by NID and MyGov are under consideration.

Analytics by CPGRAMS Data Strategy Unit (DSU)

Department of Administrative Reforms and Public Grievances has set up a Data Strategy Unit w.e.f. from March, 2022. DSU has developed an analytical dashboard that may be used for strategic decision making and policy-reforms for seamless delivery of services to the citizens. The dashboard provides GROs data analysis, trend analysis, geographical analysis, root cause analysis for all the Central Ministries/Departments and States/UTs.

Data Strategy Unit

1. The Tree dashboard is being developed by the Data Science Unit (DSU) team of DARPG
2. The Tree dashboard project is expected to be completed by December 2023 and will be launched as a flagship initiative of DARPG to promote good governance and public service excellence.
3. The Tree dashboard will provide several benefits for the citizens and the government – transparency/ accountability/ monitoring/ evaluation/ accessibility etc.

Habitual Complainants:

DSU has identified habitual complainants who have filed thousands of grievances and appeals, thereby choking the system. These grievances create difficulties for the Grievance Redressal Officers in identifying genuine critical grievances. Mr. Anand Thakur has filed 37,315 grievances, the maximum by a single person, followed by Mr. Atin Maity at the 2nd position who has registered 16199 grievances from 1st January, 2022. While, Mr. Suneet Kapur has filed 7,401 appeals, followed by Mr. Jayesh Kulkarni who has filed 5,426 appeals. Following identification of habitual complainants, the number of complaints to be filed/ month on the CPGRAMS by an individual citizen has been limited to ten public grievances.

Grievance Redressal Officers with maximum pendency:

Smt. Rukmani Attri, Additional Director E-Services in Central Board of Direct Taxes (Income Tax) has the highest pendency of Public Grievances followed by ShriSuresnder Singh, Deputy Secretary, Department of Financial Services (Banking Division).

Some Other Analytics on CPGRAMS:

Implementation of CPGRAMS 7.0 has helped direct transition of grievances to the last mile officers and faster resolution of grievances. Over the last few years average disposal time has seen a declining trend. DARPG has accordingly reduced the disposal timeline from 60 days in 2020 to 45 in 2021 and 30 days in 2022. Information on number of grievances redressed on timelines are given in the table below:

GOI		States	
Closed within 45 Days	Pending more than 1 Year	Closed within 45 Days	Pending more than 1 Year
1282188	2045	337746	371494

Training of Grievance officers under Sevottam

Sevottam Scheme is a generic framework created by this Department in 2005 for quality based improvements in Public Service Delivery. It comprises of 3 modules – (i)Citizens’ Charter; (ii) Grievance Redress Mechanism; and (iii) Capability building for quality based and timely service delivery. Each of these modules has three criteria and 11 elements each i.e. 33 elements that cover all the critical aspects of an efficient Public Service Delivery System.

Under the Scheme, DARPG releases funds to State ATIs/CTIs for setting up of a Sevottam Training Cell in the ATI. The capability of the ATIs are built for becoming Consultants for implementation of Sevottam in various Departments/Public Organizations in the State/UTs and for becoming facilitator for the certification of the State Departments/Organizations under IS 15700:2005 given by BIS, New Delhi. Under the Scheme there is a provision for a lump-sum grant of up to Rs.20 lakhs for five years to each of the State ATIs/CTIs whose proposals are received in the Department.

The DARPG has collaborated with 22 State ATI’s in the years 2022 and 2023 to train 4000 Grievance Redressal Officers of the 34000 Grievance Redressal Officers currently mapped on the State Portals of CPGRAMS. The Sevottam policy envisages comprehensive coverage of all Grievance Redressal Officers in a time bound manner through State ATIs. The DARPG has collaborated with HIPA Gurgaon, and YASHDA Pune to conduct 2 National Workshops on Sevottam in the years 2022 and 2023 to ensure commonality in course content, teaching standards and timelines of implementation across States/ UT’s.

Grievance Redressal Index for all Ministries/Departments:

To assist the Ministries/Departments to review and streamline their Grievance Redressal System, and have a comparative assessment with other

Ministries/Departments, Grievance Redressal Index has been developed. The Index has two dimensions:

- Timely Disposal of Grievances
- Quality Disposal of Grievances

Ministries/Departments has been categorized into two groups, based on the number of grievances received, to enable a fair comparison; 1st Group (Group A) contains Ministries/Departments receiving higher number of grievances (i.e. greater than 500) while 2nd group (Group B) contains the ones receiving comparatively lesser number of grievances (i.e. less than 500)

Analysis of Monthly Grievance Redressal Index

- Unique Identification Authority of India has topped the GRI ranking for the month of March 2023
- In Group A, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has improved its ranking by 8 positions in March 2023 and currently ranked at 7th position. Central Board of Indirect Taxes and Customs has jumped to 15th rank from the previous month's rank of 21
- In Group B, Department of Pharmaceutical has jumped from rank 14 in February 2023, to 3rd rank in March 2023 and Department of Legal Affairs has jumped from 9th position in February 2023 to 4th position in March

Analysis Way Forward: Design & Development of Comprehensive GRAI

- The design and development of a Comprehensive Grievance Redressal Index is at advance stage,

- The Ministry/Department-level consultations are being held to finalize the dimensions and parameters and their respective weightages,
- This will refine the ranking process and make it more efficient by covering more parameters pertaining to performance of each Ministry/Department.

Best Practices in State Grievance Portals

1. SPANDANA (Andhra Pradesh)

The Government of Andhra Pradesh grievance redressal portal operationalized at www.spandana.ap.gov.in is one of the most comprehensive grievance redressal portals of India. The common platform through SPANDANA portal integrates all levels. The process flow of SPANDANA envisages grievances are received from multiple sources – on the portal, through toll free numbers, through petitions received through e-mails, and redressal through grievance cells in district, division and tehsil levels. Village level volunteers receive door step SPANDANA applications and deliver to the GRAMA SACHIVALAYAM for redressal. Mondays are designated as grievances day and the integration of all offices at District, Sub-Division & Mandal is through video conferencing on grievances day. A 14-digit unique ID is issued through the SPANDANA website. The citizen can track his grievance through the tracking ID provided in the acknowledgement slip. The Action Taken Report is uploaded on the portal and sent by SMS to the citizen. A dedicated toll-free call centre (18002331077) has been operationalized for feedback and 100 percent quality audit on redressal is undertaken. Reopening of grievance in case the citizen is not satisfied with the quality of disposal.

BEST PRACTICES

SPANDANA PORTAL
WWW.SPANDANA.AP.G

Grievances received through multiple sources – email/ portal/ callcentre Door Step Collection of grievances

Mondays – Grievances Day 14 Digit Unique ID, tracking of grievances Feedback call centre, 100 percent quality audit

2. SWAGAT (Gujarat)

The CMO Gujarat operates an ICT based program since April 2003 for effective, transparent and speedy redress of the grievances of the citizens at various levels of the government throughout the State including that at the highest levels by direct interaction with Hon'ble Chief Minister. The SWAGAT portal is a combination of digital and communication technology the form a program to resolve public grievances effectively. Under SWAGAT, citizens can register their grievances at village, taluka and district levels. Citizens can view the status of their application online, using their allotted password and login ID at any internet access point. The software application enables an online review of sub-district, district SWAGAT and State SWAGAT

outcomes and disposal of grievances is also monitored by the software. The citizen gets a chance of hearing at SDM and DM level and if not resolved at the Hon'ble CM level also. Cases for the attention of Chief Minister are selected as those that are long standing, acute humanitarian issues, difficult to resolve at other levels in Government and those that have policy implications. Applications are registered in 3 categories – (i) Policy Matters where a limitation or gap in the policy requires attention (ii) Long Pending grievances where the application has remained unresolved after initial application (iii) First time grievances which are sent to lower levels. There exist four levels of SWAGAT – on every 4th Thursday of the month the SWAGAT hearings are held in the State Capital Gandhinagar by Hon'ble Chief Minister of Gujarat through video conference The District SWAGAT is held in all 33 districts and the Sub-District SWAGAT and GRAM SWAGAT are also held as per

SWAGAT

Applications are registered in 3 categories

- (i) Policy Matters
- (ii) Long Pending grievances
- (iii) First time grievances

Four Levels of SWAGAT

- State level SWAGAT
- District SWAGAT
- Sub-District SWAGAT
- GRAM SWAGAT

prescribed schedules. The four levels are well integrated by software. SWAGAT has enhanced the accountability of Government, systemic changes as decisions lead to policy reform, high citizen's satisfaction, total transparency, and monitoring system as also awareness at highest levels of authority on public grievances. SWAGAT received the 2010 UN Public Service Award in improving transparency, accountability and responsiveness in Public Service.

3. JK-IGRAMS (Jammu & Kashmir)

JK-IGRAMS along with LG's monthly mulaqaat with citizens and review with officers provides institutional framework to citizens that is accessible to all in Jammu & Kashmir. The JK-IGRAMS portal is www.jkgrievance.in and key features include decentralization of grievance system by mapping sub-ordinate offices upto block level, setting up of 2 call centers in Jammu and Srinagar for registering grievances, Collectors made epi-center and all Districts/ Blocks linked to CPGRAMS, Grievance Analysis teams to study and share findings, with monthly mulaaquat with LG J&K. The impacts increased disposal from 41 percent to 74 percent in 4 month's time, in all categories. The dedicated call center provides a unique JKIGRAMS number which is forwarded to the grievance officer and online status is available to the citizen for effective follow-up. Various analytical reports and other MIS options on the portal assist administration in data filtering.

4. SAMADHAN (Uttar Pradesh)

SAMADHAN is an integrated web-based application system which brings all grievance redressal mechanism to one platform and enables instant and easy communication between Government and Citizens resulting in speedy redressal of their grievances from anywhere and anytime and It also provides facility for submission of grievances online by aggrieved citizen. The Grievance input mechanism has Janta Darshan by Hon'ble Chief Minister at State level, District Collector at District level and Tehsil level. The SAMADHAN portal integrates different channels and portals including the PG- Portal, Anti Bhu-Mafia Portal, Anti-

Corruption portal, CM Helpline etc. Citizen relationship management contains online registration and tracking of grievances, project management and monitoring, analytical reports, calls/ SMS/ e-mail, integrated & single platform, send reminders and giving feedback. Feedback is obtained through the CM Helpline call center and the complainant can also provide online feedback through portal. Negative feedback is reviewed by one level higher, through grading opinion, if senior officer finds disposal of the grievance insufficient / not satisfactory then he / she can revive the disposed complaint.

Future Roadmap of Effective Grievance Redressal :

The 127th Report of Parliamentary Committee envisages the following roadmap for Effective Grievance Redressal.

1. The Committee on a recent study visit to Imphal, Guwahati and Agartala identified '*Strengthening of Public Grievance Redressal System*' as one of the subjects for discussion with the officials of State Governments. The Committee observed that the system of grievance redressal in North-Eastern states is not very robust and needs considerable improvement. There is no separate State Grievance Portal in any of North-Eastern state except Meghalaya. The Committee, therefore, recommends the Department to aid these states to develop an efficient separate State Grievance portal and also link it with CPGRAMS portal for proper monitoring. The Committee also recommends the Department to formulate a policy focussing on North-Eastern states so that Public Grievance Redressal System in these States can be ameliorated.
2. The Committee appreciates the 10-step CPGRAMS reforms process that was adopted by DARPG for improving quality of disposal and reducing the time lines. The Committee also commends the Department for the faster rate of disposal of grievances by the Department which is over one lakh per month. But the Committee is of the view that 'Quality of Grievance Redressal' is more important rather than 'Quantity of Grievance Disposal' and therefore, recommends the

Department to focus more on 'Redressal' of grievances as compared to 'Disposal' of grievance.

3. The Committee observes that whereas the number of disposals of Grievance redressal is quite high but the feedback taken for the redressal of Grievance is not at par with the pace of grievance redressal. The Committee, therefore, recommends the Department to increase the number of seats in the Feedback call centre developed by the Department so that the number of feedbacks can be enhanced. The Committee also recommends the Department to develop a mechanism in which as soon as the Grievance is disposed a SMS stating the detail of disposal is received on the Mobile of the complainant and where he/she can submit the feedback of the Grievance Redressal along with the option to appeal if he/she is not satisfied with the redressal of grievance.
4. The Committee recommends identifying "Scheme-wise complaints" by using Data Strategy Unit (DSU) which is functioning under the Department.
5. The target for 2023-24 is to reduce pendency levels to 1 lac PG cases for States and 0.50 lac PG cases for Central Ministries. This will necessitate a disposal of 1.5 lac PG cases/ month from States and 1.25 lac PG cases/ month from Ministries/ Departments of GOI. Disposal currently stands at 0.5 lac PG cases/ month in States and 1.45 lac/ month in Ministries/ Departments. The number of cases being redressed/ month needs to be increased further. This can be achieved through effective implementation of SEVOTTAM, greater coordination amongst States/ UTs and Ministries/ Departments.

**REVITALIZING URBAN DEVELOPMENT CELL:
THE TRANSFORMATIVE JOURNEY OF
REVITALIZING THE CELL'S ACTIVITIES,
ESTABLISHING PARTNERSHIPS, AND CONDUCTING
CAPACITY-BUILDING INITIATIVES.**

Manoj Pande,
Consultant, Urban Development Cell,
Centre for Good Governance, Nainital

The year 2014 was a watershed year in urban development as it ushered in a paradigm shift in how urban issues and challenges were addressed. Mega missions like Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Pradhan Mantri Awas Yojana, National Urban Livelihood Mission, Swacch Bharat Mission, and Digital India Mission were launched. These missions had ambitious goals and targets for rejuvenating the Urban Landscape and improving the Quality of Life. Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration has a long history of actively participating in such missions and schemes through capacity building by its Urban Development Cell under the Centre of Good Governance, which was also a HUDCO Chair established in the year 1996. It had been a nodal agency for capacity building under JNNuRM, however, around this time the activities of the cell were at its lowest ebb. HUDCO-HSMI had hinted at closing the HUDCO Chairs and there were no relationships carved out with either the state or the centre for participating in the

Urban Rejuvenation Journey. Under this background, I was entrusted with the task of revitalizing the activities of the cell as In-Charge of the Urban Development Cell. With an MBA in HR, a postgraduate diploma in Urban Planning and Development, and a bachelor's degree from IIT Kharagpur, I had about 30 years of experience working in Central Public Sector Undertaking in senior positions.

2.0 Empanelment of the Urban Development Cell with MoHUA: Its Process and Significance

The Ministry of Urban Development was carrying capacity building for urban functionaries and representatives under its Capacity Building for Urban Development (CBUD) programme. The programme focussed on the capacity building of urban functionaries and elected representatives in flagship urban missions under MoHUA. However, for any training agency to conduct such training programmes it needs to be empanelled with the Ministry. The process of enquiry with the Ministry Officials regarding the process of empanelment was started by me and when the Expression of Interest was re-invited by the ministry in 2017, the cell participated and was successfully empanelled as a training entity for rolling out the training programmes. The Urban Development Cell then became a part of a select group of prestigious Institutes that were carrying out training programmes for Urban Functionaries sponsored by MoHUA. The academy started rolling out the training programmes in 2017 by first signing MoU with Uttarakhand State and then with Madhya Pradesh. Modules/ Process sheets were prepared by the cell for training on different urban missions viz. AMRUT, NULM and PMAY. As an in-charge urban cell, I also had an opportunity to participate in discussions with the Secretary of Urban Development to discuss the challenges in capacity building of Urban Functionaries. Later the CBUD programme got converted to Integrated Capacity Building Programme (ICBP) and the academy was also empanelled in the same. Apart from a low in activities around 2020-22 due to covid19, the cell has been continuously carrying out training

programmes under this framework and is in the process of renewing the MoU with the states for the present financial year.

3.0 Partnership with NIUA

3.1 Third-Party Evaluation Study

Under my leadership, the Cell participated in the third-party evaluation studies for the states/ UTs regarding the Implementation of Reforms under AMRUT in the Urban Local Bodies of India. The study was sponsored by MoHUA and NIUA was the nodal agency. I was entrusted with the task of carrying out the evaluation study in UP (Bareilly, Lakhimpur, Sitapur, Gonda, and Lucknow) and Punjab (Sahibjada Ajit Singh Nagar, Patiala, Malerkotla, Ludhiana, and Firozpur). The task was completed in a short period of one month and data was collected and compiled and presented in Excel sheets to NIUA. The relationship between NIUA and the Cell was further strengthened by my attending various seminars and consultative workshops conducted by NIUA.

3.2 Sanitation Capacity Building Platform

To address the problem of management of faecal sludge, National Faecal Sludge and Septage Management (FSSM) policy was released by the Ministry of Urban Development in 2017 and states were instructed to make this the priority area. The state of Uttarakhand also released its Septage Management Protocol. To align with the centre and state strategies it was decided to start conducting training on FSSM and Decentralized Sanitation Solutions under its DoPT-sponsored programmes in 2019. The faculties from NIUA and the training material by SCBP were utilized for the above training and the modules were designed by me and contextualized for Uttarakhand. Resource Persons were shared with the material to better equip them with the advances in FSS Management. Recognising the excellent work carried out

for the promotion of FSSM and carrying out capacity building activities in Uttarakhand, on 28 February 2019 in the workshop on "National Workshop on Non-Networked Sanitation Systems" held in Mussoorie, NIUA gave a "Champion in FSSM" shield to the In-Charge Urban Development Cell. From 2019 onwards continuous consultations were held with SCBP-NIUA officials as to how a collaborative arrangement can be made for rolling out training on FSSM for ULB and parastatal organisations functionaries. This led to a deeper understanding with NIUA for conducting training under SCBP and a formal MoU was signed with SCBP-NIUA in 2020. Fruitful results have been obtained through these arrangements and the cell has so far conducted orientation training for 256 Urban Functionaries for about 82 ULBs of Uttarakhand State. Besides these advanced training on co-treatment, design of FSTP, integrated wastewater & septage management, and the Role of SHGs in providing sanitation service delivery were also conducted.

During Covid-19

Besides the above, the cell was the first in the Academy to start an online training programme with the support of NIUA, and a training programme on "COVID-19 Preparation of PPE Procurement Budget and Resource Book on Advisories and Guidelines (NIUA)" was conducted in May 2020. Thereafter a similar training programme was conducted for Panchayati Raj Officials where the handbook was compiled and edited by me and was published by the Cell itself. The cell thereafter conducted online training programmes under its SCBP arrangements with NIUA.

3.3 Infant Toddler and Caregiving Neighbourhood (ITCN) Programme.

Children are a key indicator of well-being in a healthy society. A child-friendly city ensures an enabling built environment that is healthy and safe, develops their faculties, and fosters their love for community and for nature. Meetings were

held with NIUA wherein I participated in rolling out online training programmes under this vertical. RFP was floated by them, and the cell was successful in being selected as a training entity. An MoU was signed with NIUA under its ITCN programme in October 2021. This program is intended to improve the capacities of government officials in city planning for infants and their caregivers. All three stages, Orientation, operational, and implementation modules have been completed under this programme.

3.4 Urban River Management Programme (URMP) of NIUA

As an in-charge UDC, I participated in the consultative workshops on URMP and later ToT on creating Urban River Management Plans. These discussions have led to NIUA and National Mission for Clean Ganga (NMCG) sponsoring training programmes for ULB and parastatal organisations officials of Uttarakhand. Further discussions are going on with the URMP vertical and NMCG as to how DRSTUAoA can and NMCG/NIUA can mutually cooperate to deliver training and create Urban River Management Plans for the cities of Uttarakhand.

4.0 Water, Sanitation and Health Institute (WASHi)

To further augment the capacities of the Urban Development Cell in the field of water and sanitation it was felt that the cell must form partnerships with other institutes working in the field. Discussions were held by me with the officials of WASHi to upgrade the Urban Development Cell capacities to deliver water and sanitation-related training MoU was signed in August 2022 wherein WASHi accepted to provide pro-bono services to the academy. Under these arrangements, faculty support has been provided by the UDC in programmes rolled under ICBP, DoPT, State, and SIUD. Handholding of the ULB and parastatal organisation were done in preparing City Wise Sanitation Action Plan (CSAP) for 22 ULBs. Discussions are on with the institute for carrying out hill-specific training and research work,

handholding of ULBs, and creating a chair at the academy for the next phase of the agreement with the Institute.

5.0 State Institute of Urban Development

Based on the recommendation of the fifth finance commission a State Institute of Urban Development (SIUD) was envisaged to be established at Dr R S Tolia Uttarakhand Academy of Administration. It was requested that the academy send a proposal to the Urban Directorate for their approval which was prepared by me and sent to the Urban Directorate on 18th April 2022. A detailed work plan proposal was then requested for the activities to be conducted by SIUD which was prepared and sent for the final approval. The work plan was approved by the state government and a sum of 1.25 crore has been transferred to the Academy for the establishment of the Institute in precincts of Dr R S Tolia Uttarakhand Academy of Administration. Preparation of the Memorandum of Association and the Articles of Association is in progress. The activities approved under the plan are presently being carried out.

6.0 Flagship Training Programme under Various Ministries and Urban Directorate, Uttarakhand.

Regular proposals for conducting refresher training programmes for senior-level officers are being prepared by me and sent to various ministries for approval. Under my leadership, the Cell has been carrying out training programmes for senior-level officers of Indian Forest Officers since 2017 sponsored by MoEF & CC. Proposals have also been accepted by DoPT for conducting In-Service training for senior officers of All India Services. A "Conclave on Urbanisation and Development in Fragile Mountain Ecosystems" was also conducted by the cell, which was sponsored by the Urban Directorate, Dehradun, and supported by the High-Power Committee on Urban Planning (MoHUA) and the World Bank.

7.0 As In-Charge Key Resource Centre

The training programme for Level 1 Officers working in the Jal Jeevan Mission pre-2022 was being conducted by the Urban Cell while from 2022 onwards I was given the responsibility of In-Charge of the Key Resource Centre and all the activities of the cell like preparation of action plan, preparation of modules, conduction of training and submission of required documents were overseen by me.

8.0 Contributions as a Course Director and Resource Person

As a Course Director, to date, over 80 training on various thematic areas of Urban Development have been conducted by me wherein over 2500 trainees from the Urban Local Bodies and Parastatal Organisations from Uttarakhand and other states have been trained. Modules and process sheets have been prepared by me for different thematic areas such as Women Empowerment and Participation in Urban Development, Leadership in Sustainable Development, Storm Water Management in Urban Areas, Decentralized Sanitation Solutions for Urban Areas of Hilly Regions, Child-Friendly Cities Integrated Water Resource Development & Management with a Special Focus on Hilly Town, Urban Mobility Planning and Management in Hill Areas Creating Sustainable Cities & Communities with a Special Focus on Hilly Areas, The Role of PPP in Affordable Housing Issues Challenges and Way Forward, The Role of Community Participation in Sustainable Solid Waste Management, New Initiatives in Urban Financing Credit, Rating, Municipal Bonds & Value Capture Financing, Urban Agenda 2030 & Sustainable Development Goals, etc. Modules prepared by NIUA have been contextualized for Uttarakhand. As a resource person, I have participated in professional, foundation, and induction courses and short-duration thematic courses run by UDC, KRC, DMC, Gender Cell, and e-governance. Sessions on various topics viz. urban development, water and sanitation, stakeholders' participation, leadership, good governance, ethics and values, TQM, etc. are regularly taken by me.

9.0 Its Work in Progress

As new issues and challenges unfold in Urban Development and Management and new solutions emerge it is important that the cell and SIUD keep abreast with present times. It is crucial to forge relationships with eminent institutions working in the field of Urban Development for effective outcomes in capacity building as well in the field of research. Working relationships have already been established with NIUA, WASHi and UMC Ahmedabad and talks are in progress with institutes like SPA Delhi, CEPT Ahmedabad, RCUES Lucknow. Discussions are being carried out with World Bank and UNDP for collaboration. The process of registration of SIUD is in progress. Talks are on with the Urban Directorate for finalizing the Plan of Action for capacity building for the year. The possibility of setting up a special cell focussing on sanitation challenges is being deliberated both with NIUA and WASHi. Training programmes with the support of UNDP are being conducted. EoI for Swachhta Knowledge Partners has been submitted with SBM, MoHUA and empanelment process is going on.

From August 2016 onwards, the month I took the responsibility of Urban Development Cell, the cell has marched steadily towards its objective of becoming an apex training Institute on Urban Development in Uttarakhand and as a Centre of Excellence, capable of providing solutions to Urban Issues in Hilly Areas.

It would be apt, to sum up, the review with a quote from Robert Frost's poem "Stopping by the Woods on Snowy Evening".

*The woods are lovely dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.*

DIGITAL LIBRARY - THE NEW REPOSITORY OF KNOWLEDGE

Anand Kumar, Librarian (Rtd.),
Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital

Introduction

A digital library is a new concept. The term digital library explains the nature of its collection. A digital library is understood to have the information stored predominantly in electronic or digital medium, this includes digital books, scanned image, graphics, textual and numeric data, digitized films, audio-video clips etc.

A digital library is a library which has all the information in electronic form and having electronic device to have access to the digitized information. Thus, the digital library is a library which has number of machine-readable publications and facilities for remote access to several database. The American Digital Library Federation has defined the digital library as “Digital libraries are organisation that provide the resources, including the specialized staff to select, structure, offer intellectual access to, interrupt, distribute, preserve the integrity of and ensure the persistence overtime of collection of digital works so that they are readily and economically available for use by defined community or set of communities”.

Digital libraries mean the creation and preservation of electronic books and holdings of other kinds of materials, without the need for end users to purchase the materials they want to consult and read. A digital library is a collection of digital

materials, such as electronic books (e-books), scholarly articles, research papers, multimedia content, and other digital resources, that are organized, accessible, and searchable through computer systems or online platforms.

Benefits of a digital library:

1. **Content Accessibility:** A digital library provides convenient and widespread access to a vast array of resources. Users can access materials from anywhere, anytime, if they have an internet connection.
2. **Search and Discovery:** Digital libraries often include robust search functionalities, enabling users to find specific resources quickly. They can search by keywords, titles, authors, or other criteria, making it easier to locate relevant materials.
3. **Space Efficiency:** Unlike a physical library that require space for storing books and other materials, digital libraries are not limited by physical constraints. They can store a large volume of resources without requiring physical space.
4. **Preservation and Longevity:** Digital materials can be preserved for a longer time compared to traditional print resources, which may deteriorate over time. Digital library can implement strategies for long-term preservation and ensure that valuable resources remain accessible for future generations.
5. **Remote Learning and Research:** Digital libraries play a crucial role in remote learning and research. Students, researchers, and scholars can access academic papers, journals, reference materials, and other educational resources remotely, without the need to visit a physical library.

6. **Multimedia Integration:** Digital library can incorporate various multimedia formats, such as videos, audio files, and interactive content, enriching the learning experience and catering to different learning preferences.
7. **Collaboration and Sharing:** Digital library often provide features that enable users to collaborate, share resources, and engage in discussions with other users. This fosters a sense of community and allows for knowledge exchange.
8. **Cost Savings:** Building and maintaining a digital library can be cost-effective in the long run. While there may be initial costs associated with setting up the infrastructure and acquiring digital resources, the absence of physical space and the ability to distribute resources electronically can lead to cost savings over time.
9. **Customization and Personalization:** Digital library can offer customization options for users, such as personalized reading lists, bookmarking features, and recommendations based on users' interests and previous interactions. This enhances the user experience and promotes engagement.
10. **Environmental Sustainability:** By reducing the need for physical materials and transportation, digital library contributes to environmental sustainability efforts.

Merits of Digital Library:

1. **Accessibility:** Digital library provide easy and convenient access to a vast amount of information from anywhere, at any time, if there is an internet connection. Users can access resources using various devices such as computers, laptops, tablets, or smartphones.

2. **No Physical Boundaries:** The users of digital library need not go to the library physically; people from all over the world can gain access to the same information, if an internet connection is available.
3. **Extensive Information:** Digital libraries have the potential to store and provide access to a wide range of resources, including books, journals, articles, research papers, multimedia content, and historical documents. They offer a wealth of information in diverse subjects and disciplines.
4. **Searchability and Indexing:** Digital libraries often have robust search features that enable users to quickly find specific information within the vast collection of resources. Advanced search options, filters, and metadata tagging systems enhance the efficiency and accuracy of searches.
5. **Preservation and Conservation:** Digital libraries contribute to the preservation and conservation of valuable resources. Fragile or rare materials can be digitized and stored, reducing the risk of physical damage or loss due to deterioration, accidents, or natural disasters.
6. **Cost-Effective:** Digital libraries eliminate the need for physical infrastructure and maintenance costs associated with traditional library. They require less physical space, no printing costs, and can accommodate many users simultaneously, making them more cost-effective in the long run.
7. **Round the clock Availability:** A major advantage of digital library is that the people can gain access round the clock to the information.
8. **Space:** Traditional libraries are limited by storage space, digital libraries have potential to store much more information, because digital information requires very little physical space to contain them, and media storage technologies are more affordable the ever before.

Demerits of a Digital Library:

1. **Access Barriers:** Despite the widespread availability of internet access, there are still regions or individuals who may face limitations due to unreliable connectivity or lack of access to necessary technology. This digital divide can exclude certain populations from benefiting fully from digital library resources.
2. **Technological Dependency:** Digital library heavily rely on technology, and any technical issues, such as server failures or network outages, can disrupt access to resources. Users may also face compatibility issues with different devices or software versions.
3. **Copyright and Licensing Restrictions:** Digital library must navigate copyright and licensing agreements to provide access to copyrighted materials. This can result in restrictions on the availability and use of certain resources, limiting their usefulness.
4. **Quality and Reliability:** The quality and reliability of digital resources can vary. There is a risk of encountering inaccurate or outdated information, especially in user-generated content or unverified sources. Users need to critically evaluate the credibility and trustworthiness of digital resources.
5. **Digital Preservation Challenges:** While digital library contributes to preservation, they also face challenges regarding the long-term accessibility and preservation of digital materials. Technological obsolescence, file format changes, and data loss over time can pose risks to the longevity of digital collections.

Suggestions to Improve Digital Libraries:

1. **Evaluate and categorize content:** Assess the current state of your digital library and determine if there are any areas for improvement. Categorize your content based on relevant topics, genres, or other criteria to make it easier for users to find what they're looking for.
2. **Implement a robust metadata system:** Metadata provides descriptive information about your digital content, making it easier to search and discover. Develop a standardized metadata system that includes relevant details such as titles, authors, subjects, keywords, and publication dates. Consistency in metadata will enhance searchability and organization.
3. **Optimize search functionality:** Implement an advanced search feature that allows users to search your digital library by various parameters, including keywords, author names, publication dates, or any other relevant criteria. Consider using filters and advanced search operators to refine search results further.
4. **Ensure content quality and accuracy:** Regularly review and update your digital library to ensure the content remains relevant, accurate, and up to date. Remove any outdated or erroneous materials to maintain a high level of quality and reliability.
5. **Integrate user feedback:** Collect feedback from users regarding their experiences with the digital library. Incorporate their suggestions and address any concerns to enhance the user experience.
6. **Enhance accessibility:** Make sure your digital library is accessible to a wide range of users. Consider implementing features such as screen reader compatibility, text resizing options, and alternative text descriptions for

images. Ensure your library is responsive and works well on different devices and screen sizes.

7. **Implement social features:** Consider adding social features to your digital library, such as user reviews, ratings, comments, or the ability to create personalized reading lists. This can encourage user engagement and provide valuable insights to other users.
8. **Promote collaboration and community:** Foster a sense of community among your library users by creating discussion forums or online groups where they can interact, share recommendations, and exchange ideas.
9. **Explore multimedia options:** Expand your digital library beyond traditional text-based materials. Consider adding multimedia content such as videos, podcasts, or interactive elements to provide a more diverse and engaging experience for your users.
10. **Up to date with technology:** Regularly assess emerging technologies and trends in the digital library field. Explore new tools, platforms, or formats that can enhance the functionality and user experience of your library.

Important Digital Libraries in India:

1. National Digital Library of India (NDLI)
2. Universal Digital Library
3. Directory of Open Access Books (DOAB)
4. Internet Archive
5. British Council Online Library
6. Delhi University Library System (DULS)

Conclusion:

Digital libraries provide users with quick access to resources, with powerful search tools that enable users to find the information quickly and easily they need. This quick access saves users time and effort, making it easier for them to conduct research or study efficiently. Digital library has numerous advantages in terms of accessibility, information availability, and preservation. However, they also come with certain drawbacks related to access barriers, technology dependence, copyright limitations, and quality concerns. Efforts are continuously being made to address these challenges and improve the effectiveness of digital library. Improving digital library can be a great way to enhance organization, accessibility, and overall user experience.

References

1. Kumar, P.S.G. A student manual of Library and Information Science, 2nd ed. 2012, pp 953-960
2. Information technology: Application, LPU Distance Education Booklet, 2012, pp 103-110

GOOD GOVERNANCE AND INNOVATION: THE INDIAN PERSPECTIVE

Dr. Deepa Mehra Rawat, Assistant Director (B.S.)
Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital
and Aman Bora, Research Scholar,
SSJ Campus, Kumaon University, Nainital

INTRODUCTION

The concept of Good Governance is not something new to the Indian civilization, it has been deep-rooted with the idea of '*Raj Dharma*', which meant that those who work in governance must uphold morality and treat everyone equitably and with which the rulers were bounded even in a monarchy. The Jataka stories, the Shanti Parva Anushasanparva of Mahabharat, Shukracharya's Nitisar, Panini's Ashtadhyayi, Aitareya Brahmana, Valmiki's Ramayana, and notably Kautilya's Arthashastra include this depiction of good governance.ⁱ Kautilya's Arthashastra has given immense power to the king but at the same time states: "*In the happiness of his people lies king's happiness, in their welfare his welfare, whatever pleases himself he shall not consider as good, but whatever pleases his people he shall consider as good.*"ⁱⁱ

In the present context, the word good governance became a buzzword in the 1990s with the World Bank (WB) defining it and declaring it essential for a nation's overall development. WB defined governance in a document entitled 'Governance and Development' (1992) as "*the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development.*"ⁱⁱⁱ With

the experiences of the World Bank in developing countries, the bank believed that a robust and fair development environment must be established and maintained and good governance is a crucial component of effective economic policies.^{iv} Regarding good governance, the Bank also stated that predictable, open, and enlightened policymaking (transparent processes) is a hallmark of good governance. It also includes a bureaucracy with a professional ethos, an executive branch of government that is held accountable for its actions, a robust civil society that engages in public affairs, and all of these things acting in accordance with the law.^v To summarize, effective administration within a democratic framework that is open, responsible, focused on the needs of the people, participative, and transparent is a key component of good governance.

The Indian Constitution is not explicitly referring to the idea of good governance, but it does contain multiple provisions and values that are consistent with the term. The provisions for Fundamental Rights in Part III, Directive Principles of State Policy in Part IV, Fundamental Duties in Part IV A, System for checks and balances and Independent Judiciary under Article 50, Rule of Law under Article 13 etc. of the Indian constitution^{vi} contribute to the idea of good governance.

INNOVATION AND GOVERNANCE

In comparison to the world before the Information and Communication Technology (ICT) age, governance has reached a new level with the growth of science and technology. The adoption of technology is crucial in the governance process as technology encourages participatory government by empowering citizens, streamlining administrative procedures, increasing transparency, and enabling data-driven decision-making. Governments may increase public administration's efficiency, effectiveness, and accountability by making efficient use of technology. This will improve governance and eventually result in the welfare of the people.

With ICT, came the concept of Electronic Governance or '*e-governance*'. The use of modern ICT by governments for the complete spectrum of government duties is the emphasis of the term e-governance. Consequently, e-governance is the use of information and communication technology to deliver government services, information exchange, communication, transaction, integration, various stand-alone systems and services between government and citizens, government and business, as well as back-office process and interaction within the overall framework of government.

Sharon S. Dawes defined e-governance as: "*E-governance comprises the use of information and communication technologies (ICTs) to support public services, government administration, democratic processes, and relationships among citizens, civil society, the private sector, and the state.*"^{vii} According to the Council of Europe: "*E-governance is about the use of information technology to raise the quality of the services governments deliver to citizens and businesses. It is hoped that it will also reinforce the connection between public officials and communities thereby leading to a stronger, more accountable and inclusive democracy.*"^{viii}

INDIA AND INITIATIVE FOR E-GOVERNANCE

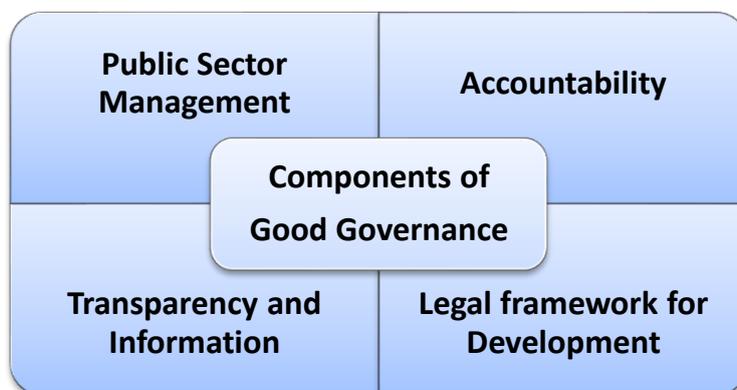
Notable initiatives for the transformation towards e-governance started in the 1990s by the Government of India (GOI).^{ix} Since then, the nation has achieved significant strides in the field of information and communication technology. The major step taken by GOI in this regard was the approval of the National e-Governance Plan (NeGP) on May 18, 2006, comprising 27 Mission Mode Projects (MMP), now 31 and 8 components. According to GOI, the NeGP was conceptualized with the vision: "*Make all Government services accessible to the common man in his locality, through common service delivery outlets and ensure efficiency, transparency and reliability of such services at affordable costs to realize the basic needs of the common man*".^x The Department of Administrative Reforms and Public Grievances

(DAR&PG) and the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) together developed the NeGP, which has been instrumental in identifying and prioritizing e-governance initiatives around the nation.^{xi}

To improve e-Government holistically, several legislative initiatives and projects have been initiated to build core and support the infrastructure. State Data Centers (SDCs), State e-Government Service Delivery Gateway (SSDG), State Wide Area Networks (SWAN), Common Services Centers (CSCs), the National e-Government Service Delivery Gateway (NSDG), and Mobile e-Government Service Delivery Gateway (MSDG) etc. are the main elements of the core infrastructure. Core policies and guidelines on security, human resources, citizen engagement, social media, as well as standards relating to metadata, interoperability, enterprise architecture, information security, etc., are among the significant support elements.

The need for a more holistic approach toward e-governance could be understood by the very fact that from slightly under 4% in 2007, India's internet penetration rate increased to around 48.7% by 2022.^{xii} This placed the nation second globally in terms of the number of active Internet users.

The last decade has been tremendous for India with regard to the digitization of government services. India has taken numerous steps for the digitalization of the governance process in recent years and these steps can be seen fulfilling the four components of good governance stated by the World Bank^{xiii} that are:



1. PUBLIC SECTOR MANAGEMENT

India has made great progress towards solid public sector administration through e-governance efforts. The public sector comprises the economy that is owned and controlled by the state. One of the major steps by GOI was the National Portal of India in November 2005, the portal's goal is to give people and other stakeholders access through a single window to the data and services offered by the Indian government.^{xiv} Unique identification numbers (Aadhar) issued by the Unique Identification Authority of India, established in 2009, acts as a platform for digital identification and make it possible to offer services effectively and transparently. The Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity acted as a link between government finances, mobile phones, and Aadhaar cards, allowing for the transmission of subsidies and the abolition of middlemen to avoid leakages. This made it possible for banking correspondents to reach out to the rural community and facilitate financial transactions.^{xv}

At the very start of 2013, GOI launched the Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme for reforming the government delivery system. Over 450 schemes totaling over 900 million individuals have been delivered through DBT. Nearly 65% of the welfare and subsidy expenditure has been paid directly into claimants' accounts by the government since 2016.^{xvi} Major schemes under

the DBT initiative are the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, Janani Suraksha Yojana, Rajiv Gandhi National Fellowship, PAHAL, Dhanalakshmi Scheme and Maulana Azad National Fellowship. As of June 2023, the total direct benefit transfer was ₹ 29,84,412 Cr.^{xvii} The Goods and Services Tax Network (GSTN) has improved tax collection efficiency while also offering a stage for innovation. GSTN has increased transparency, decreased local corruption, and unified the government's capacity to collect taxes from the states. The monthly GST collections ranged from ₹85K to ₹95K crore when the GST was first implemented in 2017, but they have since surged to about ₹1.5 lakh crore and are still increasing. The total collection reached an all-time highest in April 2023 with ₹1.87 lakh crore.^{xviii} Because of the government's collective efforts and those of other stakeholders, the value of digital payment transactions (consisting of Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface (BHIM-UPI), Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Toll Collection (NETC) and others) has greatly expanded, which can be seen from Table 1 below:

Financial Year (FY)	Total value of digital transactions (In lakh crores)
2017-18	1,962
2018-19	2,482
2019-20	2,953
2020-21	3,000
2021-22	3,021

Table 1: The total value of digital payments from FY 2017-18 to FY 2021-22
(Source: pib.gov.in)^{xix}

2. ACCOUNTABILITY

The World Bank has described Accountability as '*the heart of good governance*'. Accountability means '*holding public officials responsible for their actions.*' Political leaders must be held accountable for the activities of their governments because they are ultimately answerable to the people they represent.^{xx} By encouraging transparency, enabling digital payments and financial tracking, establishing online grievance redressal mechanisms, putting in place digital identity systems, utilizing data analytics for monitoring and auditing, and protecting whistleblowers, e-governance in India has strengthened accountability. The public sector now has a culture of accountability and honesty owing to these measures. An online platform Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) created in 2007 is available to lodge grievances to the public authorities on any issue related to service delivery 24x7 to the citizens. It connects all of the Ministries/Departments of the Government of India and the States through a single platform.

Another major step in this direction was the launch of PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) in 2015, which is a multi-purpose and multi-modal intended at resolving the problems of the common man while also monitor and assess significant initiatives and programs of the Government of India and projects suggested by State Governments. Prime Minister Shri Narendra Modi quoted the platform for efficient and responsive governance.^{xxi} Citizens may now be authenticated and verified through Aadhaar, making it more challenging for anyone to commit fraud or abuse government resources. This improves accountability across a range of sectors, including public distribution networks, financial services, and social assistance programs.

Platforms like the Public Financial Management System (PFMS) and the GSTN have expedited financial transactions, limiting the opportunity for corruption and fostering accountability in tax collection and spending management. Digital transactions create an audit trail, which makes it simpler to keep track of financial activity and spot any irregularities. A study found that e-governance has reduced corruption, especially in developing countries like India and assisted the governments in building a good relationship with the citizens and reducing corruption.^{xxii}

Decentralization of power is also an important part of good governance and the Panchayati Raj system is an Indian step toward the same. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has introduced eGramSwaraj, launched on April 24th, 2020 on the occasion of National Panchayati Raj Day; it is a user-friendly portal/application to improve e-Governance in Panchayati Raj Institutions (PRIs) across the nation with the objectives of better openness in decentralized planning, progress reporting and task-based accounting.

3. TRANSPARENCY AND INFORMATION

When the concept of transparency and information comes into the Indian context of governance, the Right to Information (RTI) Act, 2005 is a milestone in the operationalization concept of good governance. According to Rajbir S. Dalal, *“In India, RTI Act, 2005 and the concept of good governance are supplementary to each other.”* He stated the Act to be the most revolutionary act passed by the Indian parliament since independence and that it restored the *status of master to the masters (Public)*.^{xxiii} This Act made the bureaucracy concerned and pushed them to provide transparency, accountability and responsiveness in their daily operations. The RTI Act, 2005 gave citizens one more potent weapon and required the Public Information Officer to give the information seeker their requested information in a timely

manner. A digital portal ‘rtionline.gov.in’ has been set up for quick redressals. According to the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions over 1.59 lakh online RTIs were filed between April 22, 2013, and November 12, 2021.^{xxiv}

Nowadays, government agencies provide information and transactional services via their websites on the Internet. These websites serve as the main interface for the public and have become the primary touch point. The use of social media by the government to provide information, gather public opinion, and interact with individuals is on the rise. Citizens may contact directly with government representatives, report concerns, and get updates through websites like MyGov and government officials’ Twitter accounts. Under Pillar 6: ‘Information for All’ of Digital India Mission (2015), the government has worked towards hosting all the information and documents online so that citizens can have easy access to them.

Education is another such sector where there has been a great impact of the digitalization of resources. E-learning and other related tools provide a platform for improved learning, cost-effective distribution, the flexibility of learning at the learner's convenience, consistent quality content delivery, re-usability of the content, etc. GOI launched DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) in 2017 to provide curriculum-based learning materials in more than 18 languages to students, instructors as well as parents. PM e-VIDYA was launched in 2020 through which the top 100 institutions provided online courses to give 3.7 crore students in higher education better learning possibilities and to boost e-learning by liberalizing the regulations governing open, distance and online education.^{xxv} Launched in 2017, the Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) site offers Massive Open Online Courses (MOOCs). NIOS (National Institute of Open Schooling) and NCERT are running a variety of online courses pertaining to school

education on the SWAYAM platform, respectively. These courses are being taken by approximately 1.5 crore students.^{xxvi} E-Pathshala (2015) to create a resource hub for instructional flipbooks, audiobooks, films, etc.; SWAYAM PRABHA in 2017, a group of DTH channels that telecast educational content 24x7; the second phase of the National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement (NISHTHA) program was put into effect in the financial year 2021 through which approximately 6 million teachers got training are some of the major steps taken by GOI towards e-learning. These online learning platforms came as a boon during and after the COVID-19 pandemic and a study found both teachers and students found e-learning beneficial and appreciated the steps taken during the pandemic in maintaining the continuity of learning through online platforms.^{xxvii}

4. LEGAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT

Justice is also an important requisite for good governance and the social, economic and political justice is essential to preserve the rights and liberties of the individuals in a state and the constitution of India has provisions for the same. An article by Nick Robinson even suggests that the Indian Supreme Court has developed into an oversight body over the rest of the Indian government and serves as a court of good governance.^{xxviii} The Honorable Supreme Court of India established an apex organization, the e-Committee, to carry out the e-Courts project initiative in 2005 with a budget of ₹4.42 billion in an effort to enhance the use of ICT as one of the promising options for decreasing pendency. On August 7, 2013, the e-Courts MMP's national portal **ecourts.gov.in** was officially opened. More than 2852 District and Taluka Court Complexes have established their online presence on the National Judicial Data Grid's (NJDG) site **ecourts.gov.in**, and many of them are also uploading orders and judgements. They are giving case status and cause lists online. NJDG now has information on 3.3 crore orders/judgments and over 7

crore pending and resolved cases from Indian district courts.^{xxix} As Ander claimed in his study: ‘Dysfunctional’ state bureaucracies can be changed into effective, responsible, and law-abiding service providers through the practice of good governance. It is praised as an innovative remedy to poverty and underdevelopment.^{xxx}

GOI launched Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in 2020 with the vision of universal health coverage. The health ID, individual health records, Digi Doctor, and health facility register are the four main elements of the digital platform. GOI also maintains e-Sanjeevani - National Telemedicine Service of India which facilitates easy access to doctors and medical specialists through smartphones. Any person may access audio and video medical advice and prescription medication through e-Sanjeevani OPD (Outpatient Delivery).

The COVID-19 Vaccine Intelligence Network (CoWIN) launched in January 2021 served as the digital spine of one of the largest COVID-19 immunization campaigns in the world i.e., India and kept real-time monitoring of the vaccination program. The UN also mentioned in its survey about the digital steps taken by GOI during the pandemic, it mentioned how India developed an electronic procurement method for all COVID-19-related purchases that reduce the usual bid time from two weeks to three days. Also, the e-RaktKosh initiative, run by the National eHealth Authority, seeks to ‘connect, digitize, and streamline the workflow of blood banks across the country.’^{xxxix} Technology has not only assisted in keeping the healthcare system smooth but also assisted in boosting the economy of the country. A research study has predicted that the Indian HealthTech market, comprising all the technologies used to improve healthcare, is expected to grow rapidly and reach US\$25 billion by 2025.^{xxxii}

CONCLUSION

In the present world, the concept of good governance is being followed by most of the states, especially the democracies and both the domestic as well as foreign policies of the states are being positively influenced by this. ICT has played a major role in improving the quality of governance, it has made the governments today more accountable, responsive, effective and efficient. India too has benefited to a great extent in recent years with the programs like Digital India. The benefits of e-governance have not been limited to urban areas but have also reached rural India. The low internet service cost in India (one of the lowest in the world) has made people more participatory in the governance process.

Through the platforms like CPGRAMS and PRAGATI, the people are in direct digital contact with the authorities and a mechanism is there to address the people's grievances. Online RTI, Twitter and other social media platforms have made the bureaucracy more accountable and transparent than ever before. The e-governance has also made the economy strong as the functioning of state authorities is more transparent today, Foreign Direct Investment has been boosted and the corruption has reduced due to increased digital transactions. Digitalization has benefited holistically in every sector of governance whether it be legal, health, education or the economy. However, even today, the transition to digitization is not yet complete since the concept of e-governance itself is dynamic and continually evolving thus, the government must adhere to the pace of innovation.

References

1. ¹ Tripathi, R. (2017). Good governance: Origin, importance and development in India. *International Journal of Development Research*, 7(11), 16968-16970.
2. ¹ Debnath, A., & WB, P. B. D. B. (2019). The concept of good governance in Kautilya's Arthashastra. *IJRAR-International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 6(2), 745-750.

3. World Bank. (1992a). *Governance and development*. The World Bank.
4. ¹ Dalal, R. S. (2011a). The Conceptual Dimensions of Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 57(1), 91–99. <https://doi.org/10.1177/0019556120110108>
5. ¹ World Bank. (1994a). *Governance: the World Bank's experience*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2>
6. ¹ Kashyap, S. C. (1994). *Our constitution: An introduction to India's constitution and constitutional law*. NBT India.
7. ¹ Dawes, S. S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance. *Public Administration Review*, 68, S86–S102. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x>
8. ¹ Grigalashvili, N. V. (2022). CONCEPTUAL DIMENSIONS OF ELECTRONIC GOVERNMENT AND ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE DOMAIN OF DIGITAL DEMOCRACY. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 1(37). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032022/7753
9. ¹ Sapru, R., & Sapru, Y. (2014a). Good Governance Through E-Governance with Special Reference to India. *Indian Journal of Public Administration*, 60(2), 313–331. <https://doi.org/10.1177/0019556120140208>
10. ¹ *National e-Governance Plan / Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India*. (n.d.). <https://www.meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan>
11. ¹ Sapru, R., & Sapru, Y. (2014b). Good Governance Through E-Governance with Special Reference to India. *Indian Journal of Public Administration*, 60(2), 313–331. <https://doi.org/10.1177/0019556120140208>
12. ¹ Kemp, S. (2023). Digital 2023: India — DataReportal – Global Digital Insights. *DataReportal – Global Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-india>
13. ¹ World Bank. (1994b). *Governance: the World Bank's experience*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2>
14. ¹ *About us/ National Portal of India*. (n.d.). <https://www.india.gov.in/about-portal>

15. ¹ Garg, R. (2022). A Technological Approach to Address Deficiencies in UID (Aadhaar). In *3rd International Conference on Big Data, Blockchain and Security, Copenhagen Denmark*. (Vol. 10).
16. ¹ Ahmad, S. (2022). Direct Benefit Transfer: The Great Technological Move of India. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 1(1), 37-41. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i1.4>
17. ¹ Director, D. M. (n.d.). *Homepage | (DBT) Direct Benefit Transfer*. DBT | Direct Benefit Transfer. <https://dbtbharat.gov.in/>
18. ¹ PTI. (2023, June 29). 6 years of GST: Rs 1.5 trillion monthly tax revenues becomes “new normal”, focus on curbing tax evasion. *The Telegraph Online*. <https://www.telegraphindia.com/business/6-years-of-gst-rs-1-5-trillion-monthly-tax-revenues-becomes-new-normal-focus-on-curbing-tax-evasion/cid/1948558>
19. ¹ PIB Delhi. (2023, February 8). *Digital transactions in India*. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897272>
20. ¹ World Bank. (1992b). *Governance and development*. The World Bank.
21. ¹ PMINDIA. (2015, March 25). *PM launches PRAGATI: A multi-purpose, multi-modal platform for Pro-Active governance and timely implementation*. https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-launches-pragati-a-multi-purpose-multi-modal-platform-for-pro-active-governance-and-timely-implementation/
22. ¹ Singh, G., Pathak, R. D., Naz, R., & Belwal, R. (2010). E-governance for improved public sector service delivery in India, Ethiopia and Fiji. *International Journal of Public Sector Management*, 23(3), 254–275. <https://doi.org/10.1108/09513551011032473>
23. ¹ Dalal, R. S. (2011b). The Conceptual Dimensions of Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 57(1), 91–99. <https://doi.org/10.1177/0019556120110108>
24. ¹ PTI. (2021, November 18). Over 1.59 lakh RTI applications filed online in 8 years, 11,376 by women: Personnel ministry. *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-1-59-lakh-rti-applications-filed-online-in-8-years-11376-by-women-personnel-ministry/articleshow/87774104.cms>

25. ¹ hindustantimes.com, Edited by Nandini. (2020, May 17). PM eVidya Programme for digital education in India: Everything you need to know. *Hindustan Times*. <https://www.hindustantimes.com/education/pm-evidya-programme-for-digital-education-in-india-everything-you-need-to-know/story-15SmSAyTEckgx6gcYIJNYO.html>
26. ¹ *PM e-Vidya - SWAYAM Portal*. (n.d.). <https://pmevidya.education.gov.in/swayam-portal.html>
27. ¹ Singh, M., Adebayo, S. B., Saini, M., & Singh, J. (2021). Indian government E-learning initiatives in response to COVID-19 crisis: A case study on online learning in Indian higher education system. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7569–7607. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10585-1>
28. ¹ Robinson, N. (2009). Expanding Judiciaries: India and the Rise of the Good Governance Court. *Washington University Global Studies Law Review*, 8(1), 1–69. https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=law_globalstudies
29. ¹ *E-Courts Mission Mode Project | Official Website of e-Committee, Supreme Court of India | India*. (n.d.). <https://ecommitteesci.gov.in/project/brief-overview-of-e-courts-project/>
30. ¹ Anders, G. (2005). Good governance as technology: towards an ethnography of the Bretton Woods institutions. *The aid effect: Giving and governing in international development*, 37-60. <https://handoutset.com/wp-content/uploads/2022/06/THE-AID-EFFECT.pdf#page=42>
31. ¹ United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022, September 28). *Un E-Government Survey 2022*. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
32. ¹ The Indian Express Private Limited. (2023). India's healthtech market projected to reach US\$25bn by 2025: Report. *Express Healthcare*. <https://www.expresshealthcare.in/news/indias-healthtech-market-projected-to-reach-us25bn-by-2025-report/439720/>

HISTORY AND LANDSLIDES IN NAINI TAL DURING 19TH CENTURY

Dr. Ajay Singh Rawat, Retd. Professor,
Department of History, Kumaon University, Nainital

Ensnconced snugly at an altitude of 1938 metres above sea level, Naini Tal has made a tryst with fame as a popular hill station. The ancient name of Naini Tal is Tri-Rishi Sarovar, after the three sages, Atri, Agastya and Pulaha. It is believed that they came here on a penitential pilgrimage while going to Mansarovar, the holy lake in Tibet. On finding no water here for drinking, they dug a large hole and siphoned water from Mansarovar with their divine powers. Thus, the ancient Indians believed that a dip in the Naini Lake earned the same religious merit equal to a holy dip in the Mansarovar Lake.

The place was considered so sacred, that the snake god, Nag Karkotak, blessed the area with the boon that in Naini Tal and its environs, no one shall die of snake bite. It is not surprising that before the British occupied this place, the whole valley of Naini Tal was treated as a temple by the Indians and people entered the valley after bathing and removing their footwear in respect.

The second important religious reference to Naini Tal is as one of the 64 Shakti Peeths, i.e., centres of spiritual powers. These centres were created wherever parts of the body of Goddess Sati fell, when Lord Shiva was carrying her body in grief. Sati was the consort of Lord Shiva, her father Dakshaprajapati deliberately insulted Lord Shiva by not inviting him to the grand 'yagya' held at Kankhal, near

Haridwar. Shocked by her father's behaviour and unable to bear the insult to her divine husband, Sati immolated herself in the sacred fire of the 'yagya. Shiva then shouldered the corpse of Sati in grief and began roving frantically owing to which the balance of the universe was disturbed. Lord Vishnu, the Preserver, then intervened and released his 'Sudarshan Chakra', the celestial disc, ensuring that every part of the body of Sati was cut off. When no portion of her corpse was left, only then Lord Shiva was released from the spell of grief. Every place where a part of the body fell gave rise to a deity, and is considered a Shakti Peeth. It is said that the left eye, (Nain) of Sati fell here and this gave rise to the name of local goddess Naina and the lake as Naini Tal, the lake of goddess Naina.

Early Attempts to Urbanize Naini Tal.

The picturesque surroundings, together with the beauty of the lake, the majestic Himalayan view from the hill tops, its proximity to the plains and a salubrious climate, not unlike that of England led to the selection of Naini Tal as a recreation and health resort in 1841 by the British when they arrived here. In November 1843, the settlement was well advanced and by 1847 Naini Tal became a popular hill resort for the British.

Landslides in Naini Tal during the 19th Century.

While visualizing the advantages of Naini Tal as a tourist town, the British did not consider the possibility of landslides, which occurred during the first fifty years of its settlement. The first major recorded landslide occurred in Naini Tal in August 1867, when part of the hill side above the west end of the main bazaar in Malli Tal came down. Fortunately, there was no loss of life. The land slide had one advantage; a committee for the first time was set up on 6th August 1867 known as Hill Side Safety Committee to consider the safety of the hill slopes. The committee, which submitted its report on 12th October 1867, regarded the drainage of the roads as the most important aspect to be dealt with for prevention of landslides.

The Diabolic Landslide of 1880.

After 1867, the next landslide occurred in Naini Tal near the Alma Hill on the Sher-ka –Danda ridge. This landslide struck the town on 18th September 1880 and the total number of people who died in this catastrophe was 151 of whom 43 were Europeans and the rest Indians. The main causes of the landslide were hill cutting and lack of drainage system; the immediate cause however was a slight earthquake on the fatal day of 18th September, together with a continuous downpour 63.5 cm prior to the land slide.

Subsequent upon the land slide the Ramsay Committee was constituted on 22nd September 1880. Its president was Sir Henry Ramsay, the then Commissioner of Kumaon. The Ramsay Committee recommended the following measures:

- (i) Ravines to be lined and riveted.
- (ii) Fissures or long deep cracks to be filled with clay.
- (iii) Platforms, tennis courts and terraces to be covered with 6 inches (15.24 cm) of rammed clay.
- (iv) Further erection of buildings, quarrying and excavation of terraces or platforms to be absolutely prohibited on the affected hill side.

Special care should be taken to prevent injury from house drainage. All houses have cave gutters and masonry drains leading to the nearest suitable ravine where provision should be made for its reception.

- (v) Steep slopes to be turfed and planted with trees. No grass cutting or grazing to be allowed.

- (vi) An honest, efficient, and trustworthy officer should be appointed as Inspector of Buildings and Drains who should work under the sole orders and responsibility of the civil officer in charge of the station.

A committee was further appointed in 1882 to consider the stability of hill slopes in and around Naini Tal on the request of the people to prevent a recurrence of the catastrophe of 1880.

Beneficial Effects of the Landslide of 1880

In spite of the loss of life and property, the landslide had some beneficial effects. Before the year 1880, there was practically no drainage system in Naini Tal. The tragedy which occurred in that year made the authorities think of the urgent need for one. Accordingly, drainage schemes to drain water from the hill slopes around Naini lake were implemented. Nullahs, 79 km in length were constructed throughout the hill slopes of Naini Tal during the period, 1880 to 1885. These nullahs have since saved Naini Tal from destruction.

Senior citizen Satish Chandra Mungali states, “Another beneficial effect of the landslide of 1880 was the creation of the playground Flats as it now exists. A small recreation ground had existed there before the land slide, but as a result of it the space available was largely increased.” Today the Flats has become the throbbing heart of the town and is buzzing with activities throughout the year.

The Ballia Ravine Landslide

In 1898 Naini Tal had to face the anger of nature again in the form of Ballia Ravine landslide. The Ballia Ravine, which is located at the lower end of the Naini Tal lake is important from the hydrological viewpoint as the overflow of the lake water passes through Ballia Nullah attached with the lake and discharges itself in Ballia Ravine. On 17th August 1898, a large chunk of the Kailakhan ridge slid down the Ballia Ravine. It

temporarily filled the bed of the Ballia Ravine, submerged some buildings below the ravine in the area known as Brewery and caused the death of 27 Indians and one European. The cause of the landslide was deforestation and heavy rain owing to which there was percolation of water into the surface layer. From August 9th to August 17th, 1898, Naini Tal experienced 91 cm of rainfall. After the catastrophe, stone walls and drains were constructed in the Ballia Nullah and Ballia Ravine to prevent future landslides. Further, trees were planted on bare lands and unstable areas, and the management of forests in Naini Tal was laid down on the following lines:

- (1) To protect the hill sides from erosion.
- (2) To improve the quality and density of the plantations.
- (3) To improve the scenery of the town by planting more trees.
- (4) To secure the maximum production of firewood and to ensure sustained yield as far as possible.

The British then divided the town into different zones based on geological structure of the land for protective measures. The hillsides around Naini Tal Lake are very unstable owing to the tectonic movement. Movements along the faults have weakened the rocks considerably. The instability of the hill sides is evident from the growing bulges on the hill slopes, the tilting of trees, the subsidence or sinking to lower levels of roads and pathways, the developing of cracks in buildings and other structures, and the movement of pillars. The instability has further increased owing to construction of heavy buildings in an unplanned manner and by cutting trees. The British as early as 1942 had suggested not to construct houses on slopes steeper than 26.5 degrees.

Highly Unstable Zone

According to Professor K.S. Valdiya, an eminent geologist, the highly unstable zone consists of the southwest facing slope of Sher-ka-Danda and a part of the north-east facing slope of the Priory Spur of Ayarpatta ridge. The Ballia gorge (deep narrow valley with steep sides) below Talli Tal bus station and through which the outflow of the lake water passes during the rains, also comes under the highly unstable zone. The second highly unstable zone is on the southwestern side of the lake on the part of the Priory- Fine View Spur above the Purda Dhara.

The third area of great instability is the upper reaches of the Ballia Ravine and the fourth is the southwestern facing scarp or steep slope of the Raj Bhawan-Land's End tract. Blocks after blocks slump down the dangerous scarp or steep slope into the Nihal-Saulia valley year after year.

Moderately Unstable Zone

The moderately unstable zones according to Professor Valdiya are those areas where no major landslides have occurred so far but the creep or gradual movement on the slopes is visible from the tilting of trees and cracks in the buildings etc. The area to the south-east of Assembly Cottage near Snow View up to the Municipal Library on the Mall Road can be taken as a moderately unsafe zone.

Comparatively Safe Zone

Professor Valdiya is of the view that no part of Naini Tal can be described as totally free from hazards of slope failure. However, where the slope is gentler and less than 20 degrees, such as the Flats, Bara Bazar, Sukha Tal, Sleepy Hollow and Ardwell Camp, the present ATI and surrounding area are comparatively stable so far as the slope failure is concerned.

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE IN GOVERNANCE: WITH SPECIAL REFERENCE TO DISASTER MANAGEMENT

J. S. Rawat,

Former National Geospatial Chair Professor (under Geospatial Programme,
DST Government of India) & Former Professor and Head,
Department of Geography, Kumaun University, Nainital

Introduction

Geographic Information Science also known as GIScience (Wilson and Fotheringham, 2008; Longley et al., 2005) refers to a wide range of tools and techniques that contribute to measurement, surveying mapping and analysis of earth's natural and human resources and activities whether those relate to administration, planning, implementation, monitoring or research and studies on different aspects. GIScience refers to the conceptual and technological issues associated with the representation, analysis, modeling, and visualization of space-time data and information (Goodchild, 1992a, b; Bishop and Shroder, 2004; Bishop et al., 2012). In this context, GIScience represents much more than just a cartographic tool to map landforms (Wright et al., 1997). It represents an interdisciplinary field of study focused on the development of the 'philosophical, cognitive, and scientific treatments of spatial theory and concepts that can be used to address information science, physical sciences, and humanities related problems (Bishop and Shroder, 2004). Presently, the GIScience is being used worldwide in administration and planning for

decentralized, transparent, and good governance at different scales (i.e., global, national, state and district level). For this purpose the i) global level stakeholders (i.e., WHO, UNICIF etc) are developing Global Spatial Data Infrastructure (GSDI), ii) the national level stakeholders (i.e., different countries) are developing National Spatial Data Infrastructure (NSDI), iii) the state level stakeholders (i.e., different states of countries) are developing State Spatial Data Infrastructure (SSDI), and iv) the district level stakeholders are developing District Spatial Data Infrastructure (DSDI).

For converting the national level information in GIS environment for national level governance works, the Government of India has established a Division of NSDI in the Department of Science and Technology (DST), New Delhi in 1985. Since that the NSDI New Delhi (<https://nsdiindia.gov.in>) has developed a huge national level database in GIS environment for national level administration and planning. This initiative in a way, represents the progress within India in the GIScience applications in governance and the contributions from these initiatives can be broadly categorized as follows: i) development of the objectives, policies, and efforts toward building GIS data infrastructures, ii) research and development of technologies that advances the capability to use GIS information, and iii) nuanced applications of GIScience technologies (Acharya and Pandey, 2018; Dutta and Pandey, 2018).

GIScience Technologies

The GIScience technologies (Sharda et al., 2018) are divisible into three parts. These are: i) data input technologies, i.e., Remote Sensing (Campbell, 1987; Jensen, 2009), ii) Global Positioning System (GPS) (Bradford et al., 1996), and iii) technology by which digital database with geographic coordinates is developed which is known as Geographic Information System (GIS) (Goodchild, 1996; Chang, 2020). These three technologies have made tremendous progress in different aspects of GIScience such as data collection, data processing, data analysis, map preparation, interactive visualizations, and data transmission from one place to another place

through internet GIS. The GIS is being used widely, specially in developed countries in governance (i.e., both in planning and administration). The GIS based governance is now popular as g-Governance. Now the developing countries are striving for application of GIScience in governance. At present the Qatar state has 100% g-Governance System and the China is nearing almost in g-Governance System.

e-Governance V/S g-Governance

In recent years, there has been an increased need for more timely access to digital geographic maps with coordinates to facilitate effective planning and administration. In e-Governance, one can access information quickly by clicking two-three mouse buttons in computer/laptop/palmtop in the form of tables, text, and analogue maps. But in g-Governance system one can access information quickly with georeferenced maps showing geographic location with latitudes and longitudes of the targeted area/place. g-Governance makes use of concepts and principles from the domain of GIScience by utilizing IT, MIS and Communication Technologies. Thus, the g-Governance system is an upgraded version of the e-Governance system. For developing information systems for g-Governance, an enormous amount of geo-stamped data gathering, compilation, analysis, and manipulation through the GIScience technologies is needed.

Portal V/S Geo-Portal

In e-Governance System different Departments/Ministries/Institutions/Agencies have developed the storage of their data and information at one common platform known as “Portal” through which one can access information quickly by internet in the form of text, tables and analog maps. But in g-Governance System most of the Departments/Ministries/Institutions/Agencies have now upgraded their Portals in Geo-Portals by which one can access information of the targeted place/area quickly with georeferenced geographical map/s of the targeted area/place. Thus, Geo-Portal is upgraded version of Portal.

India Geo-Portal

Development of national level GIS infrastructure in our country is in progress through NSDI Division of The DST New Delhi. Hopefully, the next decade is likely to witness complete switch over to g-Governance in India with all the office records and maps accessible to planners, administrators, and decision-makers in g-referenced map/s form. For this purpose the Natural Resources Data Management System (NRDMS) Division (now Geospatial Programme) of the DST, Government of India (Dutta and Pandey,2018) promoting GIScience technologies in the country by establishing about 72 district-level GIS Centers spread in different States of the country towards establishing GIS Data Infrastructures for supporting implementation of the g-Governance concept (Acharya and Pansey,2018;Dutta and Pandey,2018). At the National Level, India Geo-Portal of NSDI (<https://nsdiindia.gov.in>), acts as a single window access to the metadata and data sets from various national and state level NSDI Partnering Agencies. While the data sets of various agencies are mostly accessible as standards-based Web Map Services (WMS) on the provision of user credentials, the metadata sets are openly accessible from the home page of the India Geo-Portal. A select set of WMS from the India Geo-Portal are accessible from the National Data Portal (<https://data.gov.in>) established and maintained by NIC Government of India under the provisions of the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP), 2012.

State Geo-Portals in India

In India, at present standards-based Geo-Portals are operational in 12 States/UTs like Jammu & Kashmir/ Ladakh, Delhi, Haryana, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, and are under development in 6 States like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. Those for Rajasthan and Goa are in pipeline through dialogue with the respective State Governments. The total number of States/UTs covered so far

under the SSDI Initiative stands at 19 and are at different stages of development and operationalisation (Dutta and Pandey,2018; Acharya and Pansey,2018).

Uttarakhand Towards g-Governance

For developing GIS Infrastructure of in Uttarakhand, a District level GIS Centre was established DST Government of India in 2003 at the SSJ Campus Almora of the Kumaun University, Nainital. Later base on based on the progress and recommendations of this Centre, a Centre of Excellence for NRDMS in Uttarakhand was established in 2012.Through this Centre the State level Stakeholder of GIS specially, the Department of Planning, Government of Uttarakhand was sensitized about the application of GISciene in Governance. Consequently, for developing and regular updating of GIS infrastructure at State and District Level, the State Government of Uttarakhand constituted the following State and District Level committees and Nodal Officers.

State SDI Steering Committee- For management and development of GIS infrastructure for the Uttarakhand State, *vide Government of UK Notification Number 233/XXXVII/14-30/2013, dated 28th May,2014*, the State Government constituted State SDI Steering Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttarakhand in which all the Secretaries are Member.

*State SDI Executive Committee-*To implement the decisions of State SDI Steering Committee, *vide Government of UK Notification Number 127/XXXVII/14-30/2013, dated 28th May,2014*) the State SDI Executive Committee was constituted under the Chairmanship of Principal Secretary, Planning, Government of Uttarakhand in which all the Heads of Line Departments are Member.

*State and District Level Nodal Officers-*To develop GIS as per the needs of state and district planners/administrators, to implement the decisions of the State SDI Executive Committee and to update GIS on regular basis, as per the direction of the

State SDI Steering Committee, the State Government has appointed two level of Nodal Officers with the approval of the Hon'ble Chancellor, Government of Uttarakhand. The Head of each State Government Line Department is the State Level Nodal Officers for developing GIS of his/her own department, while the Chief Development Officer is the Nodal Officer for GIS Development in his/her district (vide Department of Science and Technology, Uttarakhand Government Office Order No.290/XXXVII/15-30/2013/, dated 1st June,2015).

District GIS Coordination Committee -To develop GIS infrastructure of different line departments of the district as per their own needs; to make application of GIS in planning, project implementation, monitoring and in administrative works; to update district GIS at monthly, bi-annually and annual basis through different district line departments; to provide updated district GIS infrastructure; and to make efforts for capacity building of the district for GIS development, Government has constituted District GIS Coordination Committee at each district under the Chairmanship of the District Magistrate in which all the Heads of district line departments are Member.

District GIS Cells -In view of the significance of GIS in planning/administration, the State Government has established GIS Cells in all 13 District Headquarters under the control District Magistrates. *Vide UK Government Notification No.16/XXVI/TWO/(20)2004TC, dated 8th June 2018, the Government of Uttarakhand* has sanctioned 32 posts of GIS Analysts and GIS Technicians out of which till date one GIS Analyst and oneGIS Technician have been appointed at each district GIS Cell. The term of reference of these GIS Analysts and GIS Technicians are: i) development of GIS infrastructure of different line departments of the district on a centralized format, ii) to regularly update the GIS infrastructure of different line departments, and iii) to work for capacity building of the district for application of GIS in governance (i.e., administration, planning, implementation, monitoring, management, surveying, and mapping).

GIScience Applications

GIScience has wide applications in decentralization, transparency and good governance. GIScience has truly become a part of the everyday infrastructure as administrators/planners/managers/decision makers and people use digital geographic maps and mobile apps for their different purposes and various kinds of spatial collaborations. Like other countries, the use of GIScience in India has been steadily increasing in the last few years to cover infrastructure management, planning, monitoring, mapping, analysis, governance etc. A brief account of the application of GIScience in these different sectors is listed below.

In Management -Disaster Management, Environmental Management, Natural Resource Management, Management of Transportation System (Road Network Management, Air Traffic Management, Railway Networking, and traffic control), Management of Marketing Systems, Management of Business Systems, Asset Management and Maintenance. Polling Crime Area Management, Management of Health Centers, Management of Education Centres Lease Property Management. Booth Management. Land use Land Cover Management, Water Resource Management. Cropping Area Management. Wetland Area Management, Forest Fire Area Management, Watershed Management, Mine Area Management, Coastal Line Management, Vegetation Management, Timber Line Management, Snow Line Management, Glacier Lake Management, Pipelines Management, Street Light Management, Wildlife Corridor Management. Heritage Management. Irrigation water management. Desertification Management, Coastal Vegetation Mapping and Conservation Management, Irrigation Water Management.

In Monitoring-Land use/Land cover Change Detection Monitoring, Urban Sprawl Monitoring. Monitoring of weather parameters, Environmental Monitoring. Natural Resource Monitoring, Disaster Monitoring, Monitoring of Transportation System Monitoring of Marketing Systems, Monitoring of Business Systems,

Monitoring of Health Centers, Monitoring of Education Centers, Lease Property Monitoring, Asset Monitoring and Maintenance, Polling Booth Monitoring. Land use Monitoring, Water Resource Area Monitoring, Cropping Health Monitoring, Wetland Area Monitoring, Forest Fire Area Monitoring, Crime Area Monitoring, Watershed Monitoring, View shed Monitoring. Mine Area Monitoring. Coastal Line Area Monitoring, Vegetation Health Monitoring, Timber Line Monitoring Snow fall/Line Monitoring. Glacier Lake Monitoring. Pipeline Monitoring, Street Light Monitoring. Road Network Monitoring, Wildlife Corridor Monitoring, Heritage Monitoring, Air Traffic Monitoring, Defense purpose Monitoring. Coastal Vegetation Monitoring. Sea Ice Motion Monitoring, Glacier Movement Monitoring, Vehicle Monitoring, Sea Level Rise Monitoring, Land Surface Temperature Change Monitoring

In Mapping-Land use/Land cover Mapping, Geological Mapping. Geomorphologic Mapping. Hazard Zone Mapping, Water Resource Mapping, Soil Mapping, Cropping Pattern Mapping. Wetland Mapping. Disaster Events Mapping. Forest Fire Hazard Zone Mapping, Crime Mapping. Spot Mapping (Tourism, Schools, College, Hospital, etc). Watershed Mapping, View-shed Mapping, Mine mapping, Coastal Line Mapping, Vegetation Mapping, Timber Line Mapping, Snow Line Mapping. Glacier Inventory. Glacier Lake Mapping Pipeline Mapping, Street Light Mapping, Road Newark Mapping, Underground Water Interpolation Mapping, Wildlife Corridor Analysis Mapping, Migratory Route Mapping, Heritage Route Mapping, Fire equipment response distance mapping, Fisheries and Ocean Industries Mapping, Desertification Mapping, River Crossing Site Selection for Bridges Coastal Vegetation Mapping and Conservation, Archaeological Site Mapping, Cultural Heritage Inventory, Historical Agricultural Land Mapping, Landslide Vulnerability Mapping etc.

In Planning-Land use Planning, Urban and Rural Planning, Road Development Planning. Sustainable Development, Tourism Planning, Groundwater

Augmentation and River Rejuvenation Planning, Disaster Relief Planning, Traffic Control Planning (Road, Rail and Air Traffic Control).

In Analysis-Site Suitability Analysis, Proximity Analysis, Road Network Analysis, Drainage Network Analysis, Terrain Analysis, Wildlife Corridor Analysis, Weather Prediction Analysis, Crop Pattern Change Analysis, Change Detection Analysis, Environmental Impact Analysis, Navigation (routing and scheduling) Analysis, Disaster (Flood, Landslide, Drought etc.) Damage Estimation Analysis, Land Information Analysis, Coal Mine Fires Analysis, GIS in Dairy Industry Analysis, Tourism Information System Analysis, Irrigation Water Management Analysis, Fire Equipment Response Distance Analysis, Worldwide Earthquake Distance Information System Analyst, Volcanic Hazard Identification Analysis, Energy Use Tracking and Planning Analysis, Fisheries and Ocean Industries Analysis, Reservoir Site Selection Analysis, Traffic Density Studies Analysis, Desertification Analysis, Drainage Problems Analysis in Tea Plantation Areas and other Crops. Public Health Distance Analysis, Site Suitability for Waste Treatment Plant Analysis, School Student Walking Distance Analysis, Locating Underground Pipes and Cables Analysis, Irrigation Water Management Analysis, Live Air Traffic Analysis, *In Measurement* -Measurement of Length, Width, Area, height of geographic phenomenon.

GIScience Application in Disaster Management

During pre and post management of disaster events, the disaster managers, administrators, local people are badly in need of different information. For example: i) location of disaster event site with a geographic map with coordinates), location of the: nearest helipad, police thana, hospitals/health centers with available facility details including the details of doctors; SDRF station, Army Camps; fire station; shelters with capacity and kitchen managers details; public distribution shop/s, ambulance/s and many more; ii) information of the shortest route, alternative routes

to reach up to the disaster site, damage details (both in terms of casualty and property); iii) details of facilities available at the nearest district/tehsil/block/patwari headquarters and at many other places; and iv) details of all the employees with geographic map location of the department of disaster management and district disaster management authorities offices.

For accessing above mention information as per the will of the disaster managers / administrators – by clicking few mouse buttons in the computer/laptop/palmtop - the State Department of Disaster Management and the District Disaster Management Authorities should convert all the analog maps and data/information of their department in a centralized format (see Table-1) of their Districts in the GIS environment in GIS Software using latest technologies of GIScience through the District GIS Cells where two GIS Personnel are appointed by State Government for this purpose. By converting all data and information of all the districts and the entire state in seamless form, the department of Disaster Management and the District Disaster Management Authorities offices shall be paperless environment friendly and the disaster managers/administrators shall be able to access the information through query window in computer/laptop/palmtop during emergency as per their own will at the time of pre, during and post disaster management events. For example i) condition of road/s to reach up to the disaster event by the shortest route or information of alternative route/s (Fig.1); ii) location of the nearest Police Chaukeer with digital georeferenced map and employees details (Fig.1); and location/s of shelters with map and details of facilities available (Fig.3). Similarly, all the information related: i) to disaster site/area (Table-1A), ii) to different villages/towns (Table-1B), and iii) to employees of the department (Table-1C) may be accessed as and when required for disaster management during pre and post disaster events. If more data/information is needed, new information fields may be added in Table-1 as per will of the user/s.

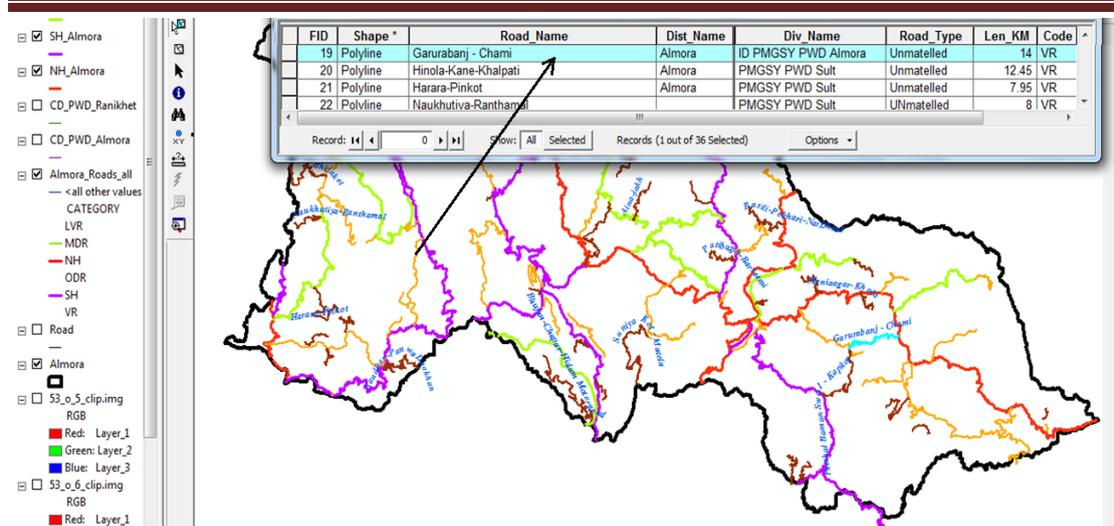


Fig.1: Query of spatial and their non-spatial (attribute) detailed data/information about the desired Classified (i.e.,NH,SH,MDR,ODR,PMGYS and other) road/s of district Almora (Uttarakhand).

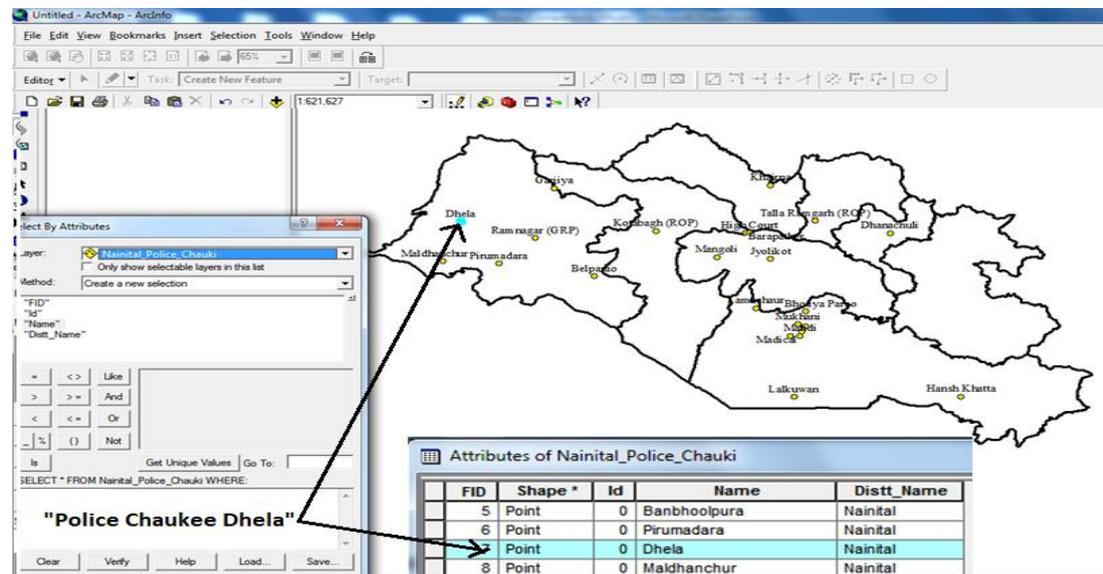


Fig.2: Query through computer of the spatial location of desired Police Chaukee,viz., Dhela with its Detailed non-spatial (attribute) data/information of district Nainital (Uttarakhand).

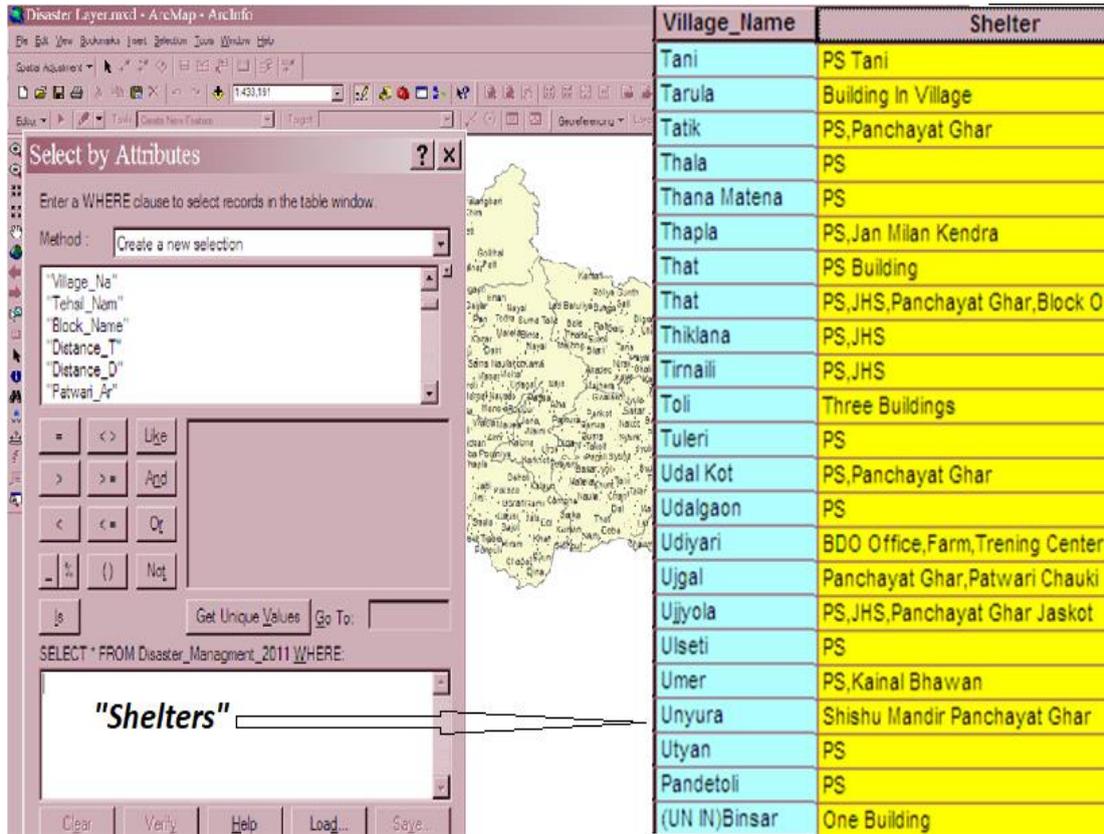


Fig.3: Query of the spatial location of shelters with their detailed non-spatial (attribute) data related to the available facilities in the shelters of district Almora (Uttarakhand).

Table-1: GIS Data Format For Disaster Management***A: DISASTER SITES DETAILS***

S.No.	Name of Information Fields	Abbreviation
1	DISASTER INCIDENT PLACE NAME	PLACE_NAME
2	TYPE OF DISASTER (FLOOD, RAIN FALL, CLOUD BRUST, LAND SLIDE ETC.)	TYPE
3	LATITUDE	LATITUDE
4	LONGITUDE	LONGITUDE
5	BLOCK NAME	BLOCK
6	DISTRICT NAME	DISTRICT
7	AFFECTED VILLAGE NAME	VILL_NAME
8	AFFECTED TOWN NAME	TOWN_NAME
9	DATE AND YEAR OF DISASTER	DATE
10	LOSS OF HUMAN LIFE IN NUMBER	LOSS_LIFE
11	LOSS OF LIVESTOCK IN NUMBER	LOSS_LSTOK
12	PARTIALLY DAMAGED BUILDINGS IN NUMBER	DAM_PBUILD
13	FULLY DAMAGED BUILDINGS IN NUMBER	DAM_FBUILD
14	LOSS OF AGRICULTURE LAND IN HECTARE	LOSS_AGRI
14	ROAD DAMAGE IN KM	DAM_ROAD
15	OTHER DAMAGE IF ANY	DAM_OTH

B: VILLAGE WISE DISASTER PREPAREDNESS DETAILS

S.No.	Name of Information Fields	Abbreviation
1	VILLAGE NAME	VILL_NAME
2	VILLAGE CENSUS CODE	VILL_CODE
3	LATITUDE	LATITUDE
4	LONGITUDE	LONGITUDE
5	BLOCK NAME	BLOCK
6	DISTRICT NAME	DISTRICT
7	VILL DISTANCE FROM THESIL HEADQUTAR IN KM	DIS_THQ
8	VILL DISTANCE FROM DISTT. HEADQUTAR IN KM	DIS_DHQ
9	PATWARI AREA	PAT_ARA
10	PATWARI CHAUKI	PAT_CHAUKI
11	PATWARI NAME	PAT_NAME
12	PATWARI PHONE	PAT_PHONE
13	PATWARI ADDRESS	PAT_ADD
14	PATWARI_P_EON	PAT_P_EON
15	PATWARI PEON PHONE	PAT_P_PHON
16	PATWARI PEON ADDRESS	PAT_P_ADD
17	PATWARI CHAUKI DISTANCE FROM VILLAGE IN KM	DIS_PC
18	REVENUE KANOONGOO AREA	RK_AREA
19	REVENUE KANOONGOO NAME	RK_NAME
20	REVENUE KANOONGOO PHONE	RK_PHONE
21	REVENUE KANOONGOO ADDRESS.	RK_ADD

22	REVENUE KANOONGOO OFFICE DISTANCE FROM VILLAGE IN KM	DIS_RK_OFF
23	NYAYA PANCHAYAT NAME	NP_NAME
24	BLOCK NAME	BLOCK_NAME
25	VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER NAME	VDO_NAME
26	VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER PHONE	VDO_PHONE
27	VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER ADDRESS	VDO_ADD
28	BLOCK DEVELOPMENT OFFICER NAME	DDO_NAME
29	BLOCK DEVELOPMENT OFFICER PHONE	DDO_PHONE
30	BLOCK DEVELOPMENT OFFICER ADDRESS	DDO_ADD
31	GRAM PRADHAN NAME	GP_NAME
32	GRAM PRADHAN PHONE	GP_PHONE
33	GRAM PRADHAN ADDRESS	GP_ADD
34	BLOCK DEVELOPMENT COUNCIL NAME	BDC_NAME
35	BLOCK DEVELOPMENT COUNCIL PHONE	BDC_PHONE
36	BLOCK DEVELOPMENT COUNCIL. ADDRESS.	BDC_ADD
37	BLOCK PRAMUKH NAME	BP_NAME
38	BLOCK PRAMUKH PHONE	BP_PHONE
39	BLOCK PRAMUKH ADDRESS.	BP_ADD
40	NEAREST ROAD HEAD NAME	ROAD_NEAR
41	APPROACH TO VILLAGE (BY ROAD/ON FOOT)	APPRO_VILL
42	NEAREST POLICE THANA NAME	THANA_NEAR
43	POLICE THANA DISTANCE IN KM	DIST_THANA
44	NEAREST HELIPAD NAME	HELL_NEAR

45	HELIPAD DISTANCE FROM DISTT. HEADQUATER IN KM	DIST_H_DHQ
46	VILLAGE IS SENSITIVE FOR WHICH DISASTER	SENTIV_FOR
47	WAS ANY DISASTER HISTORY? (YES/NO) IF YES, DESCRIBE THE EFFECT	DISAS_H
48	ELECTRICITY SUPPLY (YES/NO)	ELECTRICITY
49	WATER SOURCES	WATER_SOU
50	WATER SUPPLY FACILITY (YES/NO)	WATER_SUPP
51	NEAREST HEALTH CENTRE NAME	NHN_NEAR
52	HEALTH CENTER DISTANCE FROM VILLAGE IN KM	DIST_HC
53	TOTAL NUMBER OF EMPLOY IN HEALTH CENTER	TOT_EMPLOY
54	DOCTORS NAME	DOC_NAME
55	DOCTORS PHONE NO.	DOC_PHONE
56	NEAREST PUBLIC DISTRIBUTION SHOP	PDS_NERAT
57	PUBLIC DISTRIBUTION SHOP_DISTANCE IN KM	PDS_DIST
58	PUBLIC DISTRIBUTION SHOP NAME	PDS_NAME
59	PUBLIC DISTRIBUTION SHOP PHONE	PDS_PHONE
60	NEAREST SHELTER NAME	SHELT_NEAR
61	SHELTER CAPACITY	SHELT_CAPTY
62	VOLUNTEERS NAME	VOLUNTEER
63	BLOOD_DONORS NAME	BLOD_DONAR
64	BLOOD GROUP	BLOD_GROP
65	BLOOD DONOR PHONE NO	BD_PHONE
66	COMMUNITY KITCHEN MANAGER NAME	CKM_NAME

67	COMMUNITY KITCHEN MANAGER PHONE NO	CKM_PHONE
68	VEHICLE OWNER NAME	VO_NAME
69	VEHICLE OWNERS PHONE NO.	VO_PHONE
70	VEHICLE NAME (TAXI, BUSS, ETC.)	V_NAME
71	AVAILABLE RESOURCES IN BDO OFFICE	RA_BDO
72	AVAILABLE RESOURCES IN GRAM PENCHANT	RA_GP
73	AVAILABLE RECOURSES IN NEAREST HEALTH CENTRE	RA_HC
74	AVAILABLE RECOURSES IN PATWARI CHAUKI	RA_PC
75	NAME OF GOVERNMENT EMPLOYEE LIVING IN VILLAGE	EMP_NAME
76	EMPLOYEE PHONE NO.	EMP_PHONE

C: DEPARTMENT / OFFICES EMPLOYEE'S DETAILS

S.No.	Name of Information Fields	Abbreviation
1.	NAME OF OFFICE	NAME
2.	LATITUDE	LATITUDE
3.	LONGITUDE	LONGITUDE
4.	NAME OF EMPLOYEE	EMP_NAME
5.	DESIGNATION OF EMPLOYEE	EMP_DESIG
6.	EMPLOY CATEGORY (GEN/SC/ST/OBC)	EMP_CATGRY
7.	EMPLOYEES PAY SCALE WITH LEVEL	EMP_PAYSCLE
8.	EMPLOYEE EDUCATION QUALIFICATION	EMP_EDU

9.	EMPLOYEE CODE	EMP_CODE
10.	EMPLOYEE DATE OF BIRTH	EMP_DOB
11.	EMPLOYEE DATE OF JOINING	EMP_DOJ
12.	EMPLOYEE HOME DISTRICT	EMP_HOME
13.	EMPLOYEE GPF NUMBER	EMP_GPF_NO
14.	EMPLOYEE CPD NUMBER	EMP_CPD_NO
15.	EMPLOYEE PRAN NUMBER	EMP_PRAN
16.	EMPLOYEE MOBILE NUMBER	EMP_MOBIL
17.	EMPLOYEE EMAIL	EMP_EMAIL
18.	PREVIOUS POSTING OF EMPLOYEE	EMP_POST_I

Conclusions

GIScience is a newly emerging discipline which has done revolutionary changes in governance globally which helps in accessing data/information quickly with geographic map with coordinates. The GIScience based governance is known as g-Governance which is upgraded version of e-Governance. With the help of the technologies of this discipline, the developed countries have upgraded the e-Governance system in g-Governance system for decentralized, transparency and good governance. The developing countries are striving for application of GIScience in governance and are currently busy in upgrading their e-Governance system into g-Governance system by converting their all maps and data/information in GIS environment. In developing countries, entire the Qatar State is fully under g-Governance System. Our neighboring country China is almost nearing the g-Governance system up to cadastral level. Through the NSDI Division, the Department of Science and technology Government of India is converting the maps

and data/information of the country in GIS environment and putting these georeferenced maps and data/information in an integrated common platform known as India Geo-Portal. Hopefully the next decade in India would be of g-Governance.

The Government of Uttarakhand State is steadily striving to adopt the g-Governance System. For this purpose, with recommendations of the Centre of Excellence for NRDMS in Uttarakhand (Kumaun University, Nainital), the government of Uttarakhand has established GIS Cells under the control of District Magistrates at the Vikash Bhawan of all 13 districts and has appointed two GIS Personnel at each GIS Cell: i) for development of GIS infrastructure of all the line departments in centralized format, ii) for regular updating of GIS infrastructure, iii) for application of GIS in governance, and iv) for capacity building of the district in application of g-Governance System. As discussed, and demonstrated in this paper, the GIScience is a boon for disaster management during pre and post disaster events. It is recommended that like the Disaster Management Department, all other line departments of the district should convert their maps and office records in GIS environment with the technical assistance of the District GIS Cells for adopting g-Governance System for bringing decentralized, transparent, and good governance in the Uttarakhand State. It is hoped that soon the Uttarakhand State shall have g-Governance System for decentralized, transparent, and good governance. For this purpose, as being the Chairman to the Uttarakhand State SDI Executive Committee (*vide Government of UK Notification Number 127/XXXVII/14-30/2013, dated 28th May, 2014*), the Department of Planning, Government of Uttarakhand should take initiatives: i) to collect the georeferenced data developed of all the line departments by all 13 district GIS Cells; ii) to prepare seamless layers of all the departments for entire the State for the use of state level administrators/planners; iii) to store these all GIS data of all the departments and all the districts in an integrated common web based platform, viz., (Uttarakhand) Geo-Portal; and iv) to do needful to host the Uttarakhand Geo-Portal at the Centre for Public Policy and Good Governance

(CPPGG) for its management by which the Uttarakhand State could adopt g-Governance System for bringing decentralized, transparent and good governance in the State.

References Cited

1. Acharya P.S. and S.Pandey (2018): National Spatial Data Infrastructure India (NSDI-India) Present Status and the Future Strategies,in Geospatial Infrastructure, Applications and Technologies: India Case Studies, N. Sarda et al. (eds.), © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 , <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2330-0>
2. Bishop M. and Shroder, J.F. (2004): Geographic information science and mountain geomorphology. Springer Science & Business Media.
3. Bishop, C. (2012):. Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship. Verso Books.
4. Bradford W.,Parkinson J., Spilkar J.(1996): Global Positioning System,Theory and Applications, American Institute of Aeronautics and ASTRONAUTICS, Science,pp.1-632.
5. Campbell J.B. (1987):Introduction to Remote Sensing, the Guilford Press.

Chang K.T. (2020): Introduction to Geographic Information System,Ninth Edition,McGraw-Hill,Boston.
6. Dutta D. and Pandey S.(2018): Development of State Spatial Data Infrastructure (SSDI): Indian Experience, in Geospatial Infrastructure, Applications and Technologies: India Case Studies, N. Sarda et al. (eds.), © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 , <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2330-0>
7. Goodchild M.F. (1992a): Geographical information science. *International journal of geographical information systems*, 6(1), pp.31-45.
8. Goodchild M.F.(1992b):Geographical data modeling. *Computers & Geosciences*, 18(4), pp.401-408.

9. Goodchild M.F.(1996):GIS and Environmental Modelling, Progress and Research Issues, Edition No.1, Published September 1996, ISH 9780470236772.
10. Jensen J.R.(2009): REMOTE SENSING OF THE Environment, An Earth Resource Perspective, 2/e Pearson Education India.
11. Longley A.P. Goodchild M.F. Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005): Geographic Information System and Science, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd., England
12. Rawat J.S. and Dobhal R.(2018); Uttarakhand State Geo-Portal for Decentralised Governance, in Geospatial Infrastructure, Applications and Technologies: India Case Studies, N. Sarda et al. (eds.), © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 , <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2330-0>
13. Sarda N.L., Acharya P.S. and Sen S. eds.(2018) Geospatial Infrastructure, Applications and Technologies: India Case Studies, © Springer Nature Singapore Pvt. Ltd. 2018 <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2330-0>
14. Wilson J.P. and Fortheringham A.S. (2008): The Handbook of Geographic Information Science, Blackwell Publishing Ltd., MA 02148-5020, USA.
15. Wright S.C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T. and Ropp, S.A. (1997): The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(1), p.73.

JOSHIMATH–JUDICIAL RESPONSES TO THE EYE OPENER FOR HIMALAYAN DEVELOPMENT MODEL

Dr Priya A Sondhi and Anoop Kumar¹

“We cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge: so many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness”.

-Petra Nemcova

Chamoli district, the birthplace of *Chipko* movement and modern lessons of sustainability is now a witness to a disturbing saga, perhaps because we overlooked the lessons of *Chipko* movement. The district administration is constrained to demolish hotels, damaged houses etc. People are being evacuated and relocated, many pets and cattle are being left unattended. Nearly 700 houses in Joshimath have developed cracks in last six weeks.² Since October 2021, the town has witnessed that more than 700 houses have got cracks on the ceilings, walls, and floors³. To add fuel to fire, the ISRO in its report stated that Joshimath sank 5.4 cm in the time frame from December 27, 2022, to January 8, 2023⁴.

Joshimath; the gateway to Badrinath and Hemkund Sahib has been declared a land-subsidence zone. The essential questions which arise are - Are we able to hear

-
1. Dr Priya A Sondhi, is Associate Professor, School of Law, Bennett University and Anoop Kumar id PhD scholar, School of Law, Bennett University
 2. <https://www.hindustantimes.com/cities/dehradun-news/joshimath-land-subsidence-nearly-700-houses-developed-cracks-in-last-6-weeks-101673962770500.html> accessed on 21st January 2023.
 3. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-joshimath-crisis-1674226258-1>, accessed on 21st January 2023.

story of every falling brick? Is every developing crack an act of man? Is Joshimath a manufactured disaster?⁵ Is interim relief of 1.50 lakh sufficient?⁶ Is any fundamental right of citizens being violated? In addition to executive action from Central and State government, the Joshimath crisis has reached the portals of justice, with petitions and interim applications in Supreme Court and High Courts.

To appreciate the developments further, this article is divided into three parts relating to developments in the Supreme Court, Uttarakhand High Court and Delhi High Court followed by Conclusions and suggestions.

Response of Supreme Court

On 16.01.23 in, In Jagatguru Shankaracharya Jyothirmath Jyotishpeethadheeshwar Shri Swami Avimukteshwaranand Saraswati Ji Maharaj v. UoI .7 , the Hon'ble Court observed a substantial overlap between the case before Supreme Court and the Uttarakhand High Court. Also, it was observed that since there has been an assumption of jurisdiction by the High Court under Article 226 of the Constitution, the specific aspects which have been sought to be highlighted before Supreme Court can be addressed before the High Court for redressal.

Thus, the petitioner was permitted either to institute a substantive petition under Article 226 of the Constitution before the High Court of Uttarakhand or, in the alternative to intervene in the pending proceedings.

-
4. <https://www.deccanherald.com/national/east-and-northeast/joshimath-crisis-a-manufactured-disaster-activists-pledge-campaign-1183324.html>, accessed on 21st January 2023.
 5. <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/market-rate-of-compensation-in-joshimath-to-be-decided-with-stakeholders-interest-in-mind-cm-dharami/articleshow/96936449.cms>, accessed on 21st January 2023.

⁷ WP(C) No. 37/2023

Response of Uttarakhand High Court

In an interim application in the case of P.C Tewari vs State of Uttarakhand ⁸, the Mishra

Committee Report of 1976 was appreciated which states that

“Joshimath is sitting on rock and silt, accumulated as a result of landslides. It does not have a solid and stable foundation and is not suitable place for the coming up of a township. Also, vibrations produced by blasting and heavy traffic will also lead to disequilibrium in natural factors”. The said Report warned against undertaking of construction projects.

Article dated 25.05.2010, prepared by Shri M.P. Bisht and Shri Piyush Rautela of H.N.B. Garhwal University, Srinagar (Garhwal) of the Disaster Mitigation and Management Centre was also placed on record.

The Hon’ble court was pleased to direct the State to strictly enforce the ban on all construction in Joshimath area imposed on 05.01.23 and a submit a report by independent experts in various fields like disaster management, Hydrology, Geology, Glaciology, landslide experts before the Court in a sealed cover for its perusal before the next date.

Response of Delhi High Court

Delhi based lawyer Rohit Dandriyal who is also a permanent resident of Uttarakhand’s Pauri district, has filed a public interest litigation in the Delhi High Court seeking constitution of a high-powered joint committee under the chairmanship

⁸ (I.A. No. 9 of 2023) in WPPIL No.67 OF 2021 decided on 12th January 2023. The petition was originally filed in since the year 2021 due to sudden flooding in Dhauliganga river due to bursting of glacier which resulted in damage to the Rishi Ganga Hydro Power Project and the N.T.P.C’s Tapovan Vishnugad Hydropower Project on Dhauliganga River, leading to death of hundreds of people.

of a retired High Court judge and representatives of all relevant ministries seeking inspection of Uttarakhand's Joshimath area affected due to climate and infrastructural changes. The plea also seeks rehabilitation of the residents. His plea states that the said construction activity in Joshimath in the past years has violated the fundamental rights of the residents.⁹ It is important to note that as per the Deputy Advocate General for the State of Uttarakhand JK Sethi two committees have been formed to look into the sinking issue and that a rehabilitation package is also being prepared.

The High Court, while observing that it would hear the matter after the Supreme Court would take it up, listed the matter for further hearing on February 12.

Conclusion and Suggestions

Joshimath and the villages around it are a crystal-clear reminder of nature that certain damage could be irreversible. Though both the Central and State Government are seized of the matter and two committees have been formed to look into the sinking issue and that a rehabilitation package is also being prepared, we still do not have any direction about compensation in any of these cases before courts.

In view of the nature of the crisis and the cases before the Supreme Court and the High courts, we need one case before Uttarakhand High Court with monitoring by way of continuous mandamus.

It is essential to note that though judiciary never intends to become a parallel government, it has a constitutional duty to protect the right to life of people of India. Besides, the fundamental principles of the power of judicial review over administrative action is that the courts review the decision-making process and not the decision itself unless the decision is unconstitutional, illegal, or perverse.

⁹ Rohit Dandriyal v. Union of India

To conclude, as per Aharan Barak, President of the Supreme Court of Israel, “the strength of the judges is in understanding their limitations. More than they have answers to difficult legal problems, they have questions regarding the path they should take”.

CHILD CENTRIC DISASTER RISK REDUCTION

Dr. Manju Pandey, Assistant Professor, Disaster Management Cell,
Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital

Globally, disaster management has become an important stream in various professional and non-professional educational courses and practice. Disaster management aims at reducing or avoiding potential losses from a disaster event, assure prompt and appropriate assistance to the survivors, and achieve rapid and effective recovery. Within the disaster management cycle and concept disaster preparedness for disaster risk reduction are an essential aspect. Within the whole cycle of disaster management community is one of the most important stakeholders to adopt, imbibe and evaluate the same. Thus, the community become self-reliant, confident, and empowered to deal with the disasters and similar eventualities. Disaster management is the responsibility of all stakeholders in the society including governmental/non-governmental organizations and people themselves. Imparting and disseminating the knowledge of disaster management is essential for building knowledge, attitude and skills to engage various stakeholders in managing the disaster risks. Thus, community-based disaster preparedness is most crucial in this direction. Disasters threaten the lives, constitutional rights and needs of the children worldwide. In past two decades India have faced devastating disasters such as Uttarkashi Earthquake (1991), Chamoli Earthquake (1999) Latur Earthquake (1993), Odisha Super Cyclone (1999), Bhuj Earthquake (2001), Indian Tsunami (2004), Jammu & Kashmir Earthquake (2005), Bihar Floods (2008), Uttarakhand Floods (2013), Cyclone Phailin (2013), Chennai Flood (2015), Kerala Flood (2018), and Cyclone Fani (2019). Droughts are slow onset disasters, adversely affecting children

and women alike. Karnataka (16 districts) and Andhra Pradesh (4 districts) experienced at least 10 droughts between 2001-2015. The fire in a school in Kumbakonam, Tamil Nadu, in which 93 children died, raises serious questions about the state of basic education, including safety in schools. Sumgarh village is situated at a distance of 37 Kms towards north direction from Kapkot, Block head quarter in Bageshwar District in Uttarakhand, there is a Saraswati Shishu Mandir located towards eastern side of the river Sarayu, which was connected with a bridle road and a steel girder bridge. Out of 140 students only 35 upper primary students were present. On 18th August 2010 at 0925 hrs. under heavy rain, a major landslide occurred just behind the school building hillock. The debris hit the back side wall of the school building, smashing it, entered inside the rooms and filled up to verandah. Those who were studying in the rooms were buried alive. 18 students under the age of 04 to 10 years buried under the debris. Those who were in the verandah could escape somehow. One teacher and seven students got injuries while escaping from this disaster.

Another disaster hits in Gujrat Bhuj Earthquake 2001 where School building damaged according to the Government of Gujarat, a total of 31 teachers died and 95 were injured, 971 students perished (910 in primary schools, 37 in secondary schools, 3 in colleges and 21 in technical schools) and 1,051 were injured in the Bhuj Earthquake of 2001. Likewise so many incidences show that children suffer a lot in such kind of emergency situations. During these emergencies during disasters, children are more sufferers and are especially vulnerable to diseases, malnutrition, and violence and trafficking. So many diseases come in contact like Measles, diarrhoea, acute respiratory infections, malaria, and malnutrition are the major killers of children during humanitarian crises. Disaster leads to the child trafficking, abuse, lose or poor quality of education, detachment from the family and society, psychological disorder and, many more.

In future, vulnerability of children is expected to increase as the intensity and frequency of natural disasters rises.

Children are not the face of a pandemic, but they risk being among its biggest victims. Evidence tells that a range of health and protection risks arise from a global pandemic, school closures and attempted distancing measures. Children and their families are experiencing closure of childcare and limited or no access to healthcare and other essential services in response to the pandemic. The data is already showing the negative effects of COVID-19, and the unprecedented measures to contain it, on maternal and child health.

Disaster Risk Reduction

Disaster risk is the potential loss expressed in lives, health status, livelihoods, assets, and services, which could occur to a particular community or a society due to the impact of a natural hazard. Simply, Disaster risk reduction is an approach to minimize vulnerabilities. Disaster risk reduction (DRR) is a Scientific and systematic concept of identifying, assessing and reducing the risk. There is main three challenges of disaster risk reduction, they are; to minimize vulnerabilities and disaster risks throughout a society in order to avoid, to mitigate and prepare for the adverse impacts of natural hazards and to support sustainable development. Disaster risk reduction is often taken as climate change adaptation strategy.

About CCDRR

Child centric disaster risk reduction is a multi-sectoral approach as it covers all four dimensions of child rights. CCDRR refers to child centric disaster risk reduction which aims to address children issue before, during and after the hazards. Especially in South Asia, we have faced some of the bigger disaster event such as flood, earthquake, landslides, and epidemic diseases and so on. These hazards threaten life of many people at risk. Disaster directly hits to the prosperity of the country. As we observed minutely, it retards the socio economic, cultural, ecological, and overall status of the country. According to SAARC Disaster Management Centre's South Asia Disaster Report 2011, the region accounted for 96.5% of the total

number of disasters recorded globally in 2011 alone (291 out of 302), killing 2317 people, affecting 23,23,7,989 people and costing an estimated USD 4796 million in terms of economic damages (CRED data in SDMC.).

It was recorded that proportion of the children is more than the half of the total, who affected by disaster. It is observed that children are more likely affected by diseases, poverty, malnutrition, poor sanitation status etc as the side effect of disaster. The CRC, 1989 focused on survival, development, protection and participation of children which can be linked with children issue during emergency. CCDRR identifies eight ways of reducing child vulnerabilities and enhancing children ability to cope with vulnerabilities. Child-centered risk assessments, child friendly infrastructure, protecting children in emergencies, and social protection for children are proposed as means to reduce child vulnerabilities, while participatory action, life skills education, school safety and partnerships are suggested as tools to enhance child capacities.

Prevention & Mitigation:

Prevention and mitigation are a tool to reduce adverse effect of disasters. It includes strengthening the capacity of community networks and its systems after risk assessment. Mitigation aims to involvement of local bodies, stakeholders, and children to strengthen the capacity of communities and households to care for their children and identify and encourage existing positive practices for adaptation during disaster scenario.

Preparedness focuses on establishment of permanent mechanism and structure such as quick response team, child friendly safe space, awareness, safeguarding mechanism, life skills, mock drills in school level, sensitization meetings, awareness campaign, knowledge transfer and dissemination focusing on children. Response and early recovery include necessary action during emergency. It includes information collection, dissemination, team mobilization, prompt response and recovery to the

affected group. CCDRR focus to the service delivery with taking children of different age group on priority.

Child Participation in CCDRR

Child participation is a fundamental key of disaster risk reduction. It is assumed that children contribution is a guiding principle for development of disaster related policy and strategy. Children can play an important role to develop disaster resilient structure and mechanism. Nepal has good example of child participation in local governance. There is a national government strategy of ‘child friendly local governance’ which aims to mainstream the children issue through governance system. Child friendly governance strategy somehow address CCDRR, however, there is still needed to in cooperate CCDRR in broader aspect.

Child participation on local planning process is one of the approaches to cope with disaster. A certain assessment tools can be used to identify the issue through direct child participations in local level planning process in keeping views regarding issues and challenges for children, know how about the resources available. Afterwards children could suggest the possible way and also could discuss how they could contribute to minimize the risk. It could be the best ground to know the strategy to be followed on child centric disaster risk reduction. This ultimately contributes for sustainable development. In this changed federal context, Municipalities and Rural Municipalities especially newly elected representative should focus on child participation on their annual planning process focusing on CCDRR to achieve sustainable development goal.

In conclusion, disaster is a cross cutting and becoming a serious threat to the developing country. CCDRR approach should be in-cooperate to reduce the risk from vulnerabilities as children are most affected age group. Child participation on disaster reduction planning process and local level planning process could be one of the effective methods on Child Centric Disaster Risk Reduction.

DISASTERS AT DUSK OR DAWN FOR THE FAIRER SEX

Dr. Priyanka Tyagi, Research Officer, Disaster Management Cell,
Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital

Dr. Priyanka: Lakshmi! Your Self- Help Group (SHG) has achieved leaps in assisting the poor and destitute women.

Lakshmi: Yes maam! The journey began with a disaster lashing my placid life. I lost everything (my family, my livelihood) at that woeful hour.

Dr. Priyanka: How did you overcome to accomplish this position then?

Lakshmi: Those days exposed me to the savagery of life. I found minor, orphaned, and destitute girls being pushed into flesh trade. I witnessed the operationalization of the organized crimes in the flood ravaged region. I was sexually violated many a times.

This led my consciousness to do something to save the humanity and I came up with this Self-Help Group- **DO IT FOR OTHERS!** To safeguard the plight of forsaken womanhood.

'Violence against women is one disaster that men can prevent.'

-Puntos de Encuentro

(Honduran NGO)

According to the **United Nations Development Program (UNDP)**, ‘women, boys and girls are fourteen times more likely than men to die during the disasters.’ Disasters are natural or man-made/ artificial events that lead to massive loss of lives, economy, ecology, etc., which is beyond the resilience capacity of the affected community or the region. India is a disaster-prone state. The topography of India is exposed to the earthquakes, floods, landslides, cyclones, forest- fires, etc. India lost around \$79.5 billion to natural disasters in the past two decades (U.N Report). Moreover, the present pandemic shrank India’s Gross Domestic Product (GDP) to 7.3% in 2020-21. This was the worst performance of the Indian economy since Independence.

Disasters are considered as the fury of mother nature. Today, more or less, disasters are a response to harmful anthropogenic activities with respect to nature. The human acts of deforestation, pollution, forest fires, chemical and biological accidents, alarming population, urbanization, biodiversity extermination, etc. have disturbed environmental balance. This in return has led to global warming, weather extremes, turmoil in climatic processes, sea-level rise, etc.

However, disasters whether natural or man-made, biological, or chemical can never be seen as an independent variant. A catastrophic event is only a hazard until it incorporates other factors. The impact of a disaster is directly proportional to the social and economic downturn of the nation. Between 1991 and 2005, nearly 90% of disaster related deaths and 98% of people affected by the disasters were in the developing nations. Disasters showcase the existing evils in society. They retreat years of development and endeavors relating the welfare of the mankind. Like- the present pandemic dashed the achievements of the **Millennium Development Goals (MDGs)** and has halted the gains of **Sustainable Development Goals (SDGs)**.

So, do the **Disasters Discriminate?**

The disasters seem to impact different regions and people with varying intensity. The little developed regions and people with scarce resources are most vulnerable to the impacts of the disasters. The extremely vulnerable group is the **fairer sex** or the **women** around the globe. Regardless of their age, marital status, economic empowerment, etc., they are the worst hit.

When the disaster strikes a region, the impacted population faces the death of the loved ones, guardians, deformation and physical injuries, loss of economy, dissipation of shelter, destruction of the livelihood, etc. The affected region immediately transforms into a remote location for some time. The external aids, like that of the governments, NGOs, extended families, etc. require substantial time to reach the place.

However, with every crisis the dark world finds an opportunity to strengthen its claws and exploit the already vulnerable population. Primarily, at this phase of the disasters, the impacted residents are physically and emotionally fragile and traumatized. They are susceptible to the other kinds of evils and misfortunes. The prompt aftermaths of various disasters report the incidents of looting, violence, inhuman behavior, etc.

The **women** victims of disasters have often reported incidents relating to sexual harassment, rapes, kidnappings, etc. In prolonged period, the life of poor women is disadvantaged to the flesh trade. The Tsunami crisis of 2004 reported rapes of girls in all the age groups and some of them even faced multiple penetrations. The selling of abandoned girls is practiced like hoardings in the market. Such incidences are the instant repercussions of the disaster situations.

A report mentioned that the **survival kits** for **distressed women** entailed the demand for **Sindhoo**. The women believed; the red symbol could help them protect their chastity by notifying the people of their surviving guardian. However, the issue arises when these surviving guardians themselves become the violators of their

women, out of depressing disaster situations. So, the first challenge for a woman, at a calamitous event is to safeguard her **bodily integrity**. The killer waves in 2004 reported four times the death of women and the Gorkha earthquake (2015) reported twice the death of women. Even the pandemic soared the survival of women more than men. The women around the world also bear the brunt of **Patriarchy**. The patriarchal mindset not only limit their natural sex ratio, but also hinders the developmental capacities of the living women. So, the women are less equipped with the lifesaving skills, like that of- swimming, climbing trees, driving, etc. They are little educated, ill- informed, suffer digital inequality and lack particulars about an event. Their mobility is highly restricted, do not have decision making rights and are entirely hapless in the absence of their male counterparts. Apart from this, the woman of the family, regardless of her health, age and economy is the primary care giver in the family. She is the last one to eat and similarly the last to vacate the house in case of any emergency. So, women suffer death in the effort of evacuating all the members at the face of calamity, while the men are working outside. The cumbersome attire of the women folk is one other reason endangering their life. The uncladded sarees due to flash floods led the women to accept death in the fear of body shaming, despite their chances of survival. Besides all this, the men succumb to alcohol consumption as the coping mechanism, which again traumatizes the life of domestic women.

On the other front, even the governmental policies are **Gender neutral**. India lacks a specific, pro-active, gender sensitive approach towards Disaster Management. The programs carried out at the time of recovery encompass both the genders. However, the families with woman heads, single women, undergo hardships in assessing the government assistance. The already ill- informed women cannot retrieve the benefits due to the lack of legal credentials. Moreover, the rescue and quarantine centers have reported Gender Based Violence (GBV) and issues of peeping Tom. The education of women is also jeopardized at these hours.

However, various Non- Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society Organizations (CSOs) have played significant role in bridging this gap

between the victims and the governments. The information disseminated by them, and the activities carried out by them have helped the willing women to Build Back Better. Women have undertaken non- traditional roles (masonry, plumber, etc.) to serve their families. The disasters have given them an opportunity to attain self-reliance. Moreover, the financial assistance, short-term skill development courses (pickle industry, beautician course, stitching, etc.), efforts of AASHAs and *aaganwadis* have created women like Lakshmi. The SHG culture has further supported women's psychological and economic needs.

However, the Government of India (GoI) has miles to travel in this direction. Without framing sound Gender Specific policies with respect to Disasters, the government can never achieve Gender Equality. Primarily, there is a need for a separate and independent Disaster Management Ministry. The ministry shall deal with specific vulnerable groups with the help of defined Cells. Separate and trained personnels shall be recruited for disaster management. Disasters have become a daily affair today. The developmental and modernization strategies should not only include **Disaster Resistant Techniques** but also add perspectives like **Women in Development** and **Gender and Development**. Disaster Management shall be a graduation program and various certificate and diploma courses shall serve extra marks in the co-curriculum. Apart from all the traditional recommendations like- D as part of school exercise, safe shelter homes, educational and awareness campaigns, etc., the **Disaster Management Act** shall be upgraded with stricter and severe punishments regarding Gendered Crimes at the time of disasters.

Eventually, it is the moral duty of all the guardians to imbibe gender sensitivity and humanity into their ward at the very cognitive age.

‘Violating a women’s modesty is as grievous and acute as a disaster itself, as such acts have wiped out the ancient civilizations too (Mahabharata and the Trojan War).’

वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 में अकादमी के प्रति योगदान व भविष्य की कार्ययोजना

प्रकाश चन्द्र, पी.सी.एस., संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

दिनांक 19 अगस्त, 2021 को अपनी मूल तैनाती अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के साथ अकादमी में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया गया। तदुपरान्त जुलाई, 2022 से आतिथि तक अकादमी में पूर्णकालिक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया गया। अकादमी में अकादमी के निदेशक/मण्डलायुक्त श्री सुशील कुमार तथा श्री दीपक रावत तदुपरान्त माह जनवरी, 2022 के उपरान्त अकादमी महानिदेशक श्री बी०पी० पाण्डेय के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के तौर पर निम्न दायित्व थे:—

1. कार्यालयाध्यक्ष के प्राधिकार (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन—2018 के अन्तर्गत निर्धारित परिसीमाओं तक वित्तीय आशय के मामलों में स्वीकृति देना— (शासनादेश संख्या—61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02.04.2018 में विद्यमान व्यस्थानुसार)।
2. सामान्य प्रशासन।
3. विभिन्न योजनाओं में लघु एवं वृहद निर्माण कार्यों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण।
4. समूह 'ग' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से सामान्य एवं विशेष परिस्थितियों में स्थाई/अस्थाई अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान करना (जी.पी.एफ. नियमावली में उल्लिखित परिसीमाओं तक)।

5. समूह 'ग' के कार्मिकों को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार।
6. अतिथिगृह/छात्रावास/परिसर सेवाओं का प्रबन्धन/दिशा निर्देश प्रदान करना।
7. सिविल सेवाओं के अधिकारियों तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सत्र लेना।
8. कार्यालयाध्यक्ष की सीमा से बाहर की समस्त विंगों की पत्रावलियों को निदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करना।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी।
10. भारत सरकार, शासन, लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, आयुक्त आदि के विभिन्न संदर्भों का अनुश्रवण एवं निस्तारण।
11. मुख्य सतर्कता अधिकारी।
12. मुख्यमंत्री हैल्पलाईन के अन्तर्गत मामलों के निस्तारण हेतु स३ अधिकारी।
13. कार्यकारी निदेशक, राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल।
14. नोडल अधिकारी- मिशन कर्मयोगी।
15. विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन में किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

प्रशासनिक कार्य

अकादमी ढांचे में कार्मिकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित कार्मिकों की कमी है। अकादमी व आनुशांगिक संस्थान यथा सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (सी०जी०जी०) एवं आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ तथा वाह्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये संकाय सदस्यों, अधिकारियों व कार्मिकों के बीच अभिरुचि एवं योग्यता के आधार पर कार्य वितरण कराते हुए

अकादमी के प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों का प्रबन्धन किया गया। अकादमी में वर्तमान में कार्यरत लगभग 130 मानव संसाधनों की उपस्थिति को बायोमैट्रिक मशीन एवं अकादमी प्रवेश द्वार की प्रविष्टि के माध्यम से कराते हुए कार्मिकों में समयबद्धता एवं कार्यालय अनुशासन सुनिश्चित किया गया।

अकादमी के अधिकारियों, कार्मिकों के आवश्यक प्रकरणों में यथा आवश्यकता प्रशासनिक पहल करते हुए एक सहज वातावरण के सृजन में प्रभावी भूमिका निभाई तथा अकादमी में एक स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित करने में प्रभावी भूमिका निभाई। प्रश्नगत अवधि में अधिकारियों, कार्मिकों के बीच सौहार्द का वातावरण बना रहा। इस कारण आलोच्य अवधि में परिसर में कार्य बहिष्कार, हड़ताल जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिला। पूर्व से लंबित पेंशन भुगतान के कतिपय प्रशासनिक प्रकरणों के वाद माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित होने पर संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरणों का यथासमय समाधान सम्पन्न कराया। प्रश्नगत अवधि में अकादमी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना संबंधी कोई वाद संस्थित नहीं हुआ।

वर्ष 2004 में सोसाईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति अकादमी परिसर में ही सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स संस्था हैं। अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक उक्त सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के पदेन सचिव हैं। सी०जी०जी० के अन्तर्गत की-रिसोर्स सेन्टर, जेण्डर इश्यूज प्रकोष्ठ, बौद्धिक सम्पदा एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ, शहरी विकास प्रकोष्ठ तथा ई-गवर्नेन्स प्रकोष्ठ स्थापित हैं। उक्त सभी प्रकोष्ठ भारत सरकार से अनुमोदित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। सी०जी०जी० के प्रशासनिक प्रबन्धन में सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव की प्रशासनिक प्रास्थिति के सापेक्ष ही सी०जी०जी० को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। सी०जी०जी० में कार्यरत कार्मिकों, संकाय सदस्यों की सेवा का प्रबन्धन भी सचिव के प्रशासनिक उत्तरदायित्व में शामिल है। आलोच्य अवधि में सी०जी०जी० के कार्यों में श्रीवृद्धि की गई है। संस्था के कार्मिकों को देय मानदेय यथासमय उपलब्ध करा दिया जा रहा है। सी०जी०जी० के आन्तरिक खातों की वित्तीय संतुलन रिपोर्ट भी संतोषजनक करा दी गई है।

इसी प्रकार अकादमी में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ तथा नव गठित नगरीय विकास संस्थान भी कार्यरत है। उक्त संस्थाओं में भी संयुक्त निदेशक पूर्णकालिक अधिशासी निदेशक की तैनाती होने तक प्रभारित है। उपरोक्त संस्थानों में अनुबन्ध के अधीन संकाय सदस्यों से कार्य लिया जा रहा है।

दिनांक 27 जून, 2022 को विगत कई वर्षों से लंबित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कराया गया तथा विगत कई वर्षों से लंबित पेंशन प्रकरणों तथा ऑडिट संबंधी कार्य सम्पन्न कराये गये।



अकादमी व अन्य आनुशांगिक संस्थाओं की पत्रावलियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अकादमी के कतिपय कार्मिकों द्वारा निजी हितों के सापेक्ष शासनादेशों की मनमानी व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाते हुए ऐसे कुप्रयासों को निष्फल करते हुए अकादमी परिसर में अवस्थित सभी कार्यालयों में कार्यालय व वित्तीय अनुशासन दृढतापूर्वक लागू कराया। इसमें निश्चित तौर पर तत्कालीन निदेशक व वर्तमान महानिदेशक महोदय का पूर्ण सहयोग मिला।

अकादमिक कार्य

वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय उत्तरार्द्ध में 40



प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 996 प्रतिभागी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 106 प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराये गये, जिसमें कुल 4220 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में अकादमी परिसर में शैक्षणिक वातावरण अनुशासनबद्ध तथा अकादमिक उद्देश्यों के अनुकूल प्रभावी रहा।

माह जनवरी, फरवरी में नैनीताल के तीक्ष्ण शीतकाल में अकादमी द्वारा चम्पावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार तथा देहरादून में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मा० मुख्य सूचना आयुक्त, अपर मुख्य सचिव महोदया तथा विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता रही। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 957 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय बाल अधिकारों पर संवेदीकरण, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर संवेदीकरण तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 थे।

Online Capacity Building Programme on Mission Karmagoyi & iGOT Platform
10th Nov, 2022 (11:00 a.m. - 2:00 p.m)



अकादमी में वर्ष 1995 से ही आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम करा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली के DRR डिविजन के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सन्तोष कुमार द्वारा अपने अकादमिक जीवन की शुरुआत अकादमी से शुरू की गई थी। ऐसे में अकादमी की प्रास्थिति एवं उत्तर भारतीय हिमालयी राज्यों में अकादमी की प्रतिष्ठा और सुव्यवस्थित ढांचे के क्रम में महानिदेशक महोदय द्वारा हिमालयी राज्यों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला करने का निर्णय लिया गया। उक्त राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय **Reducing Risk & Building Resilience : Capacity Building in The Mountain States** रखा गया। इस कार्यशाला का महत्व इसलिए भी था कि इसके माध्यम से अकादमी में होने वाली कार्यशाला के स्वरूप और तैयारी का स्तर का एक मानक स्थापित करना भी था। उक्त कार्यशाला को सम्पन्न कराने में सम्पूर्ण कार्यशाला की रूपरेखा महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार सुनिश्चित की गई। इसके प्रतिभागियों एवं वार्ताकारों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, श्री बसंत श्रेष्ठा, निदेशक ICIMOD तथा पूर्व मुख्य सचिव श्री इन्दु कुमार पाण्डे, निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान श्री ताज हसन सहित प्रशासनिक एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील विषयों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वार्ताकार उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। 329 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता सहित यह कार्यशाला अद्वितीय रही। कार्यशाला के नोडल अधिकारी के तौर पर प्रतिभाग करते हुए उक्त कार्यशाला में अकादमी, सी०जी०जी० के विभिन्न संकाय सदस्यों तथा अकादमी परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग लिया। महानिदेशक महोदय द्वारा उक्त सफल आयोजन पर कार्यशाला के नोडल अधिकारी सहित सम्पूर्ण टीम की सराहना की गई।

आलोच्य अवधि में अकादमी के सहयोग से 04 राष्ट्रीय कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया गया। इसी कालखण्ड में भुवनेश्वर, श्रीनगर, त्रिचनापल्ली तथा जनजातीय सीमान्त क्षेत्र दिफू (असम) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागी/संकाय के तौर पर प्रतिभाग किया गया। उक्त राष्ट्रीय अभिमुखिकरण के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमांचल, असम तथा मेघालय के राज्य प्रशिक्षण अकादमी में रात्रि विश्राम करते हुए उक्त हिमालयी क्षेत्रों की प्रशासनिक अकादमियों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया तथा प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान को यथा आवश्यकता अकादमी में लागू कराने का प्रयास किया।

अकादमी कार्यों को गतिमान करते हुए महानिदेशक महोदय के निर्देशन में निम्नलिखित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण संस्थानों से MoU किये गए, यथा: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की; हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर; पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, वित्त विभाग, देहरादून; जी. बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा; जम्मू और कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जम्मू; भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर; उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। उक्त अकादमिक समझौता पत्र के माध्यम से अकादमी की शैक्षणिक तथा अकादमिक गुणवत्ता का क्षेत्रीय विस्तार हुआ।

अकादमी पुस्तकालय में नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष तैनात नहीं है। तथापि पारदर्शी चयन प्रक्रिया से चयनित वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पुस्तकालय प्रबन्धन को सुदृढ़ करते हुए पुस्तकालय की क्षमता में विस्तार किया गया। इस क्रम में वर्षों से लंबित सी-डेक द्वारा अकादमी पुस्तकों के डिजिटलाईज्ड डाटा वापस मंगाया गया। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के क्रम को डिजिटल करते हुए दो कम्प्यूटर केबिन के माध्यम से ई-अध्ययन की सुविधा देते हुए अकादमी के पुस्तकालय की क्षमता में अभिवृद्धि की गयी। वर्तमान में अकादमी पुस्तकालय में 96,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

जून, 2022 में मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत अकादमी को नोडल संस्था घोषित करते हुए मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को राज्य का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जून, 2022 के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन स्तरीय 03 कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया गया। शासन के निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय क्षमता विकास आयोग, नई दिल्ली के सचिव एवं माननीय सदस्यों से निरन्तर संपर्क स्थापित करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न कराया। इसी क्रम में देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान आई०एस०टी०एम०, नई दिल्ली; आई०आई०पी०ए०, नई दिल्ली; आई०आई०टी०, रुड़की; आई०आई०एम०, काशीपुर; आई०टी०डी०ए०, देहरादून तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए मिशन कर्मयोगी के कार्य को त्वरा दी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमांचल,

जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रशिक्षण अकादमियों से मिशन कर्मयोगी की प्रगति का विवरण लेते हुए प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के कार्यों को आगे बढ़ाया। अकादमी के अत्यन्त अनुभवी महानिदेशक महोदय के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा अन्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमियों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम क्रियान्वयन में अग्रणी स्थान पर है।

दिनांक 01 मई, 2023 की शासन स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अकादमी के निर्मित एल०एम०एस० पोर्टल uaoa.lms.gov.in का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। उक्त पोर्टल में अकादमी द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारियों/कार्मिकों हेतु पंजीकरण के आधार पर उपलब्ध है। वर्तमान में मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत भारत सरकार के i-GOT प्लेटफार्म में राज्य के 40 विभागों के लगभग 280 कार्मिक ऑनबोर्ड हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 10 विभागों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का आकलन अकादमी द्वारा प्रशिक्षित कार्मिकों के माध्यम से प्रारम्भ हो चुका है।

अकादमी में शहरी विकास विभाग की प्रशिक्षण इकाई राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना का कार्य विगत 2016 से प्रस्तावित था। उक्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु महानिदेशक महोदय के पर्यवेक्षण में विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय स्थापित करते



हुए अकादमी परिसर में राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारम्भ में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में कर दी गयी है। वर्तमान में शासन के शहरी विकास विभाग द्वारा नगरीय शोध एवं अध्ययन हेतु धनराशि निर्गत कर दी गयी है। राष्ट्रीय नियोजन एवं वास्तुकला संस्थान, नई दिल्ली से स्नातकों का शोध अधिकारी

के तौर पर चयन कर लिया गया है। निकट भविष्य में राज्य के विभिन्न नगरों का आधारभूत अध्ययन उक्त संस्था से कराया जायेगा।

वर्ष 1998 से लंबित राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा को अकादमी के संकाय सदस्यों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, शासन के सचिवों व निदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में अन्तिम रूप दिया गया। शासन में कार्मिक विभाग के पूर्व सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। वर्ष 2023 के माह फरवरी, 2023 में प्रशिक्षण हेतु तिथि का निर्धारण भी शासन के निर्देशों के क्रम में कर दिया गया था। किन्तु अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जुलाई-अगस्त, 2023 हेतु विस्तारित कर दिया गया है। यह निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड के मध्य क्रम के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ कर राज्य के विकास में श्रीवृद्धि करेगा। आलोच्य वर्ष में गुजरात तथा मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अभिमुखिकरण कार्यक्रम अकादमी में सम्पन्न कराये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अकादमी में सेवा-प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु राजस्व पुलिस व्यवस्था तथा जिले के विकास गतिविधियों में शासकीय नीतियों एवं विभिन्न निधियों के समन्वय से विकासपरक कार्यों के सृजन संबंधी विगत 18 वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वास्तविक धरातल पर किये गये कार्यों के अनुभव के आधार पर सत्र लिये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रशिक्षु अधिकारियों को रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने विषय से संबंधित ज्ञान के प्रसार को अकादमी प्रकाशन में मुद्रित कराने सहित विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में स्वयं प्रतिभाग करते हुए अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराते हुए उन्हें बेहतर अधिकारी बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया। आलोच्य अवधि में प्रशिक्षु अधिकारियों की उपस्थिति अकादमी में सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अनुशासनबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई गई। इससे राज्य की क्षमता का विकास हुआ है। अनुशासनहीन प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई गई, जिससे अकादमी में शुचिता व गरिमामय वातावरण बना रहा है।

अकादमी परिसर में विगत वर्षों के लंबित कार्य

अकादमी में तैनाती के समय माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 433/434 के अन्तर्गत ऑल वेदर मल्टी यूज सर्फेस कोर्ट का निर्माण कार्य तथा अकादमी प्रेक्षागृह (मानसरोवर) के जीर्णोद्धार का कार्य मात्र धनराशि स्वीकृत एवं कार्यदायी संस्था के चयन तक अपने प्रारम्भिक चरण में था। तत्कालीन निदेशक महोदयान के निर्देश में तथा कालान्तर में महानिदेशक महोदय के निर्देशन में उक्त कार्य यथासमय सम्पन्न कराने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों के विलम्ब को देखते हुए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, जनपद नैनीताल तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को पर्ट चार्ट के माध्यम से कार्यप्रगति का मासिक लक्ष्य देते हुए तथा उसका अनुश्रवण करते हुए निर्माण कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय कार्यशाला के दिन लोकार्पण भी करा दिया गया तथा दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं की उपस्थितियुक्त 11 हिमालयी राज्यों की कार्यशाला इसी प्रेक्षागृह में सम्पन्न करायी गयी। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का ही बैडमिन्टन हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किया गया। उक्त निर्माण कार्यों की मुक्तकंठ प्रशंसा परिसर में आने वाले अतिविशिष्ट महानुभावों सहित मुख्य सचिव महोदय तथा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भी की गई।



माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत निर्मित लॉन टेनिस, वॉलीबाल तथा बास्केट बाल हेतु
ऑल वेदर मल्टी सर्फेस यूज कोर्ट के निर्माण के विभिन्न चरण



माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत निर्मित आधुनिक बैडमिन्टन हॉल के निर्माण के विभिन्न चरण

अकादमी परिसर में ही प्रशिक्षु अधिकारियों के उपयोगार्थ आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण हेतु आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ से वित्तपोषित आर्टिफिशियल रॉक क्लाइम्बिंग वॉल का निर्माण कराया गया। जिसका लोकार्पण माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड महोदय द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को किया गया।

इसके अतिरिक्त विभागीय बजट से अकादमी परिसर की परिसम्पत्तियों यथा मेरू सभागार को आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण युक्त बनाया गया, जिससे देश विदेश की संस्थाओं से वैचारिक एवं अकादमिक सूचनाओं का संचरण व वीडियो वार्ता अधिक गुणवत्ता के साथ हो रहा है। कक्ष संख्या 10 के समीपवर्ती अन्य कक्षों को शामिल करते हुए 96 सीटों का एक परिचर्चा कक्ष निर्मित कर दिया गया है। कक्ष संख्या 10, कैलाश वर्तमान में पूर्ण रूप आधुनिक संसाधनों सहित तैयार हो चुका है। इसी के साथ अकादमी परिसर में स्थित आर्डवेल व एवरसिले भवन के जीर्णोद्धार कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये गये। इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त व्यायामशाला सहित अकादमी मैस के विस्तारीकरण का कार्य व प्रशिक्षणार्थी एवं अतिथि वार्ताकारों के सहकारियों को गरिमा के साथ सूक्ष्म जलपान/भोजन की व्यवस्था हेतु अन्नपूर्णा भोजनालय की स्थापना न्यूनतम धनराशि में महानिदेशक महोदय के निर्देशन में की गई। अकादमी परिसर के अनावसीय तथा छात्रावासों सहित अलकनन्दा एवं भिलंगना भवनों को 24X7 विद्युत प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करायी गई। इसके साथ ही अलकनन्दा भवन में स्थित पेन्ट्री को विकसित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतीक्षा कक्ष के तौर पर प्रयोग हेतु उत्तम सुविधायुक्त प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण कराया गया।

आलोच्य अवधि में अकादमी में देश विदेश के विद्वानों, भारत सरकार/राज्य सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों तथा माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आगमन निरन्तर होता रहा है। उपरोक्त उच्च श्रेणी के महानुभावों द्वारा अकादमी के अकादमिक कार्यों, परिसर सुविधाओं तथा अकादमी में तैनात अधिकारियों के कार्य व्यवहार की सराहना लिखित तौर पर अकादमी के विवरणिका में दर्ज की गई हैं।

अभिनव प्रयोग

वर्ष 2022 के प्रारम्भ में ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा अकादमी में पूर्णकालिक महानिदेशक श्री बी०पी० पाण्डेय सर की तैनाती की गयी। महानिदेशक महोदय के विराट प्रशासनिक अनुभव का लाभ अकादमी को मिल रहा है। महानिदेशक महोदय के अभिनव प्रयास प्रत्येक सोमवार को होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में होने वाली बैठक (SOM) निश्चित तौर पर अत्यन्त प्रभावशाली साबित हुई है। इस नवाचार में विगत सप्ताह दिये गये निर्देशों का अनुपालन तथा आगामी सप्ताह हेतु कार्ययोजना का निर्माण सभी अधिकारियों की उपस्थिति में होते हैं। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के तौर पर महोदय के उक्त अभिनव कार्यक्रम को शतप्रतिशत सुनिश्चित कराते हुए महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से कराया है। आतिथि तक कुल 56 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

वर्ष 1998 के उपरान्त अकादमी का नियमित पाक्षिकी "वैचारिकी" का प्रकाशन अवरूद्ध हो गया था। अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली उक्त पत्रिका "वैचारिकी" का 25 वर्षों के पश्चात् प्रकाशन पुनः प्रारम्भ करवाया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक दिनांक 27 जून, 2022 को अकादमी के बोर्ड के अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा बोर्ड के सदस्यों सहित विमोचन किया गया।



अकादमी के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले सेवा-प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका में प्रशिक्षु अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पत्रिका में अपने विभाग, कार्य एवं प्रशिक्षण से संबंधित लेखों को ही प्रकाशित करवाया जाय, जिससे पत्रिका में छपने वाले लेखों में से कुछ लेख जो उच्च श्रेणी के होंगे उन्हें अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "वैचारिकी" में प्रकाशित करवाया जाना प्रस्तावित है।

अकादमी में राष्ट्रीय पर्वों यथा: गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती तथा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने की परम्परा को

और अधिक भव्य तरीके से सम्पन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा: महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, योग दिवस, हरेला महोत्सव के अवसर पर 108 चिनार के वृक्षों के वृक्षारोपण सहित भव्य व गरिमामय तरीके से मनाने की पुरानी परम्परा को पुर्नजीवित करते हुए अकादमी में हर्षउल्लास का वातावरण सृजित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया।



माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत निर्मित अकादमी प्रेक्षागृह (मानसरोवर) के निर्माण के विभिन्न चरण



विभागीय बजट से कक्ष संख्या 10 को 96 क्षमता वाले कैलाश वार्ता कक्ष के पुर्ननिर्माण के विभिन्न चरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अकादमी को प्राप्त हो चुका है। उक्त बजट में कार्यालय व्यय, लघु निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन है। इसी तरह वृहद निर्माण हेतु रु० 5.00 करोड़ की धनराशि का प्रावधान भी बजट में किया गया है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाने है। उक्त बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य निम्नवत् है:-

1. अकादमी परिसर, वैभरली कम्पाउण्ड में टाईप-4/5 के 4 आवासों का निर्माण।
2. गेट नं० 2 के समीप 24 कक्षों का एकजीक्यूटिव हॉस्टल का निर्माण।
3. चौखम्बा भवन के भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल में स्थित शौचालयों का जीर्णोद्धार।
4. चौखम्बा भवन स्थित प्रशासनिक ब्लॉक का सौन्दर्यीकरण।
5. गंगोत्री छात्रावास में वरिष्ठ अधिकारियों के अनुकूल फर्नीचर।
6. अकादमी परिसर में दिव्यांगजनों को सुविधा देने वाले आधारभूत अवस्थापना विकास के कार्य।
7. नगरीय विकास संस्थान हेतु अकादमी के परिसर में भागीरथी भवन के पृष्ठ भाग में स्थित कक्ष का उच्चीकरण।
8. अकादमी में स्थल विकास।

इसके अतिरिक्त वर्ष के द्वितीय षट्मास में मिशन कर्मयोगी के मॉड्यूल निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यकारी शाखा के अधिकारियों हेतु सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नगरीय विकास संस्थान के सौजन्य से प्रदेश के चिन्हित नगरों का अध्ययन कराना शामिल है। इस हेतु अकादमी में रिक्त संकाय सदस्यों/अधिकारियों की तैनाती की जानी अनिवार्य है। इसी के साथ अकादमी में रिक्त पदों के सापेक्ष कनिष्ठ एवं मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की तैनाती भी करनी होगी। शासन में कार्मिक विभाग के पूर्व सचिव श्री अरविन्द सिंह

हयांकी तथा वर्तमान सचिव श्री शैलेश बगोली, अकादमी की आवश्यकताओं के प्रति सजग एवं पूर्ण सहयोग करते हैं।

अकादमी में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की भूमिका

यह एक संयोग है कि अकादमी में पूर्णकालिक अपर निदेशक का पद सृजित है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी हेतु कैंडर पद है। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर वरिष्ठ राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारी तैनात रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पश्चात् कदाचित ही अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एक साथ अकादमी में तैनात रहे हैं। दिनांक 30 मार्च, 2013 से अकादमी में अपर निदेशक का पद रिक्त है। ऐसे में महानिदेशक/निदेशक के उपरान्त संयुक्त निदेशक (प्रशासन) महत्वपूर्ण भूमिका में तैनात रहे हैं।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अकादमी के कार्य संचालन हेतु कार्यालयाध्यक्ष है। अकादमी के नैतिक प्रशासन एवं अकादमिक कार्यों में महानिदेशक/निदेशक/विभागाध्यक्ष के विश्वास के अधीन कार्य करते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर संयुक्त निदेशक से शासन/निदेशक की अपेक्षानुसार शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने वाले अधिकारी की होती है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक/निदेशक की अनुपस्थिति में अकादमी में कार्यालयाध्यक्ष के तौर पर कार्य संचालन हेतु जवाबदेह भी है।

अकादमिक कार्यों में सचिवालय/निदेशालय तथा क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयों के बीच समन्वयक की भूमिका का निर्वहन भी संयुक्त निदेशक को करना होता है। इस हेतु जनपद, निदेशालय एवं सचिवालय में सेवा दे चुके वरिष्ठ अधिकारी निश्चित तौर पर अधिक प्रभावी भूमिका में रहते हैं। किन्तु उपरोक्त वर्णित कार्यों में विभागाध्यक्ष का संयुक्त निदेशक पर विश्वास तथा पूर्ण सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के बीच संशय व अविश्वास की स्थिति में अकादमी में विद्यमान नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकारी/कार्मिक सक्रिय हो उठते हैं, जिसके परिणाम निश्चित तौर पर अकादमी के हितों के प्रतिकूल साबित होते हैं। संयुक्त निदेशक को अत्यन्त सजगता एवं सतर्कता पूर्वक अकादमी के विभिन्न अधिकारियों, संकाय सदस्यों तथा मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों से प्रभावी समन्वय व प्रशासनिक

नियंत्रण स्थापित करते हुए अकादमी का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजन कराना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अकादमी का आधारभूत ढांचा हमेशा तैयार रहें तथा यथासमय प्रशिक्षणार्थियों एवं अतिथि वार्ताकारों की उपलब्धता तथा उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त संसाधन यथासमय उपलब्ध कराये जा सकें। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त है। अकादमी में सभी प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करते हुए सकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हुए उनका मनोबल बना रहे, इस हेतु प्रभावी पहल किया जाना भी अनिवार्य है। निदेशक/महानिदेशक महोदय के सहयोग से अकादमी आलोच्य कालखण्ड में विकासोन्मुख हो निरन्तर नये आयाम छू रही है। इस हेतु संयुक्त निदेशक को स्वयं अनुशासनबद्ध हो अकादमी परिसर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करनी होती है। प्रायः मुख्यालय में निवास करने वाले संयुक्त निदेशक अधिक प्रभावी भूमिका में देखे गये हैं।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे अकादमी के पूर्व निदेशकों तथा वर्तमान महानिदेशक महोदय का स्नेह एवं विश्वास प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही अकादमी में तैनात राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सहयोगी साथी अधिकारी, अकादमी के प्रति प्रतिबद्ध कतिपय संकाय सदस्य तथा निष्ठावान कार्यालय के सहयोगी द्वारा 24X7 की निष्ठापूर्वक सहयोग हासिल है। तभी उपरोक्त वर्णित कार्य सम्पन्न किये जा सकें हैं।

सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के फिट रहने से सुशासन को मिलेंगे नये आयाम

हेम चन्द्र, सहायक निदेशक (रेशम), उत्तराखण्ड सरकार

ACSM Certified Fitness Trainer

(ACSM- American College of Sports Medicine)

Mr. Uttarakhand (Body Building)

ESA Certified Fitness Trainer

(Exercise Science Academy, Mumbai)

Motivational Icon of India

कुछ लोग फिटनेस का अर्थ पतला होना, तगड़ा होना या फिर सुंदर दिखने से जोड़ते हैं, जबकि फिटनेस इन सबसे कहीं आगे की बात है; स्वयं में वृहत्तर अर्थ समेटे हुये है। पतला होना, तगड़ा होना, सुंदर दिखना, इन सबको तो फिटनेस के कुछ साइड इफेक्ट्स कहना अधिक उचित होगा।

अपने अन्तिम उद्देश्यों के दृष्टिगत 'फिटनेस' शब्द को यँ परिभाषित करना सर्वथा उचित होगा कि 'फिटनेस एक कला है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को प्रसन्नता, शांति, खुशी, धैर्य, लगन, मेहनत, निरंतरता, कुशलता, दृढता, समर्पण, एकाग्रता, सकारात्मकता व आत्मविश्वास के उच्चतम स्तर तक जीना सिखाती है।

मसलन कोई व्यक्ति फिटनेस के जितने उच्च स्तर को प्राप्त करेगा, वह अपने व्यक्तित्व में उपरोक्त गुणों व विशेषताओं को उतनी ही उच्च मात्रा में सम्मिलित कर सकेगा; जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति में सर्वथा वांछनीय है।

यद्यपि फिटनेस शब्द को दैनिक जीवन में अधिकांशतया शारीरिक फिटनेस के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तथापि यह अपने में पुनः वृहत्तर अर्थ समेटे हुये है। शारीरिक फिटनेस से इतर भी फिटनेस के विभिन्न प्रकार हैं।

फिटनेस को मुख्यतया निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

- ⇒ शारीरिक फिटनेस
- ⇒ मानसिक फिटनेस
- ⇒ भावनात्मक फिटनेस
- ⇒ व्यावहारात्मक फिटनेस

फिटनेस के उपरोक्त सभी प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं व सामूहिक अर्थ में किसी की भी सफलता व खुशी का मूल-मंत्र हैं। हम सदा से ही एक सत्य वचन-उक्ति सुनते आ रहे हैं कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है'; अर्थात् यदि आपने शरीर को स्वस्थ कर लिया है तो आपने मानसिक फिटनेस भी प्राप्त कर ली है। तब आवश्यक रूप से आपके भीतर निरंतर अंकुरित हो रही भावनाएं भी अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत, न्याय संगत व मानवता को प्रेरित होंगी जो फिर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में आपके व्यवहार में स्वस्थ रूप से परिलक्षित होंगी।

उपरोक्त मात्र आध्यात्मिक तथ्य नहीं है यह विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध है। जब आप शारीरिक फिटनेस को प्राप्त करने के लिए व्यायाम/शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन, नोरेपिनेफरीन, सेरोटोनिन नामक रसायन का स्राव होता है और यह रसायन दर्द से आराम, तनाव व मूड के नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह वैज्ञानिक आधार स्पष्ट दर्शाता है कि शारीरिक फिटनेस अपने अगले कदम में आपको मानसिक फिटनेस की प्राप्ति कराती है।

फिटनेस को प्राप्त करने का मुख्य श्रोत व्यायाम/शारीरिक गतिविधि, उचित पोषण व पर्याप्त निद्रा ही है। सामान्यतया व्यक्ति व्यायाम से होने वाले लाभ को केवल वजन नियंत्रित करने तक ही सोचता है, जबकि इससे होने वाले लाभ मात्र वजन नियंत्रण से कहीं अधिक हैं। अनुसंधान दर्शाते हैं कि नियमित व्यायाम हमें अनेक बीमारियों व अस्वास्थ्यकारी स्थितियों से बचाता है और हमारे जीवन की सकल गुणवत्ता में वृद्धि करता है। नियमित व्यायाम से होने वाले कुछेक लाभ इस प्रकार हैं जैसे – हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के सुधार में सहायक, पेरिफेरल वैस्क्यूलर डिजीज से सुरक्षा, नानइंसुलिन डिपेंडेंट डाइबिटीज नियंत्रण में सहायक, मोटापा नियंत्रण में सहायक, कमर दर्द में सुधार, ओस्टियोपोरोसिस में सुधार, अवसाद, चिंता, तनाव प्रबन्धन इत्यादि।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि सभी प्रकार की फिटनेस को प्राप्त करने हेतु शारीरिक फिटनेस को प्राप्त करने का प्रयास करना सर्वप्रभावी कदम होगा। अतः इस लेख के शेष अंश में शारीरिक फिटनेस को 'फिटनेस' शब्द द्वारा ही सम्बोधित किया जा रहा है।

किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का आकलन करने का एक व्यावहारिक तरीका है **Waist-to-Hip Ratio (WHR)**। यह तरीका फिटनेस आकलन के एन्थ्रोपोमेट्रिक (मानविकी) माप विधि के अन्तर्गत आच्छादित है। **WHR** वास्तव में इतना आसान तरीका है कि इसके द्वारा मात्र आखों से देखकर भी किसी व्यक्ति की फिटनेस का काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। **WHR** विधि के अन्तर्गत व्यक्ति की कमर (**Waist**) की परिधि एवं **Hip** की परिधि का अनुपात लिया जाता है।

अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन (ACSM) के अनुसार यदि एक युवा पुरुष वयस्क में **WHR** का मान 0.95 से अधिक व एक युवा महिला वयस्क में 0.86 से अधिक तथा 60 वर्ष से 69 वर्ष आयु के मध्य के पुरुष वयस्क में 1.03 व महिला वयस्क में 0.90 से अधिक होता है तो उनमें बीमारी होने की सम्भावना बहुत अधिक हो जाती है। सामान्यतया **WHR** मान जितना अधिक होगा, विभिन्न चिरकालिक बीमारियों के होने का उतना ही अधिक खतरा होगा।

तात्पर्य है कि **WHR** विधि की जानकारी होने पर आप सामने वाले को देखकर ही उसकी फिटनेस का अनुमान लगा सकते हैं। मसलन किसी व्यक्ति को देखने से यदि जान पड़

रहा है कि उसकी कमर (Waist) उसके Hip के बराबर या अधिक है तो उसकी फिटनेस नकारात्मक जोन की तरफ जा रही है।

अब जब इस लेख को पढ़ते-पढ़ते हम फिटनेस सम्बन्धित इतने तथ्यों से अवगत हो चुके हैं तो अब बात करते हैं सरकारी महकमे की। इसे सरकारी महकमे की कार्यशैली का प्रभाव कहें या फिर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी फिटनेस को नजर अन्दाज करना व जीवन में दायम दर्जे एवं कम प्राथमिकता का विषय समझना। खैर जो भी हो हम किसी सरकारी संस्थान में चले जायें या फिर किसी सरकारी महकमे की बैठक में, आपको अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों का Waist-to-Hip Ratio (WHR) 01 से कहीं अधिक मान का मिल जायेगा अर्थात् अधिकांश की कमर की परिधि उनके Hip की परिधि से कहीं बढ़ी हुई जान पड़ेगी जो सीधा उनके फिटनेस के नकारात्मक स्तर की ओर इशारा करती हुई प्रतीत होगी। ऐसे में यह मान सकते हैं कि उनमें से अधिकांश कई बीमारियों से जूझ रहे होंगे व कुछ अनेकों बीमारियों को न्यौता देने को तैयार बैठे होंगे, कुछ अधिकारी/कर्मचारी जो देखने पर पतले नजर आ रहे होंगे किन्तु WHR विधि के माध्यम से उनकी फिटनेस का अनुमान लगाते समय हमें उनके पतलेपन को नहीं जबकि उनके Waist-to-Hip Ratio (WHR) का संज्ञान लेना है।

इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हम यह जान गये हैं कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी कितना फिट है या कितना अनफिट या फिर यह कि उनकी फिटनेस का स्तर क्या है। जबकि सरकारी महकमा एक ऐसा महत्वपूर्ण तबका है जिसके कन्धों पर सम्पूर्ण राज्य, सम्पूर्ण देश के नागरिकों के विकास, कल्याण व सुरक्षा इत्यादि का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है।

सुशासन इन्हीं के द्वारा परिभाषित किया जाना है। जब सरकारी अधिकारी/कर्मचारी फिट होगा तो वह अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर सकेगा जो अन्तिम रूप से समस्त जनता का अधिकतम विकास व अधिकतम कल्याण व समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे सुशासन अपने नये आयाम स्पर्श कर सकेगा व सुशासन असल सुशासन हो सकेगा।

फिटनेस एक वृहद विषय है यह लेख मात्र इस हेतु है कि सरकारी महकमे में फिटनेस की उपयोगिता को चिन्हित किया जा सके। आगे के अंशों में कैसे स्वयं को फिट रखा जाये जैसे अनन्त विषयों पर विचार प्रस्तुत करने के निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे।

प्रशासनिक गुरुकुल में तीन दशकीय सफरनामा

विवेक कुमार सिंह, उप निदेशक,
डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, कभी एहसास ही न हुआ कि सरोवर नगरी के इस प्रतिष्ठित संस्थान में एक युग व्यतीत हो गया। नवम्बर, 2000 से पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी तथा तत्पश्चात् उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में सम्मिलित रूप से तीन दशकों के लम्बे सेवाकाल से प्रशासन अकादमी में एक नए इतिहास को रचा गया। आतिथि तक किसी भी संकाय सदस्य द्वारा इस अकादमी में इतनी लम्बी सेवा प्रदान नहीं की गयी है। इस अवधि में विभिन्न पदों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकादमी की भूमिका एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करने में अपना योगदान दिया। दिनांक 01 मई, 1993 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी में सहायक निदेशक (कम्प्यूटर) के पद पर योगदान दिया गया था। 06 वर्ष की सेवा पश्चात् 1999 में उप निदेशक (कम्प्यूटर) के पद पर चयन पश्चात् आतिथि तक अपनी सेवाएँ निरन्तर रूप से इस अकादमी को प्रदान की जा रही हैं।

अपने प्रारम्भिक दौर में यह अकादमी मात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा प्रादेशिक सिविल सेवा के अधिकारियों हेतु कार्यरत रही परन्तु उत्तराखण्ड निर्माण के पश्चात् इसके दायित्वों को विस्तार करते हुए शासन द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित समस्त कार्मिकों हेतु एक माह का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न विभागों को अपने नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित कराने का अवसर प्राप्त हुआ। संकाय होने के नाते हमें भी विभिन्न विभागों के साथ जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।

कम्प्यूटर प्रयोग का विस्तार

वर्ष 1993 के दौरान शासकीय कार्यालयों में कम्प्यूटर की उपलब्धता न केवल सीमित थी बल्कि प्रदेशों के शीर्षस्थ अधिकारियों के कार्यालय कक्ष में ही उपलब्ध होने के कारण कम्प्यूटर को लेकर अन्य कार्मिकों में एक जिज्ञासा एवं कौतुहल को पाया जाता था। परन्तु कम्प्यूटर की उपलब्धता न होने के कारण वे उसके प्रयोग पर कौशल विकसित करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। कम्प्यूटर प्रयोग के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रारम्भिक दौर में अकादमी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव स्तरीय अधिकारियों में कम्प्यूटर प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी सराहना सम्पूर्ण प्रदेशों में हुई। मध्यस्तरीय अधिकारियों हेतु भी कम्प्यूटर प्रयोग से सम्बन्धित सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेशों में शासकीय अधिकारियों के मध्य अकादमी का एक विशेष स्थान बनाया गया। इन कार्यक्रमों में कम्प्यूटर परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट इत्यादि के सम्बन्ध में सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता रहा। समय के साथ बदलते हुए कम्प्यूटर परिवेशों में विकसित हुए नए सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित कर प्रदेशों में कम्प्यूटर कल्चर को विकसित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित करने की सफलता को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेशों एवं वर्तमान उत्तराखण्ड के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों यथा सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर, राजस्व पुलिस एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर लैब की संरचना एवं स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जिससे कि सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रयोग में दक्ष बनाने में योगदान दिया जा सका।

अन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में पदार्पण

1997 में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें विशेषकर Thames Valley University, UK से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल रहे। भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत

Direct Trainer Skills प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक के रूप में प्रमाणित किया गया। जिसके पश्चात् विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षकों को तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में अकादमी में भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एकमात्र संकाय के रूप में विद्यमान हूँ। समय के साथ अन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में अपने को स्वअध्ययन एवं अभ्यास से विकसित करते हुए H.R.D, Organizational Behaviour, Management, E-Governance इत्यादि क्षेत्र के विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारम्भ किया। आतिथि तक प्रशिक्षण प्रदान करने की विधा एवं शैली को सभी प्रशिक्षार्थी अधिकारियों द्वारा उच्च श्रेणी के रूप में आंकलित किया जाता रहा है।

प्रशिक्षण निर्माण एवं निर्देशन में भूमिका

अकादमी में तीन दशकों में समय-समय पर तैनात रहे निदेशक/महानिदेशक महोदयों द्वारा क्षमता को पहचानते हुए जो विवास दिखाया गया उसके चलते निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण व आयोजन का दायित्व अकादमी द्वारा सौंपा गया। इस क्रम में तत्कालीन उत्तर प्रदेश व वर्तमान उत्तराखण्ड की अकादमी के रूप में समय-समय पर आयोजित हुए अनेकों दीर्घकालिक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम; पी0सी0एस0 कार्यकारी शाखा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यक्रम निदेशक के रूप में दायित्वों को सम्पादित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्साधिकारियों, अभियन्ताओं, समीक्षा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारी (जू0डी0) इत्यादि सेवाओं हेतु आयोजित अनेक सेवा प्रवेश एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भी कार्यक्रम निदेशक का दायित्व संभालने का अवसर मिला है। इसके चलते अकादमी इतिहास में सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यक्रम निदेशक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से नवनियुक्त अधिकारियों को शासकीय कार्य प्रणाली, नियमों के परिचय के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास का अवसर दिया जाता है जिससे वे श्रेष्ठ प्रशासन प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन भली-भांति कर सकें।

उत्तर प्रदेश की अवधि में पी0सी0एस0 कार्यकारी शाखा के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में ग्राम्य अध्ययन एवं जिला प्रशिक्षण के दौरान अकादमी से नोडल अधिकारी के रूप में

कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ जिसमें अध्ययन स्थल का भ्रमण कर प्रशिक्षु अधिकारी की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में योगदान दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समस्त ए0 टी0 आई0 के महानिदेशक/निदेशकों की दो कॉन्फ्रेंस में अकादमी नैनीताल का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसमें नवनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जिला एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करने में योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त अपनी कार्यअवधि में आतिथि तक अनेक इन-सर्विस थीम बेस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा Computer Application, Computer for Analysis & Decision Making, E-governance, Digital India, Direct Trainer Skills, Design of Training, Mentoring skill, Management of Training, Evaluation of Training, Orientation Training for Legal Issues, Orientation Training for legal Officers, Executive Development Programme इत्यादि के प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण एवं निर्देशन से प्रदेश के कार्मिकों की क्षमता संवर्धन में अपना योगदान दिया गया।

परियोजना आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भूमिका

भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत कटिंग एज पर कार्य करने वाले जिला स्तरीय कार्मिकों हेतु उत्तराखण्ड के समस्त जिलों में दो-दो, बारह दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रमों का सफलापूर्वक संचालन कराया गया। अकादमी में आयोजित हुए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने अकादमी की टीमों को नेतृत्व प्रदान कर सफलतापूर्वक सम्पादित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी की पहचान एवं स्थान को सशक्त किया गया। भारत सरकार की संस्था Institute of Applied Manpower and Research, New Delhi के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों, प्रसार भारती तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के सफल आयोजन से अकादमी की गरिमा एवं मान्यता को स्थापित करने में योगदान दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा दे"ी भर के विभिन्न प्र"ीक्षण संस्थानों से कुल 08 लोगों का एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया जिसमें चयनित हो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्र"ासन अकादमी मसूरी एवं सिविल सर्विस कॉलेज, लंदन में टोटल क्वालिटी मैन्जमेंट में प्र"ीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिविल सर्विस कॉलेज, लंदन के तत्वाधान में आयोजित प्र"ीक्षण के अंतर्गत ब्रिटेन के कई स्थलों यथा लंदन, एडिनब्रा-स्कॉटलैण्ड व कार्डिफ-वेल्स की स्टडी टूर कर उच्च गुणवत्ता की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का अवसर मिला। उपरोक्त प्र"ीक्षण प"चात् अकादमी में प्र"ीक्षण एवं अन्य सेवाओं में गुणवत्ता विकास में योगदान दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अकादमी में तैनाती के दौरान शासकीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं कार्य"ालाओं में प्रतिभाग करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ जिसमें LBSNAA Mussoorie, IIM Bangalore, IIPA New Delhi, ISTM New Delhi, HCM RIPA Jaipur, HIPA Gurgaon, ISTD इत्यादि मुख्यतः हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्राप्त हुए अनुभवों का लाभ व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ अकादमी को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से निःसंदेह प्राप्त हुआ है।

अन्य संस्थाओं में योगदान

अकादमी में प्राप्त किये गये इस लम्बे अनुभव एवं ज्ञान तथा अपने कार्यों से बनी पहचान के कारण विभिन्न प्रदे"ी सरकारों के अन्य शासकीय प्र"ीक्षण संस्थानों व निजी संस्थानों सेवा प्रदान करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। जिसके क्रम में राज्य के भीतर स्थापित विभिन्न प्र"ीक्षण संस्थानों यथा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली; उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर; राजस्व पुलिस एवं भू-लेख सर्वेक्षण प्र"ीक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में अतिथि वार्ताकार के रूप में योगदान दिया गया। इसके अतिरिक्त दे"ी के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अतिथि वार्ताकार के रूप में आमंत्रण प्राप्त हुये। जो न केवल मेरे

को व्यावसायिक तौर पर विकसित होने में सहायक बना बल्कि प्रीक्षण के भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभवों से ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कराते हुए गुणवत्ता विकास में सहायक हुआ है।

प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन

प्रीक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त समय-समय पर अकादमी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दिखाये गये विवास के कारण अकादमी के विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर भी प्राप्त होता रहा है। अकादमी के विभिन्न अंग यथा परिसर, छात्रावास, मैस, वाहन, क्रीड़ा, स्टोर, कम्प्यूटर, स्वागत एवं प्रीक्षण समन्वय यूनिट के प्रभारी अधिकारी के रूप में योगदान देकर प्रीक्षणार्थियों हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत रहा गया।

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर के रूप में वर्ष 1994 में अकादमी में प्रथम कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना सफलतापूर्वक न केवल स्थापित करायी गयी बल्कि विभिन्न संकाय एवं पटलों पर कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित कर कम्प्यूटर प्रयोग कल्चर को स्थापित किया गया। इस लक्ष्य को सफल बनाने हेतु अकादमी संकाय एवं कार्मिकों हेतु कम्प्यूटर प्रीक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। चरणबद्ध तरीके से अकादमी के पटलों के साथ प्रीक्षणार्थी अधिकारियों आदि हेतु कम्प्यूटर सुविधा अकादमी छात्रावास एवं अतिथि गृह के समस्त कक्षों में उपलब्ध करायी गयी। समय के साथ परिवर्तित होती टेक्नोलॉजी के साथ अकादमी में विभिन्न स्थलों पर स्थापित कम्प्यूटर व अन्य तकनीकी उपकरणों को निरन्तर उच्चकृत कराया जाता रहा है जिससे कि नवीनतम तकनीकी प्रीक्षकों को उपलब्ध हो सके।

इसी क्रम में अकादमी को इन्टरनेट सुविधा वाले कार्यालय/संस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में वर्ष 1997 में वी-सेट के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी को संचालित करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना करायी गयी। जिसे प्राप्त करने के पश्चात् प्रीक्षण कार्यक्रम के आयोजन एवं कम्युनिकेशन में इसका प्रभावी प्रयोग किया गया। अन्य प्रीक्षण संस्थानों के साथ ऑनलाईन जुड़ने हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा से भी अकादमी को सुसज्जित कराया गया। अकादमी में विशेष रूप से पुस्तकालय एवं स्टोर से सम्बन्धित सूचनाओं

के संग्रह एवं प्रयोग हेतु सॉफ्टवेयर के चयन एवं स्थापना में भी योगदान दिया गया है जिसके कारण दोनों ही पटलों के कार्य में सुगमता एवं गुणवत्ता प्राप्त हुई।

अकादमी की आईटी सुविधाओं के रखरखाव एवं उच्चीकरण का दायित्व प्राप्त होने के कारण प्रभारी अधिकारी के रूप में समय-समय पर भौतिक रूप से संवर्धन के प्रयास जारी रहते हैं। जिसके तहत अकादमी के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग उपकरण, सीसीटीवी व्यवस्था, लोकल एरिया नेटवर्क, कम्प्यूटर लैब, सर्वर एवं इन्टरनेट व्यवस्था के उच्चीकरण एवं उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाता है। अकादमी की वेबसाइट के रखरखाव एवं उपलब्ध सूचनाओं को अद्यतन रखने में तैनात टीम को नेतृत्व प्रदान कर कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

व्यवस्थाओं को बेहतर करने व विस्तार हेतु निरन्तर प्रयास किये गये जिनमें अकादमी निदेशक कार्यालय, छात्रावास, अतिथि गृह व स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का सुदृढीकरण, ओपन एयर थियेटर, इन्टरलॉकिंग पाथवे, कवरड शेड-पाथ, कैफे, अग्नि सुरक्षा हाइड्रेंट, 50 हजार ली. का अग्नि सुरक्षा वाटर टैंक, क्रिकेट पिच का आदि का निर्माण सम्पादित कराया गया। इसके अतिरिक्त चर्चा कक्षों, लॉन्ज, मैस व कार्यालय कक्षों का उच्चीकरण व वातानुकूलन, मैस का विस्तार, भवनों पर आकाशीय बिजली सुरक्षा उपकरण की स्थापना, भवनों पर एलईडी लाइट सौन्दर्यीकरण, परिसर में सोलर लाइट, विभिन्न भवनों एवं अतिथि गृह के कक्षों के नामों के प्लेकार्ड तैयार कर स्थापित कराये गये। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अंतर्गत ऑल वेदर स्पोर्ट्स कोर्ट, अतिरिक्त बैडमिंटन हॉल एवं प्रेक्षागृह हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर से अनुमोदित कराने में प्रभारी अधिकारी के रूप में योगदान दिया गया।

अकादमी के परिसर में हरेला के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण अभियान सम्पादित कराने के साथ परिसर में उपलब्ध वृक्षों व पौधों की सूचना सम्बन्धित प्लेकार्ड की स्थापना में योगदान दिया गया। अकादमी में तैनात रहे विभिन्न निदेशकों एवं महानिदेशकों से सम्बन्धित एक चित्र गैलेरी को भी तैयार किया गया। अकादमी के विभिन्न स्थलों पर एक साथ सूचना प्रसारित एवं चित्रों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से साइनेज व्यवस्था को स्थापित कराया गया।

प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण समन्वय यूनिट के रूप में अकादमी के प्रशिक्षण गतिविधियों को निर्धारित करने, सम्पादित कराने, प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के प्रकाशन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। प्रभारी अधिकारी क्रीड़ा के रूप में अकादमी में जिम की स्थापना तथा अकादमी स्टोर के कम्प्यूटराइजेशन की दिशा में भी योगदान दिया गया।

मिशन कर्मयोगी एवं ई-लर्निंग हेतु प्रयास

भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी परियोजना को उत्तराखण्ड में संचालित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा अकादमी को नोडल एजेंसी नामित किया गया जिसके क्रम में इस परियोजना से जुड़ने का अवसर मिला। आतिथि तक इस दिशा में प्रदेश के विभिन्न विभागों को मिशन कर्मयोगी के i-GOT Platform पर ऑनबोर्ड कराने, 10 विभागों के टी.एन.ए. की प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित करने हेतु एजेन्सियों के चिन्हीकरण हेतु योगदान दिया गया। ई-लर्निंग की दिशा में एक पृथक् प्रयास करते हुए NeGD के Platform पर Learning Management System (LMS) को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है, जिसमें आतिथि तक 148 प्रशिक्षण सामग्री उपयोगकर्ताओं हेतु उपलब्ध हैं।

विभिन्न अध्ययन कार्य

अकादमी में विभिन्न शोध एवं अध्ययन गतिविधियों में भी योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ मुख्य शोध एवं अध्ययनों में वर्ष 1999 में Working Papers - Information Technology for Improved Governance; वर्ष 1999 में संपूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ का सुदृढीकरण; 2000 में श्रेष्ठ प्रशासन के लिये विनियमन; वर्ष 2010 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण से कार्यालयों/विभागों के कार्मिकों की कार्यदक्षता में सुधार के कारण राज्य सरकार को प्राप्त लाभों की मौद्रिक गणना अध्ययन; राजस्व विभाग के कार्मिकों के कम्प्यूटर व देवभूमि सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण से राज्य सरकार को प्राप्त लाभों की मौद्रिक गणना अध्ययन; वर्ष 2011 में तृतीय राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड हेतु ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशियों के उपभोग की स्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के कारण तथा

स्थितियों की समीक्षा एवं वर्ष 2014 में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 की प्रभाविता का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनसे जुड़कर काम करने पर शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु अवसर प्राप्त हुआ जिसके कारण परिस्थितियों को देखने एवं परखने के नजरिये में परिवर्तन आया।

एडवेंचर गतिविधियों में नेतृत्व

अकादमी में दीर्घकालीन आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सप्ताह के ट्रेकिंग व एडवेंचर गतिविधियों में प्रशिक्षुओं के दल का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें अलग-अलग प्रशिक्षुओं के दल को पिंडारी ग्लोबल, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुण्ड साहिब, नैना पीक इत्यादि की ट्रेकिंग समूह को लीड किया गया। अकादमी इतिहास में पहली बार 1994 में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं के एक दल का एक सप्ताह के स्कींग ट्रेनिंग हेतु औली में नेतृत्व करते हुए कार्यक्रम संपादित कराया गया। आधारभूत एवं सेवा प्रवर्गा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को रॉक क्लाइम्बिंग, रेपलिंग, वैली/रिवर क्रॉसिंग गतिविधियों में भी नेतृत्व प्रदान करते हुए प्रतिभाग कराया गया।

अभिलेखिकरण के प्रयास

आरम्भिक कार्यकाल में अकादमी की विभिन्न गतिविधियों को अभिलेखित किये जाने की कोई परंपरा नहीं थी। डॉ० आर० एस० टोलिया के निदेशक पद पर आसीन होने के पश्चात् इस परंपरा को प्रारम्भ किया गया कि न केवल समस्त गतिविधियों के सम्पादन पश्चात् उससे सम्बन्धित एक लिखित रिपोर्ट संरक्षित की जाये बल्कि गतिविधि से सम्बन्धित छायाचित्रों का भी संग्रह रखा जाये। इस परंपरा ने अपने कार्यों को लिपिबद्ध करने का एक कौशल विकसित किया तथा संरक्षित अभिलेखों से अकादमी का एक इतिहास भी बनना शुरू हुआ। वर्ष 1996 के पश्चात् मेरे द्वारा आयोजित किये गये समस्त कार्यक्रमों/गतिविधियों को लिपिबद्ध कर अकादमी पुस्तकालय में संरक्षित करने का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार ये संरक्षित अभिलेख नई पीढ़ी व अकादमी में तैनात होने वाले अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में

उपलब्ध हैं। अकादमी पुस्तकालय हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित 29 पुस्तकों को डोनेट कर अकादमी पुस्तकालय को समृद्ध करने में योगदान दिया गया।

सी0डी0एस0 एवं सी0जी0जी0 संस्था में योगदान

अकादमी के अंतर्गत वर्ष 1994 में स्थापित Centre for Development Studies में भी योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें सबसे पहले Project Management Unit: Information Technology को स्थापित करते हुए समन्वयक की भूमिका का निर्वहन किया गया। इस यूनिट के द्वारा Centre for Development Studies का प्रथम Paid कोर्स आयोजित किया गया। जिसकी सफलता के पश्चात् निरन्तर इस यूनिट द्वारा डिमांड आधारित Paid कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं हेतु आयोजित की गयी। Centre for Development Studies के अंतर्गत ही वर्ल्ड बैंक परियोजना – जे0 एफ0 एम0 व स्वजल में तथा यू0 एस0 ए0 आई0 डी0 परियोजना State Innovations in Family Planning Services Project Agency (SIFPSA) के PMU-Health and Family Welfare में आई0टी0 सलाहकार के रूप में योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ।

वर्तमान में अकादमी के अंतर्गत स्थापित Centre for Good Governance में ई-गवर्नेन्स यूनिट के समन्वयक के रूप में योगदान देने का अवसर प्राप्त है। जिस यूनिट के माध्यम से IIPA, New Delhi व ITDA, Dehradun इत्यादि संस्थाओं के लिये मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है जिनमें ई-गवर्नेन्स, डिजिटल इंडिया, डेटा विजुलाईजे"न, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

कोविड यग के दायित्व

वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड प्रकोप की अवधि में अकादमी दे"ा की पहली ऐसी प्रशिक्षण संस्था रही जिसने लॉकडाउन के पश्चात् ऑन-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रारम्भ किया जिसमें सम्पूर्ण अकादमी परिसर को प्रतिभागियों हेतु सुरक्षित बनाने की दि"ा में

विशिष प्रयास किये गये। प्रभारी अधिकारी परिसर का दायित्व होने के कारण संस्थान के अन्दर आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर छात्रावास, चर्चा कक्ष व मैस इत्यादि के सम्पूर्ण सैनिटाईजेशन को सफलतापूर्वक सम्पादित कराया गया तथा कोविड सुरक्षा से सम्बन्धित सूचना/स्लोगन के प्लेकार्ड तैयार कर सम्पूर्ण कैम्पस में स्थापित कराये गये। इस युग हेतु भिन्न प्रकार की सोच, नीति निर्धारण, त्रुटि रहित क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग की आवश्यकता रही। यह कार्यकाल चुनौती भरा रहा परन्तु अकादमी कार्मिकों एवं प्रतिभागियों के सहयोग से इसका सामना सुनिश्चित हो पाया।

गौरव की अनुभूति

अकादमी की सेवा करते हुए बहुत प्रतिष्ठा एवं सम्मान की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में प्रशासनिक अमले में अपने प्रशिक्षण, अनुशासन, समयबद्धता, कार्यकुशलता इत्यादि गुणों के कारण बनी पहचान से आज भी योग्यता से अधिक सम्मान एवं आदर प्राप्त हो रहा है। जिसके लिए ईश्वर एवं अकादमी दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना दायित्व बनता है। तीन दशक की सेवा में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के सभी स्तरों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनमें से कुछ को शीर्षस्थ पदों यथा प्रदेश के मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त आदि पर आसीन होने से गौरव की अनुभूति होती है।

प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग

अपने तीन दशक के कार्यकाल में अनेक उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं महानुभावों से मिलने एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनमें मुख्यतः श्री एस0 पी0 गौड़, डॉ0 आर0 एस0 टोलिया, श्री राकेश शर्मा, श्री एस0 राजू, श्री अजय जोशी व श्री बी0 पी0 पाण्डेय हैं। भिन्न-भिन्न अधिकारियों के साथ के मार्गदर्शन में कार्य करने से विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियों एवं नेतृत्व शैली का अनुभव हुआ जिसने व्यक्तित्व विकास एवं कार्यशैली में गुणात्मक विकास में सहायता प्रदान की।

इन वर्षों में अपने दायित्वों का निर्वहन सहजता एवं सफलतापूर्वक सम्पादित करने में अकादमी के मेरे सभी सम्मानित संकाय साथी-गण व अकादमी के कार्मिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सेवा प्रारम्भ करते समय तत्कालीन संकाय श्री एल०एम० पन्त, श्री एस०के० महे"वरी, श्री नि"ीथ कुमार, श्री रमे"ा अग्रवाल, डॉ० एन०एल० श्रीवास्तव, डॉ० सन्तोष कुमार का मार्गदर्"न एवं सहयोग मुझे इस अकादमी के लिए स"ाक्त नींव तैयार करने में सहयोगी रहा। तत्प"चात् संकाय के रूप में तैनात हुए अन्य साथी यथा श्री राजीव काण्डपाल, श्री राजीव शाह, डॉ० आर०के० पाण्डे, श्रीमती र"िम पाण्डे आदि के साथ एक टीम के रूप में विकसित होकर कार्य करने का सुखद अनुभव प्राप्त हुआ।

समय-समय पर अकादमी के विभिन्न पटलों पर तैनात रहे कार्मिकों के सहयोग के बिना यह सफरनामा अधूरा ही रह जाता। इस क्रम में कुछ कार्मिकों यथा श्री जे०एस० रावत, श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, श्री एच०सी० जो"ी, श्री खीम सिंह बिष्ट, श्री महे"ा चन्द्र सिंह बिष्ट, श्रीमती पूर्णिमा वर्मा, श्री महे"ा आर्या, श्री मुके"ा चौधरी, श्री जी०एस० मेहता, श्री सहादत अली अंसारी, श्री नरेन्द्र थिपोला, श्री भगवत सिंह नेगी, श्रीमती शांति पन्त, श्री रमे"ा राम, श्री एच०सी० कपिल, श्री रमे"ा लाल, श्री हरेन्द्र सिंह पपोला, श्री बद्री लाल इत्यादि ने न केवल अधोहस्ताक्षरी को समय-समय पर कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान की गयी बल्कि शासकीय कार्यप्रणाली को जानने व समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकादमी के अन्य सभी कार्मिकों से भी हमें"ा एक शालीन एवं सम्मान का व्यवहार प्राप्त हुआ। अकादमी कार्मिकों के मध्य जिस प्रकार की कार्य"ौली इस संस्थान में देखने को प्राप्त हुई उसकी प्र"ांसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। जिस प्रकार के समर्पित, अनु"ासित, कार्यकु"ाल एवं लग्न"ील कार्मिक इस संस्थान में तैनात रहे उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि सम्पूर्ण भारत से आने वाले प्रतिभागियों के मध्य अत्यन्त उच्च कोटि की छवि बनाकर इस अकादमी की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाये।

अकादमी नैनीताल में योगदान के समय से ही परिवार में माँ का साथ एवं सानिध्य घर पर मिलता रहा। अकादमी की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों का समय से निर्वहन हो सके इसका एक श्रेय माँ को भी जाता है क्योंकि उनके द्वारा भी अकादमी की अपेक्षाओं के अनुसार

योगदान दे सकने हेतु घर पर सकारात्मक वातावरण देने तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

अतिथि रिसोर्स पर्सन का सहयोग

अकादमी के विभिन्न पदों के सापेक्ष होने वाले संकाय अधिकारियों की हमें"ा से ही कमी महसूस की गयी। जिसके कारण अनेक प्री"िक्षण कार्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष से विषय-वि"ीषज्ञों को अतिथि वार्ताकार के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। अपने प्री"िक्षण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के दौरान अनेक ऐसे व्यक्ति रहे जिनके द्वारा हमारी छोटे से अनुरोध को स्वीकार कर प्री"िक्षण कार्यक्रमों में अपनी वार्ताओं से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। जिसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अकादमी द्वारा अतिथि संकाय सदस्य से सम्बन्धित एक डाटाबेस तैयार किया गया है। जिसे समय के साथ अद्यतन करने का कार्य किया जाता है।

प्रतिभागियों द्वारा मूल्यांकन

अपने कार्यकाल के दौरान सैकड़ों की संख्या में आयोजित हुए प्री"िक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों की संख्या में प्रतिभागियों के साथ अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने का जो अवसर इस अकादमी द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें पूर्ण लगन, निष्ठा एवं आनन्द के साथ योगदान देने का प्रयास रहा है, और शायद उसी का परिणाम रहा कि प्रतिभागियों द्वारा प्री"िक्षण सत्रों को अत्यन्त प्रभावी एवं उपयोगी पाते हुए मूल्यांकन किया गया। इन मूल्यांकनों के प्रमाण अकादमी पुस्तकालय में संचित की गयी कार्यक्रम निदे"ाक रिपोर्ट हैं।

भविष्य की संकल्पना

जीवन का एक लम्बा भाग इस अकादमी को समर्पित किया है। अतः इस अकादमी से एक लगाव, अपनत्व एवं सर्मपण का भाव बन गया है। जिसके कारण इस अकादमी को प्रगति करते हुए एवं नई ऊँचाईयों पर स्थापित होते हुए देखने की प्रबल इच्छा है। आगामी समय में इस इच्छा की प्रतिपूर्ति हेतु दृढ़ संकल्प के साथ नए-नए क्षेत्रों में प्री"िक्षण मॉड्यूल के विकास,

समय के साथ बदलती परिस्थितियों में प्रशिक्षण को ऑनलाईन माध्यम से उपयोगकर्ताओं हेतु हर-समय, हर-जगह उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर ई-लर्निंग सामग्री तैयार करने की दिशा में प्रयास किये जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थाओं एवं विविद्यालयों के साथ अकादमी की नेटवर्किंग को सशक्त करने की दिशा में अनिवार्य रूप से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे देश में उपलब्ध उत्कृष्ट मानव संसाधन, शोध एवं अध्ययन का लाभ अकादमी के प्रशिक्षुओं को प्राप्त हो सके। अकादमी की उपलब्ध संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग हेतु देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों/विभागों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर प्रदान करना तथा अकादमी के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश/विदेश में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रशासन सम्बन्धी उदाहरणों के अध्ययन हेतु कार्यक्रमों को निर्धारित कर आयोजित कराना एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है।

सुझाव एवं अपेक्षा

अकादमी की आवश्यकता एवं भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस विचार एवं सुझाव को साझा करना चाहूँगा कि अकादमी के संकाय पदों में दो पृथक्-पृथक् धारार्य व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक अकादमी का स्थाई काडर तथा दूसरा डेप्यूटी/ट्रांसफर के आधार पर तैनाती हेतु हो। स्थाई काडर से अकादमी की संस्थागत स्मृति (institutional memory) को बनाये रखा जा सकता है वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी/ट्रांसफर के आधार पर आने वाले अधिकारी फील्ड के अनुभवों से प्रतिभागियों को लाभान्वित कर सकते हैं। शासन द्वारा अकादमी में संकाय पदों पर योग्य एवं इच्छुक कार्मिकों को ही तैनात किया जाये तथा विभिन्न विभागों द्वारा भी प्रशिक्षण को वरीयता देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग्य एवं प्रतिभाशाली कार्मिकों प्रतिभाग कराया जाये जो अकादमी से नई दिशा प्राप्त कर उसे धरातल पर उतराने में दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ योगदान दे सकें।

समय के साथ भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है परन्तु मानव संसाधन की कमी के कारण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। संविदा अथवा आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किये जा रहे कार्मिकों में संस्थान के प्रति वो निष्ठा एवं लगाव देखने को नहीं मिलता है जो नियमित कार्मिकों में देखा जाता था।

आशा एवं प्रार्थना

आशा करता हूँ कि गत तीस वर्षों में अकादमी की प्रगति एवं प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से विकसित होते देखा है, आगामी दौर में भी सभी के योगदान से विकास के पथ पर निरंतर बढ़ते हुए प्रदेश एवं देश के शासकीय तंत्र में योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को समय की आवश्यकता के अनुरूप उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए एक गुरुकुल के रूप में अपने अस्तित्व के साथ न्याय कर पायेगी।

देवभूमि उत्तराखण्ड में नैना देवी के स्थल पर स्थापित इस अकादमी एवं इससे जुड़े समस्त लोगों पर नैना देवी की कृपा बनी रहे तथा सभी लोग अपनी सेवाओं से इस देवभूमि को उन्नत एवं उज्ज्वल राज्य बनाने में अपने योगदान दे सकें, ऐसी प्रार्थना रहेगी।

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में एक दशक

दिनेश कुमार राणा, उप निदेशक (वित्त)

डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

डॉ० आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल— दिनांक 15.09.2011 को सहायक निदेशक (वित्त) के रूप में अकादमी में कार्यभार ग्रहण किया गया। अकादमी के कार्यालय आदेश/कार्य विभाजन में अधोहस्ताक्षरी को संयुक्त निदेशक (वित्त) के साथ लिंक अधिकारी के रूप में कार्य दायित्व प्रदान किये गये। कुछ समयान्तराल बाद अकादमी में संचालित सोसायटी सी.जी.जी. के वित्त नियंत्रक का कार्य दिया गया जो कि संयुक्त निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में सम्पादित किये जाने थे।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम— तदक्रम में शासनादेश के क्रम में सहायक निदेशक (वित्त) के दायित्वों के साथ-साथ शिक्षा विभाग, भीमताल में वित्त अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया जिसको भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। वर्तमान कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप में 'वित्त नियंत्रक' कुमाऊँ मण्डल विकास निगम का कार्य किया गया। वित्त से संबंधित सभी मुद्दों पर एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिए गए कार्यों को समयबद्ध एवं सफल तरीके से सम्पन्न किया गया। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में लम्बित चले आ रहे पिछले वित्तीय वर्षों के ऑडिट कार्यों को अद्यतन कराने में सम्पूर्ण सामर्थ्य से प्रयास किये गये। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में कार्मिकों के ACR, पत्रावली/पुस्तिकाओं को अद्यतन एवं ठीक करवाया गया तथा कार्मिकों के लम्बित पड़े पदोन्नति प्रकरणों को सम्पन्न कराया गया। ACR पुस्तिकाओं को जो पैटर्न चला आ रहा था वह त्रुटिपूर्ण था जिसको नियमानुसार संकलित कराने में पर्यवेक्षक का कार्य किया गया, ताकि भविष्य में कार्मिकों की

पदोन्नति में विलम्ब न होने पाए। इस कार्य हेतु तत्कालीन प्रबंध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की भूरी-भूरी प्रशंसा भी गयी थी।

झील विकास प्राधिकरण— कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त कार्य/दायित्वों के साथ-साथ मुख्य वित्त अधिकारी LDA (झील विकास प्राधिकरण) के कार्य/दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। झील विकास प्राधिकरण में रहते हुए वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार कर बोर्ड ऑफ गर्वनर से उसको अनुमोदित कराया गया तथा वित्त से संबंधित समस्त मामलों यथा वेतन, पेंशन आदि के अलावा क्रय संबंधी प्रक्रियाओं में सफल भागीदारी की गयी। झील विकास प्राधिकरण सम्प्रति जिला विकास प्राधिकरण में समय-समय पर तीन कलावधियों में कार्य व दायित्वों का निर्वहन किया गया। इस समय पर प्राधिकरण द्वारा अपनी वृहद परियोजना सूखाताल कृत्रिम झील निर्माण के लेखा संबंधी कार्यों के सम्पादन में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन किया गया।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण— उक्त कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक की भी अतिरिक्त भूमिका का निर्वहन किया गया, जिला विधिक प्राधिकरणों को वित्तीय आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी एवं अधिष्ठान से जुड़े समस्त सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में शासन के द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया, कार्मिकों के पदोन्नति प्रकरणों में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय— सितम्बर 2015 में अधोहस्ताक्षरी की पदोन्नति शासन द्वारा वित्त अधिकारी से वरिष्ठ वित्त अधिकारी पर की गयी, सम्प्रति अकादमी में अधोहस्ताक्षरी का पदनाम सहायक निदेशक (वित्त) से उप निदेशक (वित्त) के रूप में परिवर्तित हो गया तथा उपनिदेशक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया गया। कालान्तर में 2019 में अतिरिक्त प्रभार के रूप में अधोहस्ताक्षरी को उप निदेशक (वित्त), अकादमी के अलावा वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय का दायित्व सौंपा गया। वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के दायित्वों के रूप में FC (वित्तीय समिति) की बैठकों में सदस्य सचिव के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिभाग किया गया तथा इसी क्रम में EC (एकजीक्यूटिव कमेटी) की बैठक में सदस्य वित्त के रूप में प्रतिभाग किया एवं वि.वि. में आने वाले वित्तीय प्रकरणों में अपनी भूमिका

का निर्वहन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय में अवसंरचनात्मक कार्यों में निभाई गयी भूमिका उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालय के बजट संबंधी प्रकरणों को अद्यतन किया गया।

साथ ही साथ रजिस्ट्रार, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के साथ साझा दायित्वों का निर्वहन करते हुए VC महोदय के निर्देशानुसार दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन सम्पन्न करवाया गया। विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत दैनिक कार्मिकों के बारे में एक सुझाव VC महोदय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया गया, जिसके लिये तत्कालीन VC महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी की मुक्त कंठ से सराहना की गयी।

अकादमी में लम्बे समय से कार्यरत रहने के दौरान नियमित वित्तीय प्रकरणों यथा सेवा संबंधी प्रकरणों, आय-व्यय का सही समय पर नियमानुसार सम्पादन कराया, क्रय के समस्त प्रकरणों में उ0 अधि0 नियमावली 2017 के अनुसार एक सदस्यीय समिति के रूप में एवं तीन सदस्यीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता रहा है।

उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति तिथि से लेकर आतिथि तक लेखा संवर्ग का कोई कार्मिक अकादमी में तैनात नहीं है, उक्त सभी प्रकरणों पर स्वविवेक एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशन में समस्त कार्यों का सम्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जा रहा है। सन् 2002-2010 के मध्ये निदेशक खाते में अनिस्तारित पड़ी धनराशि जिसमें ऑडिट का पैरा भी संचित हुआ था, को उत्तराखण्ड शासन से एवं समय-समय पर डी.ओ.पी.टी. भारत सरकार से पत्राचार एवं वार्ता के माध्यम से रु. 44.71 (चौवालीस लाख इकहत्तर हजार) की धनराशि को डीओपीटी को समर्पित की गयी है एवं आतिथि में निदेशक खाता अद्यतन हो चुका है जिसको बंद करने की कार्यवाही की जा रही है।

अकादमी में उपनिदेशक के पद पर रहते हुए अकादमी में संचालित सोसायटी सी.जी. जी. के पदेन वित्त नियंत्रक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में कतिपय कारणों से सीजीजी पर टैक्स देयता का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसको कि सचिव सीजीजी एवं विशेष रूप से सीईओ महोदय के दूरदर्शिता व विशेषज्ञ निर्णयशीलता के कारण प्रकरण समाप्त हो चुका है।

अकादमी में संचालित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी.एम.सी.) को भी उत्तराखण्ड शासन से निदेशक/महानिदेशक के निर्वहन पर बजट की प्राप्ति होती है जिसको ससमय नियमानुसार व्यय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता रहा है। सेवा संबंधी प्रकरण यथा संविदा /साक्षात्कार समिति के सदस्य, संविदा किये जाने संबंधी प्रकरणों पर नजर रखी जाती है। कतिपय नियम विरुद्ध पदोन्नति इत्यादि पर भी अपना पक्ष मजबूती से रखा गया है जिस पर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही भी हुई है।

अकादमी मैस, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों में से शामिल प्रतिभागियों की एक साझी समिति के द्वारा संचालित किया जाता है, में बचत रूप में उपलब्ध धनराशि का राज्य सरकार द्वारा प्रेषित ऑडिट टीम से ऑडिट कराया गया जो कि पहली बार था, जिसमें प्राप्त बिंदुओं का जवाब ऑनलाइन प्रेषित किया गया है।

इसके अलावा संकाय के रूप में अकादमी में संचालित किये जाने वाले सेवा-प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल संचालन, डीओपीटी से प्रदत्त कार्यक्रमों का संचालन, मांग आधारित वित्तीय एवं कार्यालय प्रबंधन संबंधित कार्यक्रमों का सफल संचालन, कार्यक्रम रिपोर्ट का निर्माण एवं प्रेषण का कार्य, उक्त कार्यक्रमों में वित्तीय विषयों पर वाताएँ प्रदान करना एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश/वित्तीय राय प्रदान किया जाना महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क कर खातों के बारे में रिकसिलेशन रिपोर्ट का प्रेषण एवं तालमेल स्थापित करना।

जिला कोषागार— उक्त के अलावा 12.10.2021 से शासन के आदेश के क्रम में मूल तैनाती मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में अकादमी में उपनिदेशक वित्त के रूप में कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। मुख्य कोषाधिकारी के रूप में वित्तीय, प्रशासन एवं प्रबंधन के रूप में कोषागार, हल्द्वानी का प्रशासनिक नियंत्रक एवं उपकोषागार, कालाढूंगी, रामनगर, धारी, कोश्यां कुटोली, बेतालघाट, के समस्त उत्तरदायित्वों का नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा रहा है। मुख्य कोषाधिकारी रहते हुए जनपद के प्रमुख वित्तीय प्रकरणों में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। 2022 को विधानसभा चुनाव में व्यय पर्यवेक्षक (Expenditure Nodal) की भूमिका का सफल निर्वहन एवं लेखा का परीक्षण किया गया है।

अभिनव व्यावसायिक यात्रा— डा0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, मई 2019 से फरवरी 2023

पूनम पाठक तत्कालीन उप निदेशक,
डा0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

सम्प्रति— जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्यालय, निदेशालय, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।

जिला पंचायत राज अधिकारी बागेश्वर के रूप में लगभग 03 वर्ष 10 माह के सफल कार्यकाल एवं लोक सभा निर्वाचन, 2019 में नोडल अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय बागेश्वर की सार्थक भूमिका निर्वहन के पश्चात् डा0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में 27 फरवरी, 2019 को द्वितीय कार्यकाल हेतु योगदान किया गया।

अकादमी में अपने कार्यकाल के दौरान अन्य सामान्य कार्यों जैसे नियमित सेवा प्रवेश, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा के उत्तराखण्ड कैडर के प्रशिक्षु अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा अनुरोधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यक्रम निदेशक/कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट गतिविधियों का संचालन किया गया।

1. प्रशिक्षण समन्वय इकाई की प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक के रूप में कार्य—

- प्रशिक्षण समन्वय इकाई की प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षण कैलेण्डर में जनपद में किये गये कार्यानुभवों की समावेशित करते हुए ऐसे विषयों का अधिक से अधिक समावेश करने का प्रयास किया गया जिसकी

आवश्यकता दैनिक कार्यकरण में अधिकारियों को निरंतर पड़ती रहती है। साथ ही जिनमें सुग्राह्य साहित्य सुलभ नहीं है। इस कार्यक्रमों में देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों यथा— National Law School Bangalore, All India Institute of Medical Science, New Delhi, Lal Bahadur National Academy of Administration, Mussoorie, Indian Institute of Public Administration New Delhi, National Institute of Criminology and forensic Science, New Delhi आदि से अतिथि वार्ताकारों को विभिन्न सत्रों हेतु आमंत्रित किया गया। अकादमी द्वारा ऐसे अधिकारियों हेतु जो कि निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए उनके लिए प्रथम बार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेवा निवृत्ति के पश्चात् मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव आदि विशिष्ट विषयों को सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवा का अधिकार, सिटीजन चार्टर, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

- अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं अवर अभियन्ता सिंचाई विभाग के बैच हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये सिरे से डिजाइन किया गया।
- आलोच्य अवधि में ही प्रशिक्षण समन्वय इकाई के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुये अकादमी द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं से संकाय आदान प्रदान तथा शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के क्रम में MoU हस्ताक्षरित करने में विशेष योगदान दिया गया:
 1. Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
 2. G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora.
 3. Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee.

4. Harish Chandra Mathur Rajasthan Institute of Public Administration, Jaipur.
5. Jammu & Kashmir Institute of Management, Public Administration and Rural Development.
6. National Institute of Communication finance, (NICF), New Delhi.
7. Indian Institute of Management, Kashipur.
8. पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, देहरादून।

2. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्मिकों का आरम्भ –

समन्वयक, प्रशिक्षण इकाई के रूप में राज्य सरकार के वित्त पोषण द्वारा Training Programme on Medico Legal Issues प्रस्तावित किया गया तथा कार्यक्रम निदेशक के रूप में उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक निर्देशन भी किया गया। सन्दर्भित कार्यक्रम की परिकल्पना अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित चिकित्साधिकारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन कार्यक्रम तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चिकित्साधिकारियों से उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर चर्चा के दौरान की गयी। Training Programme on Medico Legal Issues में चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार राज्य के वित्त पोषण से मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रतिभागियों की उपस्थिति अत्यन्त उत्साहवर्धक रही कुल 44 अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम को अवशेष अधिकारियों हेतु आयोजित करवाने हेतु दूरभाष पर अनुरोध भी प्राप्त हुए। विषय की गंभीरता एवं महत्ता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय पी0सी0 पंत जी ने key note address हेतु सहमति प्रदान की।

चिकित्साधिकारियों का feedback था कि National Law School, Bangalore; All India Institute of Medical Science, New Delhi; National Institute of Criminology and forensic Science, New Delhi जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के संकाय सदस्यों से अपनी शंकाओं

का समाधान प्राप्त होने से कार्य स्थल पर उनकी अनेक समस्याओं का समाधान हुआ। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शित POCSSO एवं बलात्कार जैसे मामलों में Sample Collection हेतु गृह मंत्रालय द्वारा विकसित Special Kit के सन्दर्भ में महानिदेशक महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को इस आशय का सुझाव प्रेषित किया गया कि समस्त थानों एवं चिकित्सालयों में इन किटों (Kits) की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से चिकित्साधिकारियों एवं जाँच अधिकारियों को अपने कार्य में सुगमता होगी।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम:— जनपदों में अपने सेवाकाल के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के सन्दर्भ में आ रही समस्याओं एवं शंकाओं के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के रजिस्ट्रारों तथा पंजीकरण प्रक्रिया में विशेष भूमिका निर्वहन करने वाले पदाधिकारियों जिनमें तहसीलदारों तथा राज्य में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत उपजिला मजिस्ट्रेटों को आमंत्रित किया गया। राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण तत्समय प्रवृत्त ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से हो रहे थे। जनपदों में अपने कार्यकाल के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा देखा गया था कि पोर्टल में भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का अद्यतन समावेश न होने के कारण रजिस्ट्रारों एवं आमजन को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की मान्यता का प्रश्न, संशोधन हेतु प्रक्रिया का अभाव, मृत्यु प्रमाण पत्र की दशा में पति-पत्नी का नाम न होना, दत्तक ग्रहण हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में व्यवस्था का अभाव आदि जैसे अनेक नीतिगत प्रश्न निहित थे। अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रारों के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को संचालित करने वाली एजेंसी आई.टी.डी. ए., भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग (राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु नोडल विभाग) उत्तराखण्ड स्थित जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक जो कि पदेन राज्य हेतु अपर मुख्य रजिस्ट्रार निर्धारित हैं को जोड़कर रजिस्ट्रारों की समस्याओं एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड को महानिदेशक महोदय द्वारा आवश्यक संस्तुतियों के साथ प्रेषित की गई।

उक्त संदर्भ में जनगणना कार्य निदेशालय ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक करते हुए अकादमी द्वारा की गई अधिकांश संस्तुतियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों एवं पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जिसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल में एकीकरण के सुझाव के संदर्भ में भी आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इस प्रकार अकादमी द्वारा नीतिगत सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। उक्त कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत सरकार, राज्य सरकार के नीति निर्माण से लेकर रजिस्ट्रार स्तर तक समस्त अधिकारी कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुए तथा अपनी बातें साझा की एवं व्यवस्था के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव Practioners द्वारा दिये गये। इस प्रकार नीति निर्माताओं एवं उपयोगकर्ताओं के साझा मंच का उद्देश्य व्यावहारिक समाधान प्राप्त करना रहा जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद स्तर पर अपर जिला रजिस्ट्रार की भूमिका निर्वहन के समय रजिस्ट्रारों की समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों की मुख्य भूमिका रही।

3. आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सूत्रपात:—

परिकल्पना— डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 2023 में राज्य बजट से चार जनपदों में तीन विशिष्ट विषयों पर एक दिवसीय Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संसाधनों में अधिकतम अधिकारियों तक प्रशिक्षण का लाभ पहुँचाने एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विषय में चर्चा करने के उद्देश्य से संचालित किये गये जिससे कि भविष्य में तदनुसार आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर अकादमी स्तर पर एवं Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें।

प्रशिक्षण पूर्व तैयारी— प्रशिक्षण हेतु बाल अधिकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विषय चयनित किये गये उक्त विषय अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राप्त फीडबैक एवं राज्य में सुशासन एवं विकास हेतु विषयों की महत्ता के आधार पर चयनित किये गये। माह जनवरी एवं फरवरी, 2023 में Outreach कार्यक्रमों के प्रथम चरण हेतु राज्य के चार

जनपदों— अल्मोड़ा, चम्पावत, हरिद्वार एवं देहरादून का चयन किया गया। जिस सन्दर्भ में आवश्यक तैयारी हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों से Online बैठक करते हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सहित, कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में चारों जनपदों के साथ Online Meeting की गयी जिसमें जनपदों से सहयोग की अपेक्षा की गयी। चारों प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अधोहस्ताक्षरी को कार्यक्रम निदेशक के रूप में नामित किया गया। अकादमी के सीमित मानव संसाधनों को देखते हुए कार्यक्रम निदेशक तथा विशेष कार्याधिकारी डॉ० मंजु ढौंडियाल द्वारा तीनों विषयों पर प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। मात्र सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित Case laws के सन्दर्भ में अतिथि वार्ताकार डॉ० एच० एस० राणा का सहयोग लिया गया।

विषयों का चयन एवं उद्देश्य:—

बाल अधिकारों पर संवेदीकरण कार्यक्रम — राज्य में बच्चों में नशे की बढ़ती लत, बाल अपराध, बाल मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को देखते हुए यह कार्यक्रम चिह्नित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक/संवेदीकृत करना जिससे कि उनका समेकित विकास हो सके एवं भविष्य में वे एक योग्य नागरिक रूप में अपना योगदान दे सकें, इस कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य रहा। शिक्षकों का चयन उन्हें बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने तथा उनके माध्यम से यह संदेश अभिभावकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर संवेदीकरण कार्यक्रम— विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों से औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत में यह बात निकलकर आयी कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम (POSH Act) से सम्बन्धित आन्तरिक समिति एवं स्थानीय समितियाँ विभिन्न कार्यालयों में गठित नहीं हैं और यदि गठित हैं भी तो मात्र कागज पर। सदस्यों को अपने कार्यदायित्वों की जानकारी नहीं है। उत्तराखण्ड के कार्यालयों को जेण्डर मित्रवत (Gender Friendly) बनाने के उद्देश्य से वृहद् स्तर पर उक्त

विषय पर संवेदीकरण की आवश्यकता महसूस की गई जिससे कि राज्य के कार्यस्थलों को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम – लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों हेतु अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उनके द्वारा पूछे जाने वाले अनेक प्रश्नों एवं समय-समय पर दूरभाष के माध्यम से आर0टी0आई0 मास्टर प्रशिक्षकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए यह महसूस किया गया कि अकादमी की जनपद स्तर पहुँच से अधिक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को लाभांविता किया जा सकता है। जिससे कि सुशासन हेतु शासकीय सूचनाओं में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ जन सामान्य तक सूचनाओं की पहुँच सुलभ बनाने तथा सूचना के अधिकार के अर्न्तगत अपीलों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

लक्षित प्रतिभागि— प्रथम कार्यक्रम अर्थात् बाल अधिकारों पर संवेदीकरण कार्यक्रम में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। द्वितीय कार्यक्रम अर्थात् महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर संवेदीकरण कार्यक्रम में समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। तृतीय कार्यक्रम अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था।

कार्यक्रमों से प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ— समस्त कार्यक्रमों में पंजीकरण सत्र के पश्चात् कार्यक्रम से प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ ली गयी। तीनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ निम्न प्रकार रही—

(क) बाल अधिकारों पर संवेदीकरण कार्यक्रम से अपेक्षाएँ— प्रतिभागियों द्वारा बाल अधिकारों के विषय में जानने, बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों को जानने एवं किस प्रकार से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का सदुपयोग किया जा सके इन विषयों

पर जानने की इच्छा प्रकट की। प्रतिभागियों द्वारा यह भी माना गया कि अभिभावकों एवं शिक्षकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण बच्चे बहुधा तनाव में रहते हैं। अतः उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए इस विषय पर भी प्रतिभागियों द्वारा बाल मस्तिष्क को समझने की तकनीकी के विषय में अवगत कराने का अनुरोध किया।

(ख) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोश) अधिनियम 2013 पर संवेदीकरण कार्यक्रम से अपेक्षायें— प्रतिभागियों द्वारा कार्यस्थलों को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी। साथ ही सन्दर्भित अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमों, अधिनियम अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष के दायित्वों, आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के सदस्यों के कार्य दायित्वों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया। कार्यस्थल पर पारस्परिक सौहार्द बनाये जाने हेतु उठाये जा सकने योग्य कदमों के विषय में भी प्रतिभागियों द्वारा ज्ञानवर्धन की अपेक्षा की गयी।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपेक्षायें— समस्त जनपदों के प्रतिभागियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 एवं उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के समस्त प्रावधानों को विस्तार से जानना चाहा। साथ ही व्यक्तिगत सूचना एवं तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना के सन्दर्भ में विशेष प्रकाश डालने का अनुरोध किया। कतिपय प्रतिभागियों द्वारा उनके कार्यालय में प्राप्त सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु उन पर विशेष चर्चा करने का अनुरोध किया गया।

उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं उच्चाधिकारी— कार्यक्रमों में श्री अनिल चन्द पुनेठा, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्री योगेश कुमार भट्ट, मा0 सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्री विवेक शर्मा, मा0 सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, जिलाधिकारी, चम्पावत, सुश्री झरना कमठान, मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, श्री प्रतीक जैन, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार, श्री अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा आदि की उपस्थिति कार्यक्रमों की सफलता का परिचायक है। उपरोक्त सभी महानुभावों द्वारा अकादमी की इस पहल की अत्यंत प्रशंसा की गई तथा भविष्य

में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने देहरादून में आयोजित सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के समस्त जनपदों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कराने का अकादमी से अनुरोध किया और सभी कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित होने की बात कही।

विशेष— उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सन्दर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिभागियों के भोजन एवं जलपान की व्यवस्था आवश्यक रूप से जनपदों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करवाई गई। जिस क्रम में अकादमी द्वारा उक्त व्यवस्था के सापेक्ष कुल रूपये 2,95,000.00 (दो लाख पित्तानबे हजार) का भुगतान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथियों को भेंट किए गये सोविनियर भी महिला स्वयं सहायता समूहों एवं राजकीय बाल किशोरी गृह अल्मोड़ा में निवासरत बालिकाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। इस प्रकार इन कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिकी की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भविष्य में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम— Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आवश्यकता आंकलन भी किया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से अधिकारियों को किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यह भी जानने को मिला। इन कार्यक्रमों की विस्तृत सूची तैयार की गई जिसके माध्यम से अकादमी को आगामी वर्षों में कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

अकादमी द्वारा प्रथम बार उपरोक्त तीनों विषयों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का परिणाम अत्यन्त ही उत्साहवर्धक रहा। इनमें कुल 957 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

4. जनगणना 2021 हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में चयन— जनगणना 2021 के लिए उत्तराखण्ड के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण करने हेतु जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड के दो अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण

प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया। प्रशिक्षण पश्चात् सम्पूर्ण टीम द्वारा अकादमी में ही राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

5. राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न समितियों में योगदान :-

(क) **National Capacity Building Framework Committee**— 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विकास प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है। पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं उनसे जुड़े हुए विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु 2014 में तैयार किए गए National Capacity Building Framework को वर्तमान दायित्वों एवं परिस्थितियों के अनूकूल बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के पूर्व महानिदेशक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, डा० डब्ल्यू० आर० रेड्डी की अध्यक्षता में गठित National Capacity Building Framework Review Committee के सदस्य के रूप में अधोहस्ताक्षरी को भी नामित किया गया। उक्त समिति द्वारा नियत समय में नए कलेवर में विकेंद्रित व्यवस्था हेतु सर्वथा उपयोगी National Capacity Building Framework 2022 तैयार कर पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दिया गया है जिसके आधार पर ही भविष्य में समस्त राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उक्त रिपोर्ट के प्रचालन (Operationalisation) हेतु गठित समिति में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा योगदान किया गया।

(ख) **Committee on preparation of Panchayat Development Index**- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत स्तर पर किये गये प्रयासों के मापन हेतु नीति आयोग एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित National Indicator Framework की तर्ज पर महत्वपूर्ण संकेतको का निर्माण, उनके अनुश्रवण की व्यवस्था तथा पंचायतों की रैंकिंग आदि के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती जयश्री रघुनन्दन की अध्यक्षता में Panchayat Development Index तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर गठित 8 सदस्यीय समिति के सदस्य के रूप में अधोहस्ताक्षरी को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया। उक्त

समिति द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, NITI आयोग आदि के साथ चर्चा एवं 1 वर्ष के अथक परिश्रम तथा महाराष्ट्र की कतिपय पंचायतों में फील्ड परीक्षण पश्चात् Panchayat Development Index तैयार किया गया। दिनांक 28.06.2023 को भारत सरकार द्वारा उक्त Index से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के समस्त पोर्टलों को एक प्लेटफार्म पर IPA के माध्यम से एकीकरण हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। यह सूचकांक (Index) पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों, उनके मूल्यांकन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित होगा।

6. पंचायतीराज संस्थाओं के सचिवों का प्रशिक्षण एवं लोकतंत्र का सुदृढीकरण— भारत ग्रामों में बसता है तथा 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस कारण विकास प्रशासन में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड ने राज्य के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान डा0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल से अनुरोध किया कि नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों हेतु एक माह के सेवा प्रवेश प्रशिक्षण तथा वरिष्ठ ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों हेतु 06 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायें, इन कार्यक्रमों हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में पदस्थापना के दौरान ही अकादमी को इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में सहयोग दिया गया था।

अकादमी में पदस्थापना के तत्काल पश्चात् इन कार्यक्रमों के संचालन के संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा मुझे मुख्य भूमिका प्रदान की गयी। विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ मेरे द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार अधिनियम, पंचायतीराज अधिनियम, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, आचरण नियमावली, वार्षिक चरित्र प्रविष्टि, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जाँच आदि विभिन्न विषयों में सत्र लिये गये। कुल 648 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग

किया गया। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार था कि **Front Line Functionaries** को प्रदेश की सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित अकादमी में 01 माह के सेवा प्रवेश तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इससे निश्चित रूप से कार्मिकों का मनोबल बढ़ा। अकादमी के अनुशासन का प्रभाव भी उनके जीवन पर पड़ा तथा अद्यतन नियमों की जानकारी से कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता भी देखने का मिली।

7. प्रकाशन एवं वार्तायें—

- डा0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के जर्नल JUAAN में जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के संदर्भ में आलेख प्रकाशित किया गया। उक्त आलेख के माध्यम से जन्म-मृत्यु पंजीयकों को पंजीयन के समय में होने वाली विभिन्न कठिनाईयों के समाधान प्रस्तुत किये गये हैं।
- कोविड काल में अकादमी के अन्य दायित्वों के साथ-साथ स्वतः पहल करते हुए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं ए.एन.एम. हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित **COVID-19 Book of Five Responce & Containment Measures** का हिन्दी अनुवाद किया गया। जिससे ग्राम स्तरीय कर्मचारियों तक सरलता से सन्देश प्रसारित किया जा सके।
- पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु दूरदर्शन उत्तराखण्ड के माध्यम से प्रसारित प्रशिक्षण श्रृंखला में क्षेत्र पंचायत सम्बन्धी श्रृंखला में विशिष्ट योगदान दिया गया।
- पंचायतीराज विभाग के यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण सत्र प्रसारित किये गये।

अकादमी के महानिदेशक श्री बी0पी0 पाण्डेय महोदय द्वारा प्रदान किये गये लोकतांत्रिक वातावरण का ही परिणाम था कि मुझे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से उनके समक्ष रखते हुए कार्यरूप में परिणत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही नीतिगत

मामलों में अकादमी अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त कर सकी तथा उनके व्यक्तित्व एवं मार्गदर्शन का ही परिणाम था कि आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आशा से अधिक सफलता मिली। श्री प्रकाश चन्द्र, संयुक्त निदेशक महोदय के प्रबन्धन कौशल एवं अकादमी टीम विशेष रूप से श्री वी०के० सिंह, श्री मनोज पाण्डे, डॉ० मन्जु ढौंडियाल एवं अन्य सहयोगियों के बौद्धिक सहयोग के बिना उपरोक्त परिणाम अपेक्षित नहीं थे।

हिमालयी राज्यों में जेण्डर आधारित मुद्दे एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन

मीता उपाध्याय, कन्सलटेन्ट, सुधा संस्था, अल्मोड़ा

हिमालयी राज्यों में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनिश्चित जलवायु परिवर्तन एवं कठोर जीवन-यापन सदैव ही चिंता का विषय रहा है। इन पर्वतीय राज्यों के विकास का मॉडल कैसा हो इस प्रश्न पर गहन मंथन करने के लिए इन हिमालयी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों पर ध्यान देना वांछित होगा। हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के लिए यहाँ पवित्र नदियों का उद्गम, वनों की बहुतायत, वनस्पतियों की विविधता है, किन्तु प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के होते हुए भी विकास की गति अपेक्षित नहीं रही। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में यहाँ के निवासी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। हिमालय राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील है। उत्तराखण्ड राज्य में 2013 की आपदा ने सम्पूर्ण जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था। भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने से बाढ़ की विभीषिका, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ विकास के क्रम को बाधित करती रही हैं। राज्य के 85% जिले प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। अतः एक प्रभावी आपदा प्रबंधन क्रियान्वयन नीति की आवश्यकता है जो जेण्डर दृष्टिकोण से परीक्षित हो।

हिमालयी राज्यों में निवासियों की पहुँच विकास के लाभों तक बहुत कम रही है? यदि महिलाओं की स्थिति का आकलन करें तो कहा जा सकता है कि वे विकास के लाभ लेने में पीछे छूट जाती हैं, किन्तु आपदा जन्य संकट एवं कष्टों को सबसे अधिक झेलती हैं इन पर्वतीय राज्यों में सामाजिक संरचना, रीतिरिवाज, संस्कृति एवं सोच आज भी पितृसत्तात्मक हैं जहाँ महिलाओं की भूमिकाएँ, घरेलू कार्यों, पशु-पालन, चारा ईंधन का प्रबन्धन तक सीमित है। इन्हीं

जेण्डर आधारित भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं के कारण आज भी महिलाएँ विकास के लाभ कम ले पाती हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की भूमिका स्वाधीनता आंदोलन हो या पर्यावरण संरक्षण, मद्य निषेध जैसे मुद्दों पर अत्यंत मुखर रही है। चिपकों आंदोलन में गौरा देवी की भूमिका आज भी पथ प्रशस्त करती दिखाई देती है। जल, जंगल, जमीन का कैसे आदर्श प्रयोग एवं संरक्षण हो यहाँ की महिलाओं से अधिक जानकार कोई नहीं हो सकता। मौसम की भविष्यवाणी के लिए उनका पारंपरिक ज्ञान एवं अनुभव किसी भू वैज्ञानिक से कमतर नहीं किन्तु जेण्डर आधारित आपदा प्रबन्धन में इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।

यह भी प्राकृतिक सत्य है कि महिला एवं पुरुष की शारीरिक संरचनाएँ भिन्न हैं और इस दृष्टि से उनकी शारीरिक आवश्यकताएँ भी भिन्न हैं। आपदा प्रबंधन में उसके सभी चरणों में चाहें वह पूर्ण तैयारी हो या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य, गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं हेतु आकस्मिक उपचार की व्यवस्था का होना आवश्यक हैं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का प्रबन्धन भी अपरिहार्य है। बालिकाओं एवं महिलाओं को मासिक धर्म के कारण पृथक शौचालय एवं सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था जैसे छोटी-छोटी सावधानियों से महिला स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा सकते हैं। राहत शिविरों में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने से उन्हें मूत्र नली में संक्रमण तथा सर्वाकइल कैंसर जैसे गंभीर रोगों की चपेट में आने से रोका जा सकता है।

आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में यदि हम असहायता (Vulnerability) की बात करें तो जेण्डर असमानता के कारण महिलाएँ अधिक असहाय हो जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में पिछड़ने के कारण उनमें आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। जिस कारण आपातकाल में वे आवश्यक बचाव के उपाय नहीं सोच पाती। यद्यपि मौसम की भविष्यवाणी, फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु एवं आपदा से बचाव हेतु अनुभव जन्य ज्ञान उनके पास है। आवश्यकता है कि जेण्डर संवेदनशील आपदा प्रबन्धन में उनके इस पारम्परिक ज्ञान का लाभ हम लें तथा उन्हें आपदा प्रबन्धन के सक्रिय भागीदार के रूप में विकसित करें। महिलाओं की दायम स्थिति के कारण प्रायः आपदाकाल में वे शारीरिक शोषण एवं ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं से भी जूझती है। बालिकाएँ एवं महिलाएँ आपदाकाल में लापता हुई हैं किन्तु उनकी ठीक-ठीक

संख्या बताना संभव नहीं हो सका है क्योंकि आज भी हमारे पास Sex Disaggregated Data तथा Gender Based Data Collection की समुचित व्यवस्था नहीं है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण की सक्षम प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। आज पुरुष, महिला के अतिरिक्त ट्रांस जेण्डर के अधिकारों की भी माँग उठ रही है और आपदा से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को समावेश आपदा प्रबन्धन तकनीकों में होना ही चाहिए। आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों में यदि महिलाओं के ज्ञान और अनुभवों का सहयोग लें तो यह प्रभावी प्रबन्धन की ओर एक कदम होगा। आपदा प्रबन्धन के प्रथम चरण जिसमें खतरों की पहचान है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं का अनुभव लाभदायी होगा। वनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं जल-स्रोतों का संरक्षण करने में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। अतः प्राकृतिक आपदा के जोखिमों को कम करने में महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण के सक्रिय एजेंट के रूप में चिन्हित की जा सकती हैं। राहत एवं बचाव ढालों में भी महिलाओं को प्रशिक्षित कर बचाव कार्यों को अधिक स्नेही एवं संवेदनशील किया जा सकता है। आवश्यक सूचना तंत्र विकसित करने में भी महिलाओं की क्षमता कहीं कमतर नहीं दिखाई पड़ती। आज हिमालयी क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु विकास हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है जो कि जेण्डर संवेदनशील हो, प्रकृतिजन्य आपदाएँ हो या मानवजनित, वन्य जीव एवं मानव संघर्ष हो या पर्यावरण प्रदूषण महिलाएँ जहाँ असहायता की श्रेणी में हों किन्तु उनके अनुभव एवं कठोर श्रम के कारण उन्हें इन आपातकालों में एक सशक्त संसाधन के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

ⁱ Tripathi, R. (2017). Good governance: Origin, importance and development in India. *International Journal of Development Research*, 7(11), 16968-16970.

ⁱⁱ Debnath, A., & WB, P. B. D. B. (2019). The concept of good governance in Kautilya's Arthashastra. *IJRAR-International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 6(2), 745-750.

ⁱⁱⁱ World Bank. (1992a). *Governance and development*. The World Bank.

- ^{iv} Dalal, R. S. (2011a). The Conceptual Dimensions of Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 57(1), 91–99. <https://doi.org/10.1177/0019556120110108>
- ^v World Bank. (1994a). *Governance: the World Bank's experience*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2>
- ^{vi} Kashyap, S. C. (1994). *Our constitution: An introduction to India's constitution and constitutional law*. NBT India.
- ^{vii} Dawes, S. S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance. *Public Administration Review*, 68, S86–S102. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x>
- ^{viii} Grigalashvili, N. V. (2022). CONCEPTUAL DIMENSIONS OF ELECTRONIC GOVERNMENT AND ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE DOMAIN OF DIGITAL DEMOCRACY. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 1(37). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032022/7753
- ^{ix} Sapru, R., & Sapru, Y. (2014a). Good Governance Through E-Governance with Special Reference to India. *Indian Journal of Public Administration*, 60(2), 313–331. <https://doi.org/10.1177/0019556120140208>
- ^x *National e-Governance Plan | Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India*. (n.d.). <https://www.meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan>
- ^{xi} Sapru, R., & Sapru, Y. (2014b). Good Governance Through E-Governance with Special Reference to India. *Indian Journal of Public Administration*, 60(2), 313–331. <https://doi.org/10.1177/0019556120140208>
- ^{xii} Kemp, S. (2023). Digital 2023: India — DataReportal – Global Digital Insights. *DataReportal – Global Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-india>
- ^{xiii} World Bank. (1994b). *Governance: the World Bank's experience*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2>
- ^{xiv} *About us| National Portal of India*. (n.d.). <https://www.india.gov.in/about-portal>

- ^{xv} Garg, R. (2022). A Technological Approach to Address Deficiencies in UID (Aadhaar). In *3rd International Conference on Big Data, Blockchain and Security, Copenhagen Denmark*. (Vol. 10).
- ^{xvi} Ahmad, S. (2022). Direct Benefit Transfer: The Great Technological Move of India. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 1(1), 37-41. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i1.4>
- ^{xvii} Director, D. M. (n.d.). *Homepage / (DBT) Direct Benefit Transfer*. DBT | Direct Benefit Transfer. <https://dbtbharat.gov.in/>
- ^{xviii} PTI. (2023, June 29). 6 years of GST: Rs 1.5 trillion monthly tax revenues becomes “new normal”, focus on curbing tax evasion. *The Telegraph Online*. <https://www.telegraphindia.com/business/6-years-of-gst-rs-1-5-trillion-monthly-tax-revenues-becomes-new-normal-focus-on-curbing-tax-evasion/cid/1948558>
- ^{xix} PIB Delhi. (2023, February 8). *Digital transactions in India*. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897272>
- ^{xx} World Bank. (1992b). *Governance and development*. The World Bank.
- ^{xxi} PMINDIA. (2015, March 25). *PM launches PRAGATI: A multi-purpose, multi-modal platform for Pro-Active governance and timely implementation*. https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-launches-pragati-a-multi-purpose-multi-modal-platform-for-pro-active-governance-and-timely-implementation/
- ^{xxii} Singh, G., Pathak, R. D., Naz, R., & Belwal, R. (2010). E-governance for improved public sector service delivery in India, Ethiopia and Fiji. *International Journal of Public Sector Management*, 23(3), 254–275. <https://doi.org/10.1108/09513551011032473>
- ^{xxiii} Dalal, R. S. (2011b). The Conceptual Dimensions of Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 57(1), 91–99. <https://doi.org/10.1177/0019556120110108>
- ^{xxiv} PTI. (2021, November 18). Over 1.59 lakh RTI applications filed online in 8 years, 11,376 by women: Personnel ministry. *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-1-59-lakh-rti-applications-filed-online-in-8-years-11376-by-women-personnel-ministry/articleshow/87774104.cms>

- ^{xxv} hindustantimes.com, Edited by Nandini. (2020, May 17). PM eVidya Programme for digital education in India: Everything you need to know. *Hindustan Times*. <https://www.hindustantimes.com/education/pm-evidya-programme-for-digital-education-in-india-everything-you-need-to-know/story-15SmSAyTEckgx6gcYIJNYO.html>
- ^{xxvi} *PM e-Vidya - SWAYAM Portal*. (n.d.). <https://pmevidya.education.gov.in/swayam-portal.html>
- ^{xxvii} Singh, M., Adebayo, S. B., Saini, M., & Singh, J. (2021). Indian government E-learning initiatives in response to COVID-19 crisis: A case study on online learning in Indian higher education system. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7569–7607. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10585-1>
- ^{xxviii} Robinson, N. (2009). Expanding Judiciaries: India and the Rise of the Good Governance Court. *Washington University Global Studies Law Review*, 8(1), 1–69. https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=law_globalstudies
- ^{xxix} *E-Courts Mission Mode Project | Official Website of e-Committee, Supreme Court of India | India*. (n.d.). <https://ecommitteesci.gov.in/project/brief-overview-of-e-courts-project/>
- ^{xxx} Anders, G. (2005). Good governance as technology: towards an ethnography of the Bretton Woods institutions. *The aid effect: Giving and governing in international development*, 37-60. <https://handoutset.com/wp-content/uploads/2022/06/THE-AID-EFFECT.pdf#page=42>
- ^{xxxi} United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022, September 28). *Un E-Government Survey 2022*. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
- ^{xxxii} The Indian Express Private Limited. (2023). India’s healthtech market projected to reach US\$25bn by 2025: Report. *Express Healthcare*. <https://www.expresshealthcare.in/news/indias-healthtech-market-projected-to-reach-us25bn-by-2025-report/439720/>



**Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration,
Nainital, Uttarakhand - 263001
Ardwell Camp, Mallital, Nainital
www.uaoa.gov.in**